Supported by :

नीति आयोग
National Institution for Transforming India

जल प्रहरी
जल वायु अनुकूलन प्रकल्प
JAL PRAHARI
Mission Climate Adaptation

sarkaritel.com
we connect...

जल प्रहरी
2024

श्री लक्ष्मण सिंह
पद्म श्री सम्मान से अलंकृत
जल प्रहरी (2019)

श्री उमा शंकर पांडे
पद्म श्री सम्मान से अलंकृत
जल प्रहरी (2019)

स्मारिका / Souvenir

Initiative supportted by: Ministry of Jal Shakti, Goverment of India / जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित

Country Partner | State Partner | Knowledge Partners | Magazine Partner | Radio Partner | Print Partner

National Institute of Urban Affairs

CEEW

BIG FM

अमर उजाला

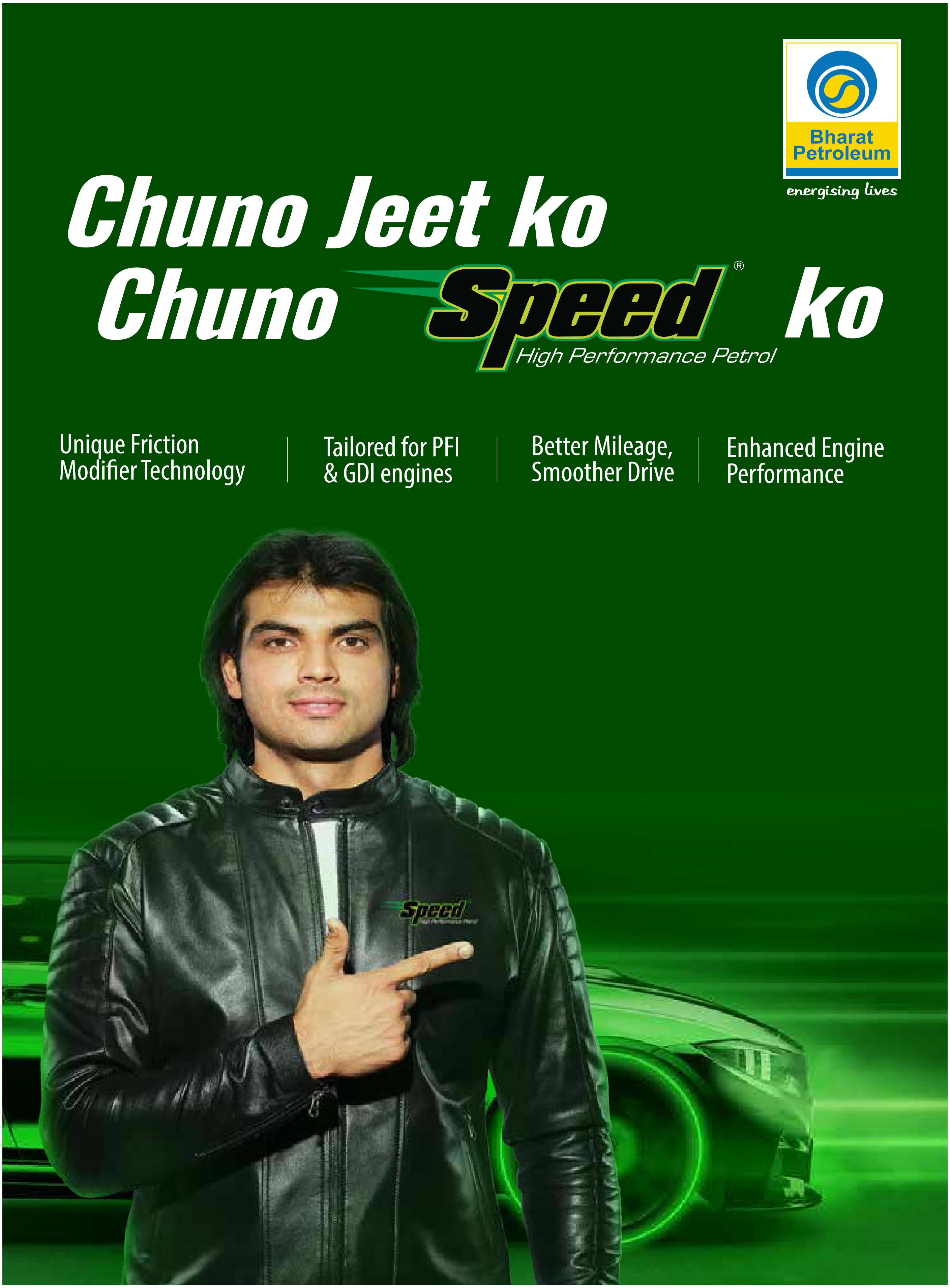
Bharat Petroleum
energising lives
Chuno Jeet ko
Chuno Speed® ko
High Performance Petrol
Unique Friction Modifier Technology
Tailored for PFI & GDI engines
Better Mileage, Smoother Drive
Enhanced Engine Performance

CONTENT

Sl. N	Name	Page No.
1.	Our Sponsor : BPCL Ad	0
1.	Concept note by Anil Singh	1
2.	Editor's Article from Ameya Sathaye	2
3.	Glimples from Jal Prahari Samman Samaroh	3
4	Article from National Water Mission, Ministry of Jal Shakti	21
5.	Article from Jal Purush Shri Rajendra Singh, Waterman of India	22
6.	Article from German GIZ	24
7.	Article from Department of Rural Development, Govt. of Uttar Pradesh	26
7.	Our Sponsor : NTPC Bongaigoan	28
8.	Our Sponsor : Powergrid Ad	29
9.	Article from National Institute of Urban Affairs	30
10.	Distinguished Jury Panel of Jal Prahari Samman 2024	31
	PROFILES OF JAL PRAHARI'S	
1	Shri Ajay Namdev	32
2	Shri Ajit Dyandev Pawar	34
3	Amity International Pushp Vihar, New Delhi	36
4	Smt. Arunima Mishra	38
5	Shri Ashutosh Dwivedi, IAS	40
6	Shri Birbal Ram Bishnoi	42
7	Shri Chinmay Udgirkar	44
8	Shri Chotelal Meena	46
9	Shri Dinesh Vishnoi	48
10	Shri Gaurang Rathi, IAS	50
11	Shri Gauranga Das	52
12	Shri Indra Vikram Singh, IAS	54
13	Shri Kailash Karthik N. IAS	56
14	Smt. Kanupriya Harish	58
15	Shri Manish Verma, IAS	60
16	Shri Manoj Kumar Sati	62
17	Shri. Meda Gurudutt Prasad	64
18	Shri Nand Kishore Verma	66
19	Shri Nandkishore Prajapati	68
20	Shri Nandlal Singh	70
21	Shri Nizamudeen. A, IAS	72
22	Shri Pradeep Mahapatra	74
23	Shri Rahul Sisodia	76
24	Shri Ranveer Singh Gurjar	78
25	Shri Sandeep Kaushik	80
26	Shri Saroj Kumar	82
27	Shri Savji Dholakia	84
28	Shri Sindhav Hasmukhbhai Ranchhodbhai	86
29	Shri Somnath Mali	88
30	Shri Stanzin Chosphel	90
31	Dr. Subash Dhakal	92
32	Shri Suresh Chandra Rakwar	94
33	Shri Ved Prakash Maurya	96
34	Shri Vikrant Tongad	98
35	Shri Vipul Pandya	100
36	Shri Vishal Ashok Sonkul	102
37	Dr. Zinabhai P. Patel	104
38	Management Team : Bal Bharti Public School, Sector-29, Noida Ad	106
39	Our Sponsor : HUDCO Ad	107
40	Our Sponsor : Tata Motors Limited Ad	108

प्रस्तावना

जल प्रहरी रहें लालफीताशाही से सुरक्षित ताकि कर सके सुनिश्चित जल संचय, जन भागीदारी

अनिल सिंह सागर
वरिष्ठ पत्रकार,
पजाब केसरी ग्रुप
नवोदय टाइम्स

जल, नदियां किसी सरहद से बेशक न बंधे हुए हों लेकिन नियत के खोट से बचाव के लिए, प्रबंधन में सुविधा रहे, इसके लिए नीति जरूरी है। इसके लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव करने वाले एक मसौदा मॉडल विधेयक सभी राज्यों को भेज दिया गया है। यह प्राधिकरण गांवों से लेकर शहरों तक जल सुरक्षा योजनाएं विकसित करने, भूजल प्रबंधन और डूब क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत जल सुरक्षा हासिल करने के लिए सरकार ने राज्य स्तर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआरएम) के गठन का प्रस्ताव दिया है, जो विभिन्न जल-संबंधित विभागों और एजेंसियों के प्रयासों का समन्वय और एकीकरण करेगा।

राज्यों के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली आईडब्ल्यूआरएम परिषद की समग्र देखरेख में इस राज्य आईडब्ल्यूआरएम प्राधिकरण को जल क्षेत्र के विकास की दिशा निर्धारित करने के लिए विभिन्न नियामक शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह गांवों और शहरों से लेकर जिलों और राज्य स्तर तक जल सुरक्षा योजनाओं, भूजल प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन और नदी संरक्षण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

राष्ट्रीय नीति का नया मसौदा इस दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण कदम है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल क्षेत्र में नवाचार को गति देने की राष्ट्रीय रणनीति भी बनाई है।

इस नीति का उद्देश्य जल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए नवाचार को प्रेरक शक्ति बनाना है, ताकि सभी के लिए जल सुरक्षा हासिल की जा सके। इसका मिशन जल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिहाज से खुले सहयोग के अवसर और सक्षम मंच बनाना है।

जल के औद्योगिक उपयोग में बेहतर दक्षता हासिल करने की आवश्यकता है। देश के औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 40 अरब घनमीटर जल का उपयोग किया जाता है। भारतीय उद्योगों में जल उपयोग दक्षता विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। जल उपयोग दक्षता में सुधार की बहुत गुंजाइश है।

लेकिन इन सबसे पहले और जरूरी है कि ऐसे लोगों को इस नीति का हिस्सा बनाया जाए जो जल संचय, जन भागीदारी को लेकर चलने का मानस तैयार करते हैं। ऐसे लोग जो खुद का जीवन खपा कर जल प्रहरी बनकर उन लोगों से पानी की रक्षा करते हैं जो जरूरतमंद को पानी मुहैया कराने के लिए भारी कीमत वसूलने के कुचक्र रचते हैं। इसलिए नीति में जल संरक्षण के लिए काम करने वाले शामिल किए जाएं, उनके प्रयास, प्रयोग काम भी लालफीताशाही से प्रभावित न हों। जल प्रहरी जनजन के लिए, जल संचय कर सकें जन जन के लिए जल स्रोतों की रक्षा, निर्माण कर सकें यह प्रबन्ध भी होने चाहिए ताकि कानून के चाबुक से इनके मन में पीड़ा न हो, न ही इनके काम प्रभावित हों। समाजिक भागीदारी से जल भागीदारी जन भागीदारी के भगीरथ सदैव सुरक्षित रहें अन्यथा जल सुरक्षा का चक्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा।

अनिल सिंह सागर
संयोजक जल प्रहरी

संपादकीय

जल संरक्षण के लिए समर्पित हैं जल प्रहरी, पूरी दुनिया में जल सुरक्षा के संदेश को करेंगे मजबूत

अमेय साठ्ये

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं मुख्य संपादक

sarkaritel.com
we connect ...

Diplomacy
india.com

जल संरक्षण आज सबसे महत्त्वपूर्ण विषय है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हमने जब से यह पहल की है, तब से यह एक अद्भुत यात्रा रही है। जून 2019 की गर्मियों में मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया सहित विभिन्न धाराओं के लोगों से जल संरक्षण को बढ़ावा देने का आग्रह किया। एक जिम्मेदार मीडिया संगठन के रूप में हमने इसे एक मिशन के रूप में लेने का फैसला किया और देश के कोने-कोने में कई महीने हजारों मील की यात्रा की। दिसंबर 2019 के महीने में हमें भारत भर से 70 जल संरक्षक मिले और जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से जल प्रहरी सम्मान समारोह का पहला संस्करण आयोजित किया, जिसमें उन संगठनों, व्यक्तियों को मान्यता प्रदान की गई, जिन्होंने हमारे देश को जल संरक्षण के मुद्दों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील बनाने और देश को जल आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद की है। तब से हम 200 से अधिक जल प्रहरियों को सम्मानित कर चुके हैं।

राष्ट्रीय जल मिशन ने जल संरक्षण और "एक पेड़ के नाम" को बढ़ावा देने के लिए सरकारी टेल एवं जल प्रहरी, जलवायु उन्मूलन प्रकल्प के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मीडिया संगठन सरकारी टेल के रूप में सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव सरकारी एजेंसियों द्वारा जल निकायों को पुनर्जीवित करने, नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए हमारे जल प्रहरी को मान्यता और संलग्न करना रहा है। पिछले 24 वर्षों से हमारा मिशन वी कनेक्ट रहा है। हमारे जल प्रहरी लक्ष्मण सिंह "लापोडिया" और उमा शंकर पांडे को इस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान "पद्म श्री" से सम्मानित किया गया जो हमारे साथ-साथ सभी जल प्रहरियों के लिए गर्व का विषय है।

पानी की कमी एक बढ़ता हुआ संकट है जो दुनिया के कई हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्तमान में वैश्विक आबादी के 40 प्रतिशत से अधिक लोग पानी की कमी का अनुभव करते हैं, और आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। मामले को बदतर बनाने के लिए, दुनिया की जल आपूर्ति का 5 प्रतिशत से भी कम मीठा पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त और सुलभ है। पानी तक सतत पहुँच हमारे समय के परिभाषित मुद्दों में से एक होगी और यह एक ऐसी समस्या है, जिससे हमें अभी निपटना होगा। चाहे नीति, प्रौद्योगिकी या व्यक्तिगत कार्रवाइयों में नवाचारों के माध्यम से, जल की बर्बादी को कम करना और पानी का अधिक कुशलता से उपयोग करना दुनिया भर में प्राथमिकता बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का अनुमान है कि 2 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित पेयजल तक पहुँच नहीं है और 3.6 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुँच नहीं है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्से पहले से ही गंभीर जल तनाव का सामना कर रहे हैं, जहाँ आबादी संसाधनों की उपलब्ध ता से कहीं अधिक है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर हम अपने उपभोग और बर्बादी को रोकने में विफल रहे तो 2025 तक आधी वैश्विक आबादी को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। पिछले चार संस्करण में यह अनुभव मिला कि जो भी जल प्रहरी काम कर रहे हैं वह शब्दों, सरकारी लक्ष्यों, भाषा, योजनाओं से परे बूंद बूंद की रक्षा में जुटे हैं; यही ऐसे पहलू हैं, जिनको लेकर हम पूरी दुनिया में जल सुरक्षा, संवर्धन करने वाले जल प्रहरियों के मंच के तौर पर जल प्रहरी तैयार करेंगे जो जल की सुरक्षा, प्रबंधन पर समर्पित होकर काम कर रहे हैं।

ACTIVITIES RELATED TO WATER CONSERVATION AND PREPERATIONS FOR JAL PRAHARI 2024

श्री पंकज कुमार, आईएएस, पूर्व सचिव, जलशक्ति मंत्रालय

प्रो. रमेश चंद, सदस्य नीति आयोग

जल प्रहरी श्री रविन्द्र सिंघल, आईपीएस, पुलिस आयुक्त, नागपुर पुलिस

एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में बाल भारती पब्लिक स्कूल, सेक्टर-29, नौएडा में वृक्षा रोपण करते हुए श्री मनीष वर्मा, जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर

ACTIVITIES RELATED TO WATER CONSERVATION AND PREPERATIONS FOR JAL PRAHARI 2024

श्री सी.आर. पाटिल, जल शक्ति मंत्री को जल प्रहरी पुस्तिका भेंट करते हुए

श्री राज भूषण चौधरी, जल शक्ति राज्य मंत्री को जल प्रहरी पुस्तिका भेंट करते हुए

ACTIVITIES RELATED TO WATER CONSERVATION AND PREPERATIONS FOR JAL PRAHARI 2024

नागपुर में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में नए प्रशिक्षु युवकों के साथ 'एक पेड़ माँ के नाम'

सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉ. सुरेश गोसावी के साथ 'एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण

ACTIVITIES RELATED TO WATER CONSERVATION AND PREPERATIONS FOR JAL PRAHARI 2024

श्रीमती नुपुर गोयल, आईएएस मुख्य विकास अधिकारी, जिला मेरठ और स्कूल के साथ बच्चों के साथ 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान

श्री सुमित महाजन, आईएएस मुख्य विकास अधिकारी, जिला सहारनपुर जेवी जैन इंटरकॉलेज में 'एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण

जल प्रहरी सम्मान समारोह 2022 की झलकियाँ

Glimpses from Jal Prahari Samman Samaroh 2022

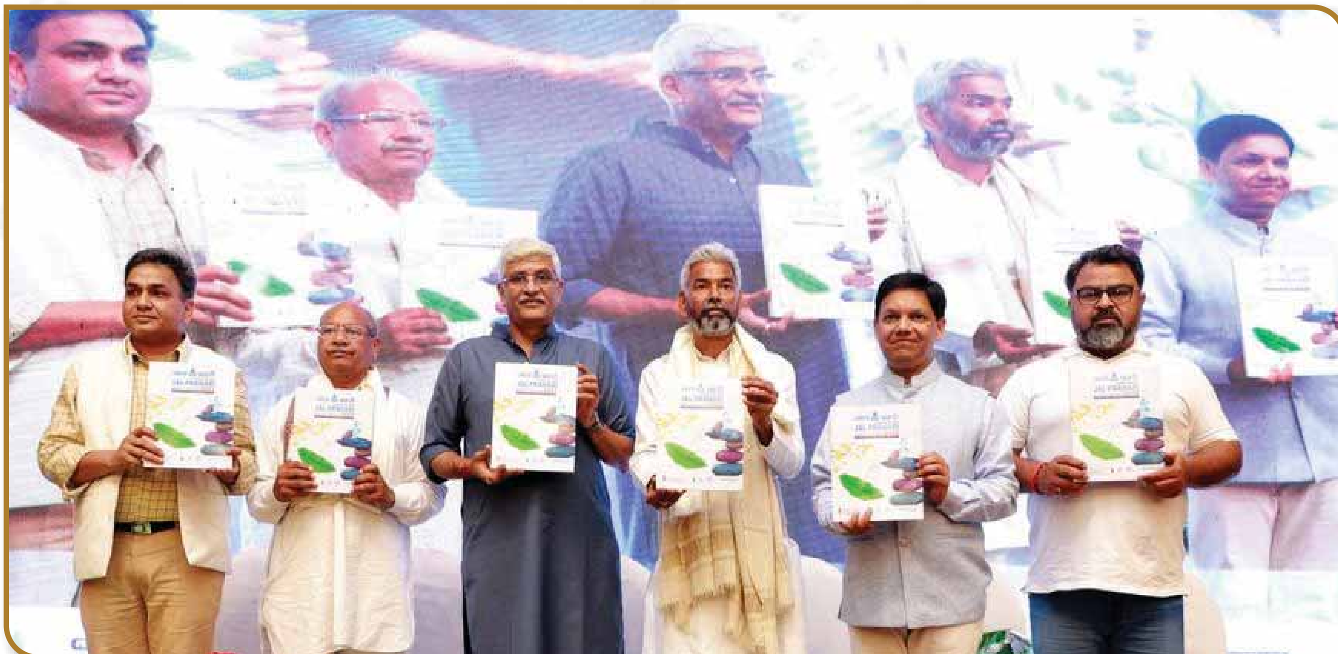

Glimpses from Jal Prahari Samman Samaroh 2022

जल प्रहरी सम्मान समारोह 2022 की झलकियाँ

Glimpses from Jal Prahari Samman Samaroh 2022

जल प्रहरी सम्मान समारोह 2021 की झलकियाँ

Glimpses from Jal Prahari Samman Samaroh 2021

जल प्रहरी सम्मान समारोह 2021 की झलकियाँ

Glimpses from Jal Prahari Samman Samaroh 2019

जल प्रहरी सम्मान समारोह 2019 की झलकियां

Glimpses from Jal Prahari Samman Samaroh 2019

जल संचय जन भागीदारी : जल शक्ति अभियान का सशक्त मॉडल

National Water Mission
Ministry of Jal Shakti

प्रारंभ

'जल संचय जन भागीदारी' पहल की शुरुआत दिनांक 6 सितंबर, 2024 को गुजरात के सूरत शहर से की गई। यह पहल जल संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है । श्रेष्ठ, भारत के हर नागरिक, उद्योग और सामुदायिक संस्थाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास है, जिससे जल सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सामूहिक भागीदारी से जल की हर बूंद को संरक्षित करना, भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना तथा जल की गुणवत्ता को सुधारना हैं।

गुजरात मॉडल की सफलता : गुजरात ने सामुदायिक भागीदारी और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंडिंग के माध्यम से जल संरक्षण का एक आदर्श मॉडल पेश किया है। राज्य में 10,000 से अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण हो चुका है, जो अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन रही है।

प्रमुख विशेषताएँ

सामुदायिक स्वामित्व और सहभागिता : श्रेष्ठ पहल की बुनियाद स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी है। यह नागरिकों को अपने जल स्रोतों के प्रति जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गांवों और शहरों में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, स्थानीय जल समस्याओं का समाधान और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

किफायती और प्रभावी संरचनाएँ : श्रेष्ठ पहल के तहत विभिन्न भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जैसे चेक डैम, फार्म पॉन्ड्स, रिचार्ज पिट्स और छत वर्षा जल संचयन प्रणाली। इन संरचनाओं की लागत ₹15,000 से लेकर ₹1.5 लाख तक है, जो इसे हर वर्ग के लिए किफायती बनाती हैं।

वित्तपोषण के स्रोत और CSR का उपयोग : श्रेष्ठ पहल के वित्त पोषण में सरकारी योजनाएँ जैसे मनरेगा, पीएमकेएसवाई और अमृत, साथ ही बैं और डोनर फंडिंग शामिल हैं। उद्योग, स्वयंसेवी संगठन और व्यक्तिगत डोनर्स सामूहिक रूप से जल संरक्षण में योगदान दे रहे हैं।

लक्ष्य

- एक मिलियन पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण।
- गुजरात मॉडल का विस्तार, जिसमें सामुदायिक भागीदारी और निजी अंशदान शामिल हैं।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संकट के प्रभाव को कम करना।

अब तक की उपलब्धियाँ

- 2.5 लाख पुनर्भरण संरचनाओं की शुरुआत; 2 लाख पूर्ण।
- सभी राज्यों और हितधारकों के साथ विस्तृत समन्वय।
- **जेएसए :** सीटीआर पोर्टल के माध्यम से डेटा मॉनिटरिंग।

अभियान का महत्व

यह पहल सामुदायिक जुड़ाव और सरकारी समर्थन से जल सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता देने का प्रयास है। इसका उद्देश्य भारत को जल संकट मुक्त बनाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को संरक्षित करना है।

आपका योगदान महत्वपूर्ण :

- अपने घर, स्कूल या कार्यालय में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करें।
- अपने क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण में भाग लें।
- जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाएँ और दूसरों को भी जोड़ें।

हिंसा, तस्करी, लूटपाट, सुख, समृद्धि शांति व प्रेम का कोलम्बिया में प्रत्यक्ष दर्शन

जलपुरुष राजेन्द्र सिंह
दि वॉटरमैन ऑफ इंडिया

इनका सिद्धांत है कि, कोई भी व्यक्ति हथियार नहीं रखेगा, हिंसक युद्ध का समर्थन नहीं करेगा, हिंसक हमले का साथ नहीं देगा, हिंसक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा तथा कोई भी गोरिल्ला लोगों को किसी भी तरह से खाने-पीने, रहने आदि का सहयोग नहीं करेगा। जिन-जिन लोगों ने इस सिद्धांत को माना, उन सभी लोगों को इस शांति समुदाय में शामिल किया गया है और उनका विधि वत पंजीकरण होता है।

कोलम्बिया, दक्षिण अमेरिका की यात्रा शुरू होने से पहले मैंने अपने बहुत सारे मित्रों से कोलम्बिया की दर्दनाक कहानी सुनी थी। इसलिए यात्रा से पहले मन में इसे गहराई से जानने की उत्सुकता और थोड़ा-सा अनमनापन था। 29 अक्टूबर 2024 को देर रात दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा शुरू हुई और दो दिन की हवाई यात्रा के बाद बगोटा एयरपोर्ट होते हुए 1 नवम्बर 2024 को मेडेलिन एयरपोर्ट पहुँचा। यहाँ 'विश्व तीर्थ बचाओ जुड़ाव' के साथियों ने यात्रा का स्वागत किया। यहाँ आसमान बिल्कुल साफ देखकर मन आनन्दित हुआ। 2 नवम्बर को मेडेलिन से यात्रा सेनहोज सीतो, अपार्टाडो कोलम्बिया, दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में पहुँची। यहाँ पर जहां मैं रुका हुआ था, उस समुदाय का नाम शांति समुदाय (कौमूनी दाद दे पॉज) है। यह शांति समुदाय 27 वर्ष पुराना है, जिसकी स्थापना 23 मार्च 1997 को हिंसा से बचाने और प्रकृति के रक्षण-संरक्षण के लिए हुई थी। यह 27 छोटे-छोटे गाँवों और 27 समुदायों के साथ इस अपार्टाडो क्षेत्र में बसा है। यह पूरा क्षेत्र तीन पहाड़ी शृंखलाओं के बीच में स्थित है। समुदाय के इन 27 गाँवों में एक जैसे ही सिद्धांत की पालना होती है। इनका सिद्धांत है कि, कोई भी व्यक्ति हथियार नहीं रखेगा, हिंसक युद्ध का समर्थन नहीं करेगा, हिंसक हमले का साथ नहीं देगा, हिंसक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा तथा कोई भी गोरिल्ला लोगों को किसी भी तरह से खाने-पीने, रहने आदि का सहयोग नहीं करेगा। जिन-जिन लोगों ने इस सिद्धांत को माना, उन सभी लोगों को इस शांति समुदाय में शामिल किया गया है और उनका विधिवत पंजीकरण होता है।

इस समुदाय के साथ दो-तीन दिन शांति, अहिंसा, सत्य और प्रेम का व्यवहार देखकर, जानकर और सुनकर ऐसा लगा कि, हमने जैसा पहले कोलम्बिया के बारे में सुना है, वह सब गलत था। लेकिन चौथे दिन ही शांति समुदाय (कौमूनी दाद दे पॉज) के 19 वर्षीय नौजवान 'ऐरियन' की किसी ने चाकूओं से टुकड़े-टुकड़े करके हत्या कर दी। इसकी जानकारी हमें रात को मिली और फिर उस रात नींद ही नहीं आयी; क्योंकि जिस घर में हम ठहरे थे, उसी के बराबर वाले घर का ही वह 19 वर्षीय युवा था। इसके कारणों को और अधिक गहराई से जानने की कोशिश की तो पता चला कि, यह शांति समुदाय ऐसे स्थान पर बसा हुआ है, जहां के रास्ते से ही अवैध व्यापार कोकीन-ड्रग की तस्करी, हथियारों का लेनदेन, मानव तस्करी आदि सभी तरह का अवैध व्यापार होता है। यह दक्षिण अमेरिका में पनामा के जंगल से जाने वाले अवैध लोगों को भी रास्ता देता है। पनामा वह देश है, जिससे होकर दक्षिण अमेरिका से उत्तर अमेरिका के जंगल में पैदल चलकर पहुँचा जा सकता है। यहाँ के लोगों ने बताया कि, इस क्षेत्र का नियंत्रण जिस सेना के पास होता था, वह साल भर में इतना ज्यादा पैसा (डॉलर) कमा लेता था कि, जिसको गिना नहीं; तौला जाता था। यहाँ अवैध काम करने वाले पैरा मिलिट्री और गोरिल्ला सेना ने मिलकर शांति से रहने वाले अहिंसक समाज के 412 लोगों की हत्या की है। चार हजार से ज्यादा मानव अधिकारों का हनन हुआ है, 18 बार इन लोगों को विस्थापित किया गया है। यहाँ एक नदी है, जिसका नाम रियो सान होजेज हैं। बहुत समय पहले इस नदी के किनारे बसे सेनहोजे समुदाय गुरैल्ला और पैरा मेल्टरी के बीच क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर हुई लड़ाई के कारण भाग गए थे। जब यह लड़ाई बंद हुई, तब गुरैल्ला के लोग ही पैरा मेल्ट्री में शामिल हो गए थे।

इस क्षेत्र में अवैध व्यापार को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए। इसी प्रयास में शांति स्थापित करने के लिए यह समुदाय बना था; लेकिन यहाँ की पुरानी सरकार अपने अवैध कामों को चलाने के लिए, ऐसे समुदाय जो सरकार के गलत कामों को गलत कहने की हिम्मत रखते है, वैसे लोगों को इस क्षेत्र में बसने की इजाजत नहीं देती थी। नई सरकार ऐसे समुदाय को उनके मूल स्थान पर बसाए रखने में तो आपत्ति नहीं करती, लेकिन पैरा मिलिट्री इनको उजड़ने के लिए तत्पर रहती है। तब इस समुदाय को समझ आया कि, यह लड़ाई पैसों के लिए है, ना कि विचार धारा की। क्योंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत धनी है, यहाँ के पहाड़ों में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ मौजूद हैं। इसलिए यह लड़ाई अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी जारी है। इस देश में शांति के बहुत प्रयास हुए। शांति के प्रयास करने वाले यहाँ के राष्ट्रपति 'सैन्ट्रोस' को शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया है। यहाँ इन्होंने शांति कायम करने के लिए पैरा मिलिट्री और गोरैल्ला सेना के बीच समझौता करवाया है। पूर्व राष्ट्रपित सैन्ट्रोस ने जो समझौता किया था, उस समझौते को क्रियान्वित करने तथा सत्य और अहिंसा का काम वर्तमान राष्ट्रपति पेट्रो की सरकार कर रही है। अपनी नेता गिलोरिया इसाबेल क्यार्टस मोंटोया को इसकी जिम्मेदारी दी है। यह 30 साल पहले अपार्टाडो की मेयर थी, तब से इस कार्य को कर रही है, लेकिन वह भी उतनी सफलतापूर्वक नहीं कर पा रही, क्योंकि इस सरकार में भी कुछ बड़े माफिया मौजूद हैं। चूंकि गौरैल्ला समुदाय के लोग ही पैरा मेल्टरी में शामिल हैं, इसलिए सरकार अवैध व्यापार और मानव तस्करी को नहीं रोक पा रही है। इन सभी परिस्थितियों से लड़कर, इस शांति समुदाय ने खुद अपने खाने-पीने और रहने की सभी सुविधाएं स्वयं अपने स्तर से जुटाई हैं। अब इस पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी कंपनियों द्वारा पैदा की जाने वाली केले और गन्ने की खेती दिखाई देती है। यहाँ केले की डेढ़ दो मीटर गहरी नालियां खोदकर रोपाई की जाती है,

क्योंकि यहाँ बरसात अधिक होती है। यहाँ भारत जैसी खेती तो नहीं है, लेकिन पहाड़ी पर भी गन्ना होता है। यहाँ कॉफी के बहुत बड़े-बड़े खेत हैं, जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इस समुदाय ने अपने नियम बना रखे हैं कि, समुदाय में कोई भी व्यक्ति हथियार नही रखेगा, कोई भी असंवैधानिक रूप से जमीन पर कब्जा नहीं करेगा, कोई भी ना तो शराब पीएगा और ना ही बनाएगा तथा आपसी झगड़ों का समाधान भी सभी मिल-जुलकर ही करेंगे। यह प्रकृति का रक्षण-संरक्षण करने वाला एक अनोखा समुदाय हैइस समुदाय के साथ 9 नवम्बर तक इस क्षेत्र की सेनहोजे नदी की पैदल, घुड़सवारी और कहीं-कहीं खच्चर से 23 घंटे की दुर्गम यात्रा की। यह बहुत ही घना (गहरा) हरा जंगल है। इतना गहरा-हरा जंगल पहले कभी नहीं देखा। जंगलों के ऊपर बादल, पहाड़ियों और पहाड़ों के अंदर से निकलती हुई जलधाराएं देखकर, मन आनंदित हो गया। यह बहुत ही सुंदर जंगल है। कहीं-कहीं तो इतना गहरा जंगल है कि, पशु अंदर तक नहीं जा सकते और कुछ जगह संतरे के बाग और दूसरे पेड़ हैं, जो बहुत आकर्षक लगते हैं। यहाँ के समुदाय ने बताया कि, यह बहुत घना जंगल है। आने-जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, फिर भी यह कंपनी जंगल में बसे सभी गाँवों को उजाड़ना चाहती है। मैनें यही कहा कि, यह जैव विविधता के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय जगह है। ऐसी महळवपूर्ण जगहों को खनन (माइनिंग) के लिए देना, कदाचित उचित नहीं है। इस जगह को सुरक्षित रखना होगा। यहाँ आदिवासी विश्वविद्यालय में संवाद किया। दक्षिण अमेरिका में कोलम्बिया की राष्ट्रीय नेता, मंत्री और सत्य शोध की अध्यक्षा गिलोरिया इसाबेल क्यार्टस मोंटोया ने अपनी पुस्तक 'ळ मवहर्तपें कम सं ळनमततं ल हमवहर्तपें कम सं मेचमतंद्रमरू त्मसिमगपवदमे मद जपमउचवे कम सं ऱ्चं जवजंस' भेंट की। यहाँ मुझे प्रकृति से प्रार्थना करने तथा तभासं के अनुभवों का रखने का अवसर मिला। यह दक्षिण अमेरिका में होने वाले तस्करी, नशीले पदार्थ, हथियार व मानव तस्करी का क्षेत्र है। इसलिए यहाँ यह सब देखकर आत्मा भी कांप जाती है। ऐसी स्थिति में शांति समुदाय का प्रकृति के पोषण के कार्य में लगना एक अद्भुत अनुभव कराता है।

यहाँ के समुदाय द्वारा एक बड़ी खनन कंपनी के खनन से बचाकर, जंगल को संरक्षित किया गया है। इस जंगल को मेरे नाम से घोषित किया। इन्होंने कहा कि, जिस तरह से मैंने अरावली पर्वत माला को खनन से रुकवाकर संरक्षित किया है, इसी तरह से हम भी अपने जंगल को बचाने के काम में जुटे हैं। इस जंगह में कभी भी खनन नहीं हो पायेगा। 10 नवम्बर को शांति समुदाय (कौमूनी दाद दे पाज) ने सेनहोजेसीतो में प्रातः प्रार्थना कराई और अपने अनुभवों को रखा। यहाँ प्रार्थना कराते हुए मैंने कहा कि, हे देवी स्वरूपा 'प्रकृति'! हम सब इंसान, पेड़-पौधे, जीव-जंतु तुम्हारे बच्चे हैं। तुम्हारा प्यार हम पर बना रहेगा, तो हम सब तुम्हारे बच्चे बनकर आपके प्रत्येक अंग-प्रत्यंगो को समझकर संवारने का काम करते रहेंगे। हे देवी स्वरूपा प्रकृति मां! हम उन पर आपकी कृपा चाहते हैं, जो आपको सम्मान करते हैं, जो आपको देवी स्वरूपा मानते हैं और आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते। जो आपको कष्ट दे रहे हैं, आप उनको क्षमा मत करिए। उनको आप जितना भी बड़ा से बड़ा दंड दे सकते हैं, दीजिए और जो आपका सम्मान करते हैं, उनका संवर्द्धन करिए। यहाँ की ग्रैंड मदर और सिविल सोसाइटी के मेंबर ने मुझे संयुक्त रूप से यूनिवर्सिटी ऑफ रजिस्टेंस एग्रो सेंटर की तरफ से सफेद कश्मीरी शॉल ओढ़ाकर, सम्मानित किया। शांति समुदाय के लोगों ने कहा कि, ''हमने पिछले 27 सालों में बहुत मेहनत से 60 हेक्टेयर जंगल को खनन से सुरक्षित कर रखा है, उसे 'राजेंद्र सिंह एग्रो कल्चर सेंटर' के नाम से जाना जायेगा।'' इसका यहाँ बोर्ड लगाया गया। 11 नवम्बर को अपार्टाडो में हुई बैठक में यहाँ की मेयर शामिल हुई। उसने यहाँ सेनहोजे नदी में गाय को काटकर डालने वालों पर रोक लगाने हेतु बातचीत करते हुए कहा कि, गाय की उपस्थिति का दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोपरि स्थान है। यह सही वक्त है, जब सेनहोजे नदी की पवित्रता, शुद्धता और स्वच्छता को बचाकर रखें। यदि नदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा। यहाँ का जंगल भी वैश्विक दृष्टि से बहुत महळवपूर्ण है। जंगलों को बचाना लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र में खनन होगा तो पूरा जंगल ही बर्बाद हो जाएगा। यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए बहुत महळवपूर्ण है; इसलिए आप इस शांति समुदाय (कौमूनी दाद दे पाज) की मदद करें।

मेयर ने जबाव देते हुए कहा कि, ''हम आपसे मिलने ही इसलिए आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि, इस वैश्विक महळवपूर्ण जगह को विश्व के लिए बचाकर रखना जरूरी है। यदि यह जंगल कटता है, तो यहाँ की जैव विविधता भी खत्म हो जायेगी। सेनहोजे नदी की यात्रा करने व नियोल जंगल को वैश्विक स्तर पर जैवविविधता हेतु संरक्षित करने हेतु मैं आपकी आभारी हूं।'' सेनहोजेसीतो की यात्रा करके, 12 नवम्बर को अर्पाटाडो एयरपोर्ट से मैडेलिन पहुँचे, जहां तीर्थ बचाओ जुड़ाव के साथियों के साथ बैठक की। पर अभी भी मेरे मन में कोलम्बिया की वही डरावनी तस्वीर सामने थी। मैडेलिन से यात्रा करके 14 नवम्बर को पुएब्लो बेलो, कोलम्बिया क्षेत्र में पहुँचे। यह प्राकृतिक नैसर्गिक चेतना का केंद्र है, आध्यात्मिक भाषा में इसका नाम मीना मुनिया है। मीना मुनिया दुनिया के केंद्र में स्थित है। इस जगह को बादलों का घर भी कहा जाता है। यहाँ के आध्यात्मिक गुरु को मामू कहा जाता है। ये भगवान् के सचिव जैसे होते हैं; जो समाज को भगवान् के साथ जोड़ने का काम करते हैं। ये भक्त और भगवान् के बीच की एक कड़ी हैं, जो भक्त को भगवान् से जोड़कर रखती हैं। ये किसी के गुलाम नहीं होते, ये तो केवल भगवान् और भक्त के बीच संबंध बनाने के लिए भगवान् ने जो विधि रची है, उस विधि का समाज के सामने वर्णन करके, समाज को विधि के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। समुदाय और 'विश्व तीर्थ बचाओ जुड़ाव' के साथियों के साथ विचार-मंथन हुआ, जिसे यहाँ तरीबरी कहते हैं। यहाँ चिंतन में, सबसे पहले सभी को कोकिन वनस्पति की पत्ती खिलाई जाती हैं। यह संजीवनी जैसी होती है। जब भी इस समुदाय के लोग कोई पवित्र काम करते हैं, तो इस पत्ती को चबाते हैं। उसके बाद वे अपना अनुष्ठान करते हैं। यहाँ मैंने कहा कि, यह पूरी दुनिया एक है, तीर्थ बचाने वाले भी एक हैं; हम सब अपनी संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करते हुए प्रकृति के रक्षण-संरक्षण में भी एक होकर ही जुटें। हम प्रकृति के प्रति निहित भारतीय आस्था को समझें। भारतीय आस्था कोई धार्मिक आस्था नहीं है, यह तो भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता की देन है। प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में प्रकृति के साथ सम्मान से जीना और प्रकृति के लिए सम्मान से काम करना निहित है। भारतीय ज्ञान-तंत्र केवल भारत के भूखंड व जीवन व्यवहार से जुड़ा हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के संयुक्त ज्ञान का निचोड़ है। इस 21वीं शताब्दी में हो रहे अत्याचार, शोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण के खिलाफ दुनिया को खड़े करने का एकमात्र रास्ता भारतीय ज्ञान-तंत्र ही है। इसी को जीवन में अपनाना होगा।

कोलम्बिया में महात्मा गांधी जैसे सत्य और अहिंसा के प्रयोग दिखते हैं। यह चित्र बहुत पुराने सिएरा नेवाद डे सांता मार्टा, पर्वत पर मौजूद अरहुआका, कोगी, वायो, कोरन्कार आदिवासी समुदायों में ही दिखता है। यह प्रकृति का रक्षण-संरक्षण करके, सुख-शांति से जीने का अपना एक मूल रास्ता अपनाए हुए हैं। लेकिन इन आशाओं के बीजों से दुनिया जानने और सीखने की कोशिश नहीं कर रही है। दुनिया को कोलम्बिया के बगोटा, मेडेलिन जैसे शहरों में ही दिखते हैं; पर यदि कोलम्बिया को देखना है तो सिएरा नेवाद डे सांता मार्टा, पर्वत पर जाना चाहिए और सीखना चाहिए। यहाँ के आदिवासी पर्यटन के लिए अपने क्षेत्र में खुली छूट नहीं देते। इनकी नियंत्रण रेखा में पर्यटक नहीं जा सकते। मैं यहाँ इसलिए जा पाया, क्योकि यहाँ के समुदाय ने मुझे अपने जैसा प्रकृति, मानवता और भारतीय ज्ञानतंत्र का काम करने वाला माना। इस कोलम्बिया यात्रा में हमारे ''नीर-नारी-नदी नारायण है, नारायण है, नारायण है, ''नारे और हमारी पंचमहाभूतों की व्याख्या को लोगों ने स्वीकार किया। कोलम्बिया में एक तरफ हिंसा, अशांति, तस्करी, हत्या और लूटपाट है; दूसरी तरफ सुख, समृद्धि, शांति और प्रकृति-प्रेम का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यह दर्शन केवल आदिवासियों की भूमि पर ही मौजूद है, शेष कोलम्बिया को भी इसी तरह सदाचार और व्यवहार अपनाना चाहिए। यह सिर्फ कोलम्बिया में ही क्यों? पूरी दुनिया में होना चाहिए।

PROJECT WATER SECURITY AND CLIMATE ADAPTATION

(An Indo-German Bilateral Project)

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Background: Water is a critical natural resource, indispensable for sustaining life, ecosystems, and human well-being. It serves as the foundation for agriculture, energy production, industry, and public health, while supporting biodiversity and playing a key role in climate regulation. However, the rising pressures of climate change, pollution, population growth, and inefficient resource management have intensified global water security challenges. Addressing these multifaceted issues demands an integrated and adaptive approach to ensure the sustainable management of freshwater resources. Recognizing the critical importance of water to global development, this project aligns with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Clean Water and Sanitation (SDG 6), which seeks to ensure access to safe water and sanitation for all. Additionally, the project underscores the interlinkages between water and other SDGs: supporting Zero Hunger (SDG 2) by facilitating sustainable agriculture, promoting Good Health and Well-Being (SDG 3) through access to clean water, and contributing to Climate Action (SDG 13) by building resilience against climate impacts such as floods and droughts. This document provides a detailed overview of the project's objectives, strategies, and anticipated outcomes in addressing water-related challenges.

About WASCA: The Water Security and Climate Adaptation in Rural India (WASCA-II) project addresses the escalating water challenges faced by rural communities in India, exacerbated by climate change. Focused on enhancing sustainable water resource management, the project promotes integrated and locally tailored solutions to mitigate water scarcity and build resilience against climatic uncertainties. By empowering rural communities, WASCA-II aims to address issues such as erratic rainfall, water shortages, and declining water quality, ensuring that water management practices are adaptive, inclusive, and responsive to evolving challenges. The project adopts a learning-centered approach, enabling continuous improvement in resource management and fostering long-term climate resilience. Funded by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), WASCA-II reflects a collaborative effort between India's Ministry of Rural Development (MoRD) and Ministry of Jal Shakti (MoJS). This partnership underscores a shared commitment to addressing water security and climate adaptation through sustainable and integrated strategies. By fostering innovative and adaptive management approaches, WASCA-II aims to secure water resources and support the well-being of rural communities, ensuring they are equipped to thrive amidst the growing challenges posed by climate change. The project spans 17 states across India, covering 15 agroclimatic zones within five major climatic regions, each with unique characteristics influencing agricultural practices and water management strategies. These regions face distinct challenges related to temperature, rainfall, and soil conditions, requiring tailored solutions to enhance water security and climate resilience.

Areas of Operations: The project addresses key challenges in water and natural resource management through a comprehensive approach encompassing 10 crucial operational areas. The 10 focus areas are briefly mentioned below:

Land Management: WASCA focuses on implementing integrated approaches to rehabilitate degraded lands, ensuring that land use is optimized for both environmental sustainability and long-term agricultural productivity.

Command Area Development (CAD): The project's efforts in Command Area Development (CAD) are designed to optimize the use of available water resources through modernized irrigation infrastructure and improved water management practices.

River Rejuvenation: The project employs advanced geo-informatics tools to assess and manage river systems, facilitating eco-restoration initiatives and improving flood control measures. These tools help in mapping water courses, monitoring river health, and predicting flood-prone areas, enabling more effective river management.

Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain (JSA-CTR): The ridge-to-valley approach promoted under the Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain initiative emphasizes the need for comprehensive, watershed-based solutions. The project integrates this approach by focusing on water harvesting, storage, and efficient utilization across entire catchment areas.

Sustainable Management of Water Bodies: The sustainable management of water bodies, such as lakes, ponds, and reservoirs, is essential for maintaining ecological balance and supporting agriculture. WASCA's approach to restoring water bodies includes implementing comprehensive catchment area treatment programs that address pollution, siltation, and encroachment.

Groundwater Management: WASCA focuses on augmenting aquifer recharge through techniques such as rainwater harvesting, improving recharge wells, and promoting sustainable agricultural practices. These interventions are designed to restore groundwater levels, enhance water availability, and ensure long-term groundwater sustainability.

Coastal Area Management: The project addresses these challenges through the application of advanced tools and techniques to manage coastal areas effectively. By considering salinity and sedimentation patterns in developing scientific solutions, the project ensures the implementation of measures to control coastal erosion, enhance soil fertility, and protect ecosystems.

Convergence Initiatives: Convergence is fostered by aligning multiple programs, such as the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), Water Conservation (WDC 2.0), and Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS). By integrating these schemes, WASCA ensures the efficient allocation of resources, improves implementation on the ground, and promotes a holistic approach.

Capacity Development: The strong emphasis on capacity development ensures that local stakeholders, including government officials, water managers, and community leaders, are equipped with the necessary skills for planning, implementation, and monitoring. Through training programs, workshops, and knowledge-sharing initiatives, the project aims to build local capacity for sustainable water management and stakeholders adapt to changing climatic conditions.

Digital Transformation: WASCA harnesses GIS tools to collect, analyze, and visualize water-related data, enabling more informed decision-making. By providing real-time information on water availability, land patterns, and environmental conditions, GIS supports better resource planning, improves monitoring of water systems, and enhances the overall effectiveness of water management strategies.

Achievements: The WASCA project has delivered significant achievements and practical outputs across various states, demonstrating its successful implementation of sustainable water and natural resource management practices.

- Hampapuram, Andhra Pradesh: The project developed a comprehensive watershed as a model for the implementation of Gram Panchayat (GP) GIS plans, utilizing a scientific approach to optimize land and water resource management. This initiative serves as a benchmark for watershed management in rural areas, showcasing the power of data-driven decision-making.

- Tamil Nadu and Kerala: the project has implemented various climate-resilient measures in pilot districts, enhancing local communities' ability to adapt to changing climate patterns and mitigate the impacts of climate-related challenges. These measures included mangrove plantation, cascading of tanks, wetland conservation, grey water management and sand dunes stabilizations, all tailored to the region's specific climatic crisis.

- Bihar: the project successfully mapped the entire drainage network contributing to the River Ganga, identifying blocked and semi-blocked streams using GIS tools. This effort has significantly improved the understanding of water flow and drainage patterns, allowing for targeted interventions to enhance water availability and reduce flood risks.

These examples reflect the project's ability to achieve tangible, scalable solutions, demonstrating its contribution to advancing water security and climate adaptation across India.

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

ग्राम्य विकास विभाग
उत्तर प्रदेश

जल संरक्षण के अन्य कार्यों की प्रगति व प्रभाव : ग्रामीण क्षेत्रों में गिरते भूजल स्तर को सुधारने एवं जल संचयन एवं जल संरक्षण को बढ़ाने हेतु मनरेगा योजना अंतर्गत जल संबंधी अनेक कार्य कराए जा रहे हैं। मनरेगा योजना के तहत कुल 266 प्रकार के अनुमन्य कार्य हैं, जिनमें से 85 कार्य जल संसाधन प्रबंधन एवं जल संरक्षण से संबंधित हैं। जैसे-तालाब का निर्माण, जलाशयों का पुनरोद्धार, चेक डैम का निर्माण, सोक पिट का निर्माण, रुफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, नदियों का पुनरोद्धार, बाँधों का निर्माण, मेड़ बन्दी, पौधारोपण आदि। प्रदेश ने 5 वर्षों में 10.02 लाख जल संबंधी कार्य पूर्ण कराते हुए जल संबंधी कार्यों पर 15467.03 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की है।

कराए गए जल संबंधी कार्यों का वर्षवार विवरण :

वित्त वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल योग
जल संचयन संबंधी कार्य	53591	52047	106213	62826	51107	325784
वॉटर शेड बंधन	13456	10715	21456	13574	10960	70161
सिंचाई संबंधी कार्य	82080	79873	163284	102612	76993	504842
परंपरागत जलाशयों का जीर्णोद्धार	16000	15552	30336	22052	17407	101347
कुल योग	**165127**	**158187**	**321289**	**201064**	**156467**	**1002134**

जल संबंधी कार्यों पर किए गए व्यय का विवरण (करोड़ में) :

2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल योग	कुल योग
जल संचयन संबंधी कार्य	1168.52	801.88	1019.85	1058.88	594.54	4643.67
वॉटर शेड बंधन	318.88	166.16	235.19	214.06	162.94	1097.24
सिंचाई संबंधी कार्य	1579.89	1251.64	1427.49	1328.61	1216.38	6804.01
परंपरागत जलाशयों का जीर्णोद्धार	571.73	316.62	766.50	738.27	529.01	2922.12
कुल योग	**3639.02**	**2536.30**	**3449.03**	**3339.81**	**2502.87**	**15467.0**

तालाबों का निर्माण : मनरेगा योजना अंतर्गत प्रदेश में बड़े स्तर पर तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। तालाबों का मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी को संचित करना है। यह जल स्रोतों के सूखने के जोखिम को कम करता है और सूखा पड़ने पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तालाबों में पानी जमा करने से भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। तालाब का पानी धीरे-धीरे जमीन में समा जाता है, जिससे जल की सतह में वृद्धि होती है। इसके अलावा, तालाबों में पानी का संचयन वर्षा जल संचयन की प्रक्रिया को संतुलित करता है, जो पर्यावरण को बनाए रखने में मदद करता है। इससे न केवल जल की उपलब्धता बढ़ती है, बल्कि बाढ़ की स्थिति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। प्रदेश में गत 5 वर्षों में मनरेगा योजना से 110737 तालाबों का निर्माण कराया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 18192 तालाबों पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है।

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	संख्या
1	2019-20	16579
2	2020-21	16821
3	2021-22	20205
4	2022-23	26501
5	2023-24	3063

अमृत सरोवर प्रगति एवं प्रभाव : वित्तीय वर्ष 2022-23 में माननीय प्रधानमंत्री जी के परिकल्पना के स्वरूप ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमृत सरोवर योजना प्रारम्भ की गयी। अमृत सरोवर की परिकल्पना का जन्म भी उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में एक सरोवर पर भ्रमण करने के पश्चात हुआ। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य प्रदेश को दिया गया, इस लक्ष्य के अनुसार प्रदेश को 5625 अमृत सरोवर निर्माण का लक्ष्य दिया गया। इस लक्ष्य को प्रदेश सरकार ने मात्र 6 माह में ही पूर्ण कर लिया। प्रदेश सरकार ने अमृत सरोवर योजना की महत्ता को देखते हुए प्रति ग्राम पंचायत 2 अमृत सरोवर निर्माण का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह योजना 15-08-2023 को पूर्ण कर दी गयी परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लेते हुए इस योजना को 1 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया।

अद्यतन स्थिति अनुसार प्रदेश ने 24337 अमृत सरोवरों का चिंहांकन करते हुए 18706 अमृत सरोवरों पर कार्य पूर्ण करा लिया है। प्रदेश इस कार्यक्रम के प्रारम्भ से ही देश में प्रथम स्थान पर रहा। अमृत सरोवरों ने ग्राम पंचायतों में न केवल जल संचयन एवं जल संरक्षण करते हुए गिरते भूजल स्तर को सुधारा है अपितु इन अमृत सरोवरों पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे योग दिवस, छट पूजा, स्वतंत्रता दिवस आदि के आयोजन से सामाजिक समरसता भी बढ़ी है। अमृत सरोवरों के समीप भूमि की उपलब्धता के अनुसार खेल मैदान/पार्क/ओपेन जिम का निर्माण भी कराया गया। अमृत सरोवरों के समीप अमृत वाटिका का निर्माण भी किया गया। जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश ने ष्सेल्फी विद अमृत सरोवरष का आयोजन 22-03-2023 को आयोजन किया, जिसमे ग्रामीण निवासियों, जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अमृत सरोवर पर सेल्फी लेते हुए उन्हे विभिन्न सोशल मीडिया चसंजवितउे पर पोस्ट किया, यह कार्यक्रम इतना सफल रहा कि उस दिन यह ट्विटर के टॉप ट्रेंडिंग पोस्ट मे से एक रहा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अत्यधिक गर्मी के दृषिगत जो अमृत सरोवर सूख गए थे, उनमे ग्राम पंचायत में स्थित नलकूपों तथा नहरों के माध्यम से सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए अमृत सरोवर में पर्याप्त जल की व्यवस्था करने हेतु निर्देश जारी किए गए। इसके अतिरिक्त यह निर्देश भी जारी किए गए कि अमृत सरोवर का कैचमेन्ट एरिया इम्प्रूवमेंट सुनिश्चित किया जाये, जिससे पर्याप्त मात्रा में वर्षा जल अमृत सरोवर में पहुँच सके।

नदियों के पुनरोद्धार की प्रगति एवं प्रभाव : प्रत्येक नदी के लिए समुद्र तट तक पानी का न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह अनिवार्य रूप से बनाया जाना आवश्यक है, जो नदी के साथ लगने वाले इकोलॉजिकली संवेदनशील क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तुओं को बनाये रखने में सहायक सिद्ध होते है, तथा इससे नदी के ऊपर निर्भर बड़े समुदायों को रोजगार की सुरक्षा भी मिलती है। उक्त आवश्यकता के दृष्टिगत् मुख्य नदियों में मिलने वाली सहायक विलुप्तप्राय नदियों का पुनरूद्धार मनरेगा योजना से किया जा रहा है।

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	जनपद की संख्या	नदियों की संख्या	किलोमीटर
1	2018-19	6	06	94.48
2	2019-20	26	19	843.84
3	2020-21	36	25	1410.81
4	2021-22	12	14	268.83
5	2022-23 एवं 2023-24	38	63	690.0

नदियों के पुनरूद्धार कार्यक्रम में न केवल बेड एरिया पर कार्य कराया गया अपितु नदियों के किनारे तालाब निर्माण, वृक्षारोपण, नालों का जीर्णोद्धार इत्यादि कार्य कार्य गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रति जनपद 2 नदियों/ बड़े नालों के जीर्णोद्धार का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा योजना अंतर्गत नदियों के पुनरूद्धार कार्य से कई ऐसी छोटी नदियाँ जो अपना स्वरूप पूर्णत: खो चुकी थी उनको उनके मूल स्वरूप में लाने का कार्य कराया गया। कई नदियों पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण किया जा चुका था, उन नदियों पर से अतिक्रमण को हटाते हुए कार्य कराया गया। मनरेगा योजना से कार्य कराने से इन नदियों में अविरल धारा का प्रभाव देखा जा सकता है।

एनटीपीसी NTPC
50 YEARS OF POWERING GROWTH

बोंगाईगाँव
BONGAIGAON

GENERATING MILLIONS OF SMILES !

Powering progress goes beyond the generation of electricity; it encompasses empowering communities and nurturing a sustainable future. At NTPC Bongaigaon, Assam we not only generate 750 MW of reliable power, our commitment is to illuminate lives and drive positive change while upholding a healthy balance with the environment.

**TOGETHER,
WE KINDLE DREAMS AND
ASPIRATIONS
FOR A BRIGHTER TOMORROW.**

NTPC Limited

(A Govt. of India Enterprise)

Bongaigaon Thermal Power Station

P.O. : Salakati, Distt. : Kokrajhar (BTAD),
Assam - 783369

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

Follow us ON : /ntpc1 /ntpcltd1 /ntpclimited /company/ntpc /ntpclimited

Leading the Power Sector

पावरग्रिड
POWERGRID

1 राष्ट्र
ग्रिड
फ्रिक्वेंसी

पावरग्रिड

दुनिया की सबसे बड़ी विद्युत पारेषण उपयोगिताओं में से एक

पावरग्रिड का व्यवसाय

पारेषण

- पारेषण लाइनें– 1,78,975 सर्किट किमी
- सब–स्टेशन– 280
- ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता– 5,45,961 एमवीए

परामर्श सेवाएं

- 250 से अधिक घरेलू क्लाइंट्स को पारेषण संबंधी परामर्श
- 23 देशों में वैश्विक उपस्थिति के साथ 30 से अधिक क्लाइंट्स
- पावरग्रिड लीडरशिप एकेडमी– दुनिया भर के प्रतिभागियों के लिए 550+ पाठ्यक्रम

टेलिकॉम

- 1,00,000 कि.मी. टेलिकॉम नेटवर्क का स्वामित्व एवं प्रचालन
- एनकेएन एवं एनओएफएन क्रियान्वयन में प्रमुख परामर्शदाता

भविष्योन्मुखी

- नवीनतम तकनीक द्वारा संचालित
- अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का एक महारत्न सार्वजनिक उपक्रम है, जो देश भर में पारेषण योजनाओं के नियोजन, डिजाइनिंग, वित्तपोषण, निर्माण, प्रचालन तथा विद्युत अनुरक्षण में संलग्न है और टेलिकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी प्रभावी उपस्थिति है।

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट सं.–2, सेक्टर–29, गुरुग्राम, हरियाणा–122001, फोन : 0124-2571700-719

पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

सीआईएन : L40101DL1989GOI038121 | वेबसाइट : www.powergrid.in | फॉलो करें

एक महारत्न पीएसयू

WATER AND ENVIRONMENT AGENDA AT NIUA

National Institute of Urban Affairs

The National Institute of Urban Affairs (NIUA) is an autonomous body under the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), India. It supports the Ministry, State Governments, and Cities in defining and implementing sustainable urban trajectories.

Since 2020, a core area of NIUA's focus has been on the 'water and environment' sector given its vital role enhancing liveability in cities and improving the quality of life of urban residents. Accordingly, a dedicated vertical for 'Water and Environment' was set up with the objective of supporting Indian cities in pursuing ecologically-responsible urban development.

The core areas of work undertaken by NIUA's Water and Environment vertical includes:

- Developing enabling frameworks, tools, and decision support systems to improve water security and enhance the environmental outlook in cities.
- Developing and organizing niche capacity building programmes on emerging areas of concerns and interest.
- Establishing innovative institutional mechanisM+s to translate forward looking policies into practice.
- Plugging existing knowledge gaps through action research.
- Supporting the Central Government and State Governments in implementing their programmes for water and environment management.
- Engaging with diverse categories of stakeholders to promote environmentally responsible behaviour.

Some of notable achievements of NIUA's Water and Environment Vertical include:

- Developed a national framework for managing urban rivers called "Urban River Management Plan" to help river cities across India to develop their river management plans in a holistic and integrated manner. Thus far, 70+ cities have prepared (or are in the process of preparing) their plans using this framework
- Introduced a programme on Shallow Aquifer Management for AMRUT 2.0 that is focused on promoting the judicious and sustainable management of shallow aquifers in order to enhance water security in cities. The programme is being implemented in 85+ cities across India.
- Developed an assessment framework to evaluate the efficacy and efficiency of the Drink from Tap mission in Odisha. The evaluation is being carried out in 24 cities across the State.
- Established India's River Cities Alliance of 145 cities from 21 States. The Alliance is a platform for river cities to interact and exchange knowledge and good practices on various facets of managing urban rivers.
- Running an annual flagship national Student Thesis competition on Re-imagining Urban Rivers to sensitize next generation professionals on water and river-sensitive consideration. So far, 115 universities across India have been associated with this initiative over the last four years.
- Promoting the application of Nature-based Solutions in urban settings through a dedicated programme in Bhubaneshwar.

The Water & Environment (W&E) vertical at NIUA operates from its New Delhi office with a diverse team of 20 members, that include scientists, urban planners, architects, civil engineers, environmentalists, geologists, and other experts.

JAL PRAHARI SAMMAN SAMAROH 2024

Distinguished Jury Panel

JUSTICE SANGITA DHINGRA SAHGAL, Chairperson

Members

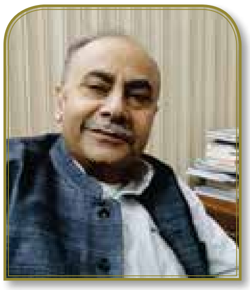

Dr. DK Bhalla (IAS) Retd.
Advisor to Nagaland CM

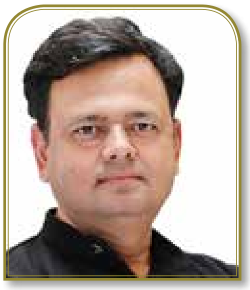

Shri Yugal Joshi
Programme Director
Niti Aayog

Giriraj Goyal (MES)
Former Director,
(Ministry of Jal Shakti)

Shri Sujith Bangar
Ex-IRS Officer &
CEO Taxbuddy.com

Shiv Mohan Dixit
Advisor (Technical)
National Water Mission
Ministry of Jal Shakti

Shri B. K. Yashwant Patil
Head-IT & Madhuban Radio Brahma Kumaris, Mount Abu

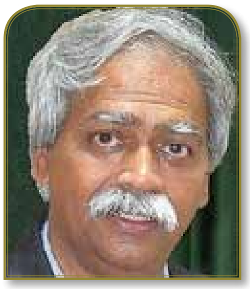

Shri Vinod Bodhankar
Co-Founder, Co-Director Sagarmitra Abhiyaan & Convenor, IPRBC, Jalbiradari

Shri Ajay Kaushik
HOD Horticulture
Delhi TourisM+

CA Shri K. K. Gupta
Chartered Accountant

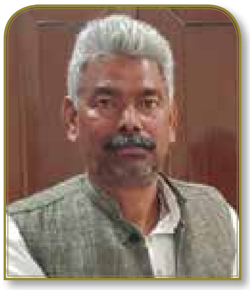

Shri Umashankar Pandey
Padma Shree Awardee

Shri Laxman Singh
Padma Shree Awardee

Anil Singh Sagar
Convenor, Jal Prahari Samaroh
& Senior Journalist

बेतवा की आस्था का कायम रहे गौरव, हर तालाब को मिले जीवन

अजय नामदेव
कार्यक्रम संयोजक
बहुजन हितकारी शिक्षा प्रसार समिति
जिला निवाड़, मध्य प्रदेश

लगभग तीन दशक से जल संरक्षण, जल संवर्धन, तालाबों के गहरीकरण, जैविक खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण जैसे विषयों पर ग्रामीण स्तर सक्रियता सतत जारी है।

बुंदेलखंड के निवाड़ी जिले में ठेहरका के तालाब से बेतवा नदी तक नैना नदी के उद्गम से लेकर संगम तक पदयात्रा कर दोनों ओर वृक्षारोपण एवं नदी को स्वच्छ एवं संरक्षित कर पुनः जीवित करने का सफल प्रयास किया गया। इस कार्य से मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के 14 गांव एवं उत्तर प्रदेश झांसी के 6 गांव से निकली नैना नदी को पुनर्जीवित करने का एक अनूठा प्रयास सफल रहा। इस पहली सफलता के बाद तालाबों की सफाई एवं गहरीकरण का कार्य भी उनके द्वारा किया गया।

पारंपरिक वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर तालाबों को गहरा कर, नदियों की सफाई के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए केन नदी से लेकर बेतवा नदी तक लगभग 60 किलोमीटर की एक पदयात्रा की जिसमें 12 पंचायत शामिल हुई। यात्रा को सफलतापूर्वक ओरछा में बेतवा नदी के दोनों घाटों की सफाई कर समापन किया गया। यात्रा के फलस्वरुप ओरछा में जल स्वच्छता सुनिश्चित करने के प्रयास हुए जो आज भी ओरछा जो कि रामराजा की नगरी के रूप में विख्यात है।

बेतवा नदी समुचे बुंदेलखंड के लिए जल का स्रोत है व आस्था का केंद्र है व स्वच्छ एवं सुंदरता के चलते यहां जल से जीवन को अधिक समृद्ध बनाने में सहयोग मिला। जन अभियान परिषद के साथ मिलकर जल संवर्धन के तहत निवाड़ी जिले के टेहरका ग्राम पंचायत के तालाब की सफाई और तालाब के पानी को पीने योग्य बनाने का लक्ष्य लेकर बहुजन हितकारी शिक्षा प्रसार समिति के कार्यक्रम समन्वय के रूप में निरंतर कार्यरत रहे एवं टेहरका पंचायत के एकमात्र जल स्रोत तालाब को जीवित करने का कार्य किया गया।

वर्ष 2022 में बुंदेलखंड के निवाड़ी जिले से 11 नदियों का जल लेकर उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में महादेव का अभिषेक करने के लिए एक यात्रा जन अभियान परिषद के सहयोग से निकल गई जिसका मुख्य उद्देश्य नदियों की सफाई पर केंद्रित था। एवं उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों की स्वच्छता एवं संरक्षण के लिए जागरूकता हुई और लोगों में नदी में कचरा ना फेंकने के लिए जागरूक हुए।

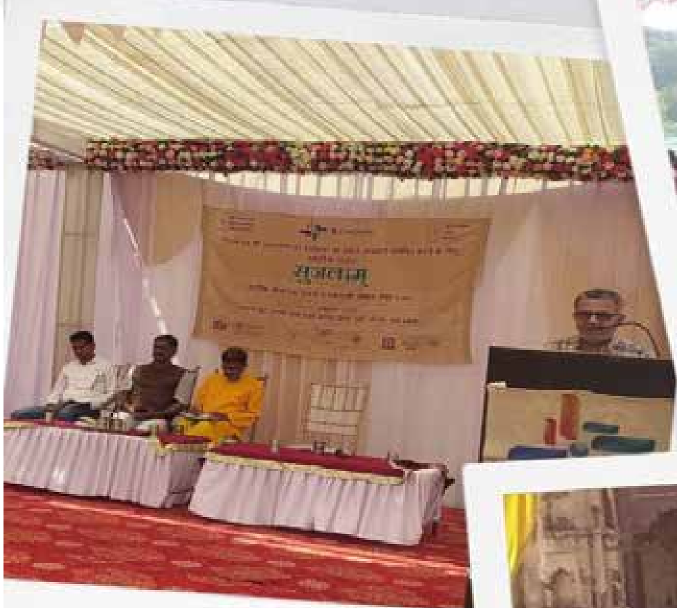

लोकसहभाग से लोकहित के जल स्रोतों ने बदल दिया तालुका के गाँवों के किसानों का जीवन

अजीत द्यानदेव पवार
सामाजिक कार्यकर्त
दहिवडी तहसील-सतारा, महाराष्ट

सरकार का सहयोग मिला तो सतारा जिले के कई काम देखते ही देखते पूरे हो गए। हजारों लोगों को लाभ मिला और यह प्रक्रिया जारी है।

जल संसाधन कार्यों को बिना किसी निधि से 2014 में शुरू किया और 200 किसान और 500 एकड़ खेती को फायदा मिला। सिंचाई क्षेत्र बढ़ गया और उसके बाद 2015 मे लगभग 5.75 किलोमीटर नाली के रुंदीकरण, विस्तारीकरण के काम करवाए और इसका 2000 किसानों को उनकी तीन हजार एकड़ जमीन पर लाभ मिला। करीबन 59 गाँवो में सिंचाई को लेकर समस्या थी लेकिन प्रशासन के सहयोग से ग्रामसभा मे पानी का महत्त्व समझाया, जिसका परिणाम लोगों ने शासन का काम खुद किया और बारिश के दिनों मे 100,200,300 मिलीमीटर बारिश वाला यह प्रदेश है वहा आज तक टैंकर नहीं आते। कई सालों से चलती आ रही यह समस्या ज्ञान के आधार पर खत्म हो गई।

तालुका के सभी गाँव और महाराष्ट्र के सैंकडों गाँवों में 12,500 ग्रामसभाओं से लेकर लोगों को समझाया और परिणाम यह हुआ कि हर रोज 80 गांवों में 45,000 लोग श्रमदान करने के लिए आए। पैसा, श्रम, संसाधन दान किए व 100 करोड़ रुपये जमा हुए, जिससे तीन करोड़ घनमीटर जलसंधारण का काम हुआ। इसी काम की सरकारी कीमत 700 करोड़ थे; इसके बाद पूरा तालुका टैंकर मुक्त हो गई थी। इलाके में बंजर जमीन उपजाऊ हो गई, किसान करोड़पति बन गए। माण गंगा नदी मे एक बंधारा बनवाया, जिसमें 25 करोड़ लीटर पानी इकटठा होता है और इससे 25 हजार लोगों को पानी मिला।

संत, समाज, शासन के माध्यम से 1 करोड़ पेड़ लगाये संगोपन और पानी दिया जिससे वृक्ष आज 40 फिट के बन गये है। जल समस्या करीबन पांच दशक से बनी हुई थी लेकिन उसे हल करने के लिए जमीन दान पर ली और कुंआ खोदा पाइप लाइन डालकर रयत शिक्षण संस्थान के युवा साथियों के साथ काम किया और लोक सहभाग से पीने के पानी का बढ़ा स्रोत खड़ा किया। उससे हजारों लोगों को फायदा पहुंचा।

VOLVO

स्कूल की पहल बच्चों के जरिए भविष्य की नींव रखती है

श्रीमती अमिता मोहन
प्राध्यापक, एमिटी इंटरनेशनल
पुष्प विहार, नई दिल्ली

बिल्डिंग में रेन वाटर हारवेस्टिंग लगाया, चलता रहे यह सुनिश्चित किया और बच्चों ने भी हिस्सेदारी निभायी, कई ऐप विकसित कर जल संरक्षण को नई दुनिया से जोड़ा है।

जल नीति जल संरक्षण, छात्र सहभागिता और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जो सभी स्थिरता और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के साथ कार्यरत है। जल संरक्षण में प्रशासनिक उपाय और छात्र-संचालित पहल दोनों शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करती है कि जल संरक्षण स्कूल संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन जाए।

जल संरक्षण पहल

जल संरक्षण विचारों को समर्पित एक सुझाव बॉक्स स्कूल के चारों ओर रखा गया है, जो शिक्षकों और छात्रों को अपने विचारों का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पहल जल-बचत उपायों और नवाचारों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है।

स्कूल ने कम प्रवाह वाले नल और फ्लश सहित 100 से अधिक जल संरक्षित करने वाले उपकरण लगाए हैं, जिससे सालाना लगभग 2 मिलियन लीटर पानी की बचत होती है। इसकी निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत जल-कुशल प्रणाली है, जो सुनिश्चित करती है कि स्कूल अपने जल-बचत लक्ष्यों को पूरा करता रहे।

वर्षा जल संचयन

एमिटी की वर्षा जल संचयन प्रणाली में तीन गड्ढे शामिल हैं जो वर्षा जल को इकट्ठा करते हैं और जमीन को रिचार्ज करते हैं। 1,50,000 लीटर की कुल भंडारण क्षमता के साथ, यह प्रणाली हर साल 1,00,000 लीटर भूजल को रिचार्ज करने में मदद करती है। एकत्रित वर्षा जल का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है, जिससे बागवानी के लिए बाहरी जल स्रोतों पर निर्भरता कम हो जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच और तकनीकी नवाचार

एमिटी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जहाँ छात्रों ने अभिनव जल प्रबंधन समाधान प्रदर्शित किए हैं। सिंगापुर में इन स्कूल्स प्रतियोगिता में टीम ऊर्जा ने भागीदारी की।

नासा स्पेस सेटलमेंट प्रतियोगिता में, स्कूल की टीम ने मंगल ग्रह की अंतरिक्ष बस्ती को डिजाइन किया, जिसमें एक अलौकिक वातावरण में जल प्रबंधन चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। जल प्रबंधन के लिए उनके अभिनव दृष्टिकोण ने उन्हें उनकी रचनात्मकता के लिए अतिरिक्त मान्यता दिलाई।

छात्रों ने निकाले जल संरक्षण के लिए सरल समाधान

कक्षा 12वीं के छात्र शिवम मुखर्जी ने स्लज नाइट नामक एक स्मार्ट सीवेज जल प्रबंधन प्रणाली तैयार की, जो अपशिष्ट जल के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करती है और पीने योग्य पानी के संदूषण को रोकती है।

नौंवी कक्षा के श्रेय भरतिया ने मिट्टी की नमी संवेदन और वर्षा का पता लगाने की क्षमताओं के साथ एक स्वचालित संयंत्र जल प्रणाली बनाई।

अधिराज कुमार चौहान ने महासागर अन्वेषण और पर्यावरण निगरानी के लिए एक मानव रहित समुद्री वाहन (यूएमवी) डिजाइन किया।

नव्या नायर ने पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल सिपाही मोबाइल ऐप विकसित किया, ताकि सोच-समझकर पानी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। ये परियोजनाएँ छात्रों के बीच रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्कूल की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिससे उन्हें जल संरक्षण चुनौतियों का समाधान करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जाता है।

SAVE WATER

जल ANTHEM
जल ANTHEM

EMERALD COURT OWNERS'
Resident Welfare Association
Office

RECHARGING
WATER
POSTER MAKING

वाटर हारवेस्टिंग से जल समृद्धि की ओर बढ़ते कदम...

अरुणिमा मिश्रा,
सचिव, आश्रयनिष्ठा वेलफेयर सोसाइट
न्यू सरकंडा बंगाली पारा,
बिलासपुर, छत्तीसगढ

पानी किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता लेकिन वाटर हारवेस्टिंग से जल समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। यह साबित करने के लिए छत्तीसगढ़ में चल रही है वाटर हारवेस्टिंग मशीनों का मिशन...

तालाबों की सफाई करवाकर, उन्हें गहरा करवाया ताकि जलभरण बढ़ाया जा सके और गाँवों में ज्यादा से ज्यादा पानी एकत्रित हो तथा लोगों, पालतू पशुओं को पानी मिल सके। आसपास के इलाके में वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा जल संरक्षण का कार्य करने के लिए जल संरक्षण जन-जन में जागरूकता अभियान चलाए गए। चूंकि गाँव में तालाब पानी का बड़ा स्रोत हो इसीलिए नए तालाबों का निर्माण कार्य करवाया गया। पानी मिलता रहे और उसका समुचित उपयोग हो इसलिए जल संरक्षण के तौर-तरीके सिखाने के लिए जल बचाओ मिशन चलाया गया। बृहद रूप से वृक्षारोपण कराया गया और जल जमाव करने के तरीके बताए गए जिससे जल संरक्षण करने में आसानी हो, वर्षा का जल इकठ्ठा करने और उससे सिंचाई करने के तरीक जैसे कई अन्य कार्य भी संस्था द्वारा कराई गई और समय-समय पर किए जाते हैं। हमलोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग मशीन मुफ्त में उपलब्ध कराई।

जल संरक्षण के लिए हम 10 गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग मशीन बांट चुके हैं इसके लिए हम लोग गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और जल संरक्षण के लिए उपाय बताते है तथा जरूरत की चीजें उपलब्ध कराते हैं जल संरक्षण के लिए हम छोटे-छोटे कैंप का आयोजन करते रहते है। जल संरक्षण के लिए अधिकतर हम किसान भाई लोगों को इसके बारे में बताने और जल इक्कठा करने का काम करते है, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। अतएव जल संरक्षण आज की मुख्य आवश्यकता बन गई है। गांवों में हम लोग जल संरक्षण के उपाय बताते हैं। ताकि लोग यह जाँच करें कि घर में पानी का रिसाव न हो। आपको जितनी आवश्यकता हो उतने ही जल का उपयोग करें। पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद रखें। मंजन करते समय नल को बंद रखें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलें। पानी के हौज को खुला न छोड़े। तालाबों, नदियों अथवा समुद्र में कूड़ा न फेंके। उसे स्वच्छ रखें,वर्षा जल संचयन और छोटे तालाबों में भंडारण गर्मियों के दौरान पानी की आपूर्ति करने का काम की संस्था करते रहती है

भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है इस लिए हम किसानों को हमेशा इसके लिए प्रेरित करने का काम करते रहते है गाँव में संस्था द्वारा कैंप लगा कर कुछ इस तरह के उपाय बताए जाते है। कृषि प्रथा जैसे ऑफ सीजन जुताई (पहले मानसून की बारिश से पूर्व) मिट्टी की नमी का संरक्षण ।। यदि भूमि को 30 सेमी की गहराई तक जोता जाता है 90 सेमी की गहराई तक नमी हासिल की जा सकती है। अन्य विधियाँ जैसे बीजों की जल्दी बुवाई, उर्वरकों का कम उपयोग, खर-पतवार, निकाई, कीट और रोग नियंत्रण और समय पर कटाई मिट्टी में सीमित नमी की बावजूद उपज में वृद्धि करता है।

मिट्टी में जैविक अवशेषों को मिलाने से मिट्टी की नमी का संरक्षण होगा। पहाड़ी ढलानों की खेती पानी को बहाव को रोकती है। छह प्रतिशत तक ढालू भूमि पर जहां भूमि की जल-शोषण क्षमता अधिक हो तथा 600 मिमी प्रतिवर्ष से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में समोच्च-बंध बनाकर खेती की जानी चाहिए ताकि एक समान ढाल की लम्बाई कम की जा सके तथा दो बांधों के बीच की भूमि पर खेती की जा सके। इससे भूमि एवं नमी संरक्षण साथ-साथ हो जाते हैं। पानी की कमी से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभी और भविष्य में सभी के लिए पर्याप्त पानी हो, पानी बचाना बेहद महत्त्वपूर्ण है। ड्रिप सिंचाई : यह तकनीक पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचाने में मदद करती है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। स्कूलों, मोहल्लों में भी लोगों को जल संरक्षण के क्रियाकलाप सिखा रहे हैं।

पेड़ मत काटो..
वृक्षारोपण
करो.

अंग्रेजों के जमाने की नदी को पुनर्जीवित कर किसानों के चेहरे पर लौटा दी मुस्कान

आशुतोष द्विवेदी, आईएएस
संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग
(पूर्व में - डीडीसी मुजफ्फरपुर)
पटना, बिहार

अंग्रेजों द्वारा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाई गई बाया नदीमानव निर्मित नदी है। यह बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले से निकलती है। नदी की कुल लंबाई लगभग 296 किलोमीटर है, मछुआरों, किसानों के लिए यह अब लाइफलाइन बन चुकी है।

बाया नदी, गंगा नदी की एक सहायक नदी गंडक नदी (नीचे की ओर) में मिल जाती है। बाया नदी अपनी यात्रा के दौरान हरसिद्धि, तुरकौलिया, कोटवा, कल्याणपुर, केशरिया, साहेबगंज, पारो, सरैया, वैशाली, पटेढ़ी बेलसर, गोरौल, भगवानपुर, महुआ, जंदाहा, सहदई बुजुर्ग, विद्यापति नगर, महनार, पटोरी, मोहिउद्दीन नगर, बछवाड़ा, मोहनपुर और तेघड़ा से गुजरती है।

यह नदी क्षेत्र में सिंचाई का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है तथा किसानों, मछुआरों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका का साधन है। हालांकि, मानसून के मौसम में नदी में बाढ़ आने का खतरा भी रहता है, जिससे आस-पास के इलाकों में फसलों और संपत्ति को नुकसान पहुँचता है। पिछले कुछ दशकों में से प्राकृतिक क्षरण व मानवीय क्रियाकलापों के कारण नदी का प्रवाह बाधित हुआ है।

नदी के विभिन्न हिस्सों में तलछट जमा होने और अत्यधिक शैवाल के खिलने से भी नदी का प्रवाह बाधित हो रहा है। नदी की पहुँच में, पुनर्ग्रहण के लिए विभिन्न खंडों का चयन किया गया है और बाया नदी के पारिस्थितिक प्रवाह को भी बनाए रखा गया है। नदी की पहुँच में, पुनर्ग्रहण के लिए विभिन्न खंडों का चयन किया गया है और पारिस्थितिक तंत्र को भी बनाए रखा गया है। अब यहाँ हालात बदले हैं, नदी को पारू ब्लॉक में पुनर्जीवित किया गया है। करीबन 35 किलोमीटर में काम होने के बाद सात हजार से अधिक किसानों को सीधे काम से लाभ मिला है जबकि आसपास के करीबन एक लाख किसान नदी के प्रवाह से लाभान्वित होंगे।

सूझबूझ से टैंकर किए विदा, गाँव में पानी के पाइप से पहुँची खुशहाली

बीरबल बिश्नोई, धींगाणा
जोधपुर, राजस्थान

सुरपुरा, मंडोर पंचायत समिति में प्राचीन स्थापत्य एवं कृषि के लिए प्रसिद्ध एक छोटा सा गांव है और आज पानी के कई काम यहां पहचान बन गए हैं।

ग्राम पंचायत द्वारा 2023 में पंप हाउस का निर्माण करवाया गया जोकि पूरे जिले में उदाहरण के रूप में सामने आया। ग्राम सुरपुरा में पंप हाउस निर्माण से पूर्व पानी की समस्या बहुत अधिक थी। क्योंकि पानी की पाइपलाइन मानक लाभ जो की ग्राम सुरपुरा से 25 किलोमीटर दूरी पर है वहां से सप्लाई होता था जो की पूरी तरह से नहीं हो पाता था, जिससे ग्रामवासियों को पूरा पानी नहीं मिल पाता था और गर्मियों में समस्या काफी ज्यादा हो जाती थी। जोकि बहुत बड़ी समस्या थी ग्रामवासियों को पानी के टैंकर मंगवा कर जल आपूर्ति करवानी पड़ती थी।

ग्राम पंचायत ने उपलब्ध फंड से पंप हाउस का निर्माण करवाया, जिसमें मनकलाव से आने वाली पाइपलाइन पर उसे लगाकर पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामवासियों ने ली एक समय सारणी तैयार की गई तथा सारणी के अनुरूप प्रत्येक बस्ती मोहल्ले पानी की सप्लाई प्रारंभ की और पानी घर में पहुँचने लगा, टैंकर से राहत मिली। भीषण गर्मी में भी अब पानी की कमी की समस्या नहीं रहती।

ग्राम पंचायत की प्रमुख नदी को सभी ग्रामवासियों व जन सहयोग एवं भामाशाह की सहायता से उसका कायाकल्प किया गया सर्वप्रथम खुदाई का कार्य प्रारंभ कर पानी के बराबर क्षमता को बढ़ाया गया, जिससे नरेगा में ग्रामीणों को आर्थिक सहायता के साथ नदी के सौंदर्य निखर को प्रखर किया गया नदी में पानी के आवक क्षमता को बढ़ाया ताकि पानी का उपयोग पशुओं को पीने एवं अन्य जरूरत के लिए हो सके।

नदी की पाल की चारों तरफ से पाल बंधाई का कार्य कर वहां पर वृक्षारोपण का कार्य करने से नदी में पानी की क्षमता में बढ़ोतरी हुई। भूमिगत पानी की गुणवत्ता की जाँच हेतु ट्यूबवेल की खुदाई की गई, जिसमें भूमिगत पानी का उपयोग खेल मैदान में उद्यान विकास का कार्य किया गया तथा खेल मैदान में 200 से अधिक वृक्षारोपण किया गया। गाँव की कुल जनसंख्या लगभग 3,420 है। लोगों को इन कार्यों का लाभ मिला।

जल संरक्षण के मंच पर गोदावरी प्रवाह की तरह यात्रा जारी है...

चिन्मय उदगीरकर
नासिक, महाराष्ट्र
सचिव, नमामि गोदा

एक दशक से अधिक समय से वे गोदावरी नदी के संरक्षण और कायाकल्प के लिए समर्पित हैं। गोदावरी और उसकी सहायक नदियों को बहाल करने के प्रयासों में प्रदूषण को कम करने, वनीकरण, नदी के किनारों की सफाई और नदी के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित किया। यह यात्रा जारी है...

सोलापुर जिले के सांगली तालुका में कासलगंगा परियोजना के ब्रांड एंबेसडर के रूप में काम किया, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान अर्जित की। इस अभूतपूर्व पहल में एक मौसमी धारा को बारहमासी नदी में बदला गया और इससे स्थानीय समुदाय के लिए एक स्थायी जल स्रोत को बनाया जा सका। जन भागीदारी को बढ़ाने और जमीनी प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय आबादी के लिए पानी की कमी के दबाव वाले मुद्दे को प्रभावी ढंग से हल किया गया, जिससे बेहतर आजीविका और कृषि विकास संभव हुआ। इससे वनीकरण हुआ और पर्यावरण संरक्षण भी संभव हुआ।

कोपर गाँव : गोदावरी नदी की सफाई के लिए सतत प्रयास जारी हैं। नदी की सफाई के लिए युवाओं के साथ मिलकर पिछले पांच वर्षों से निरंतर समुदाय-संचालित क्रियाकलाप करते हुए प्रदूषण को कम करने और नदी की पवित्रता को बहाल करने के लिए काम कर रही है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी गोदावरी नदी के कायाकल्प प्रयासों को सम्मानित किया गया। सरकारी योजना, चला जनुया नदीला (चलो नदी से जुड़ें) के ब्रांड एंबेसडर: यह महाराष्ट्र सरकार और डॉ. राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में जल बिरादरी की एक संयुक्त पहल है, जिससे पूरे राज्य में नदी संरक्षण पर व्यापक ध्यान आकर्षित किया है।

अभिनव जल संरक्षण परियोजना : मेरा जल बैंक

पानी की कमी से निपटने और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए मेरा जल बैंक पहल शुरू की। सरल, किफायती वर्षा जल संचयन समाधान ने घरों को स्थायी जल प्रबंधन में योगदान करने के लिए सशक्त बनाया है।

ब्रह्मगिरी कायाकल्प : गोदावरी की पवित्रता के लिए एक दृष्टि

ब्रह्मगिरी की हरियाली, गोदावरी की पवित्रता के लिए ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर पौधारोपण, मिट्टी के कटाव को रोकने और गोदावरी के अविरल प्रवाह को सुनिश्चित करने तथा क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने पर है।

अविरल गोदावरी में बारहमासी प्रवाह हो इसके लिए पूर्णतय सक्रिय :

इन कार्यों से हजारों व्यक्तियों और समुदायों को महत्त्वपूर्ण रूप से लाभान्वित किया है। गोदावरी नदी के संरक्षण के उनके प्रयासों ने नासिक में पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार किया है, जबकि नमामि गोदा के सहयोग से 2015-16 के नासिक कुंभ मेले को हरित कुंभ में बदलने से लाखों लोगों तक पहुँच बनाई, जिससे स्थिरता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिला। कासलगंगा परियोजना के ब्रांड एंबेसडर के रूप में उन्होंने सोलापुर जिले में एक स्थायी जल स्रोत प्रदान किया जा सका, जिससे आजीविका और कृषि में वृद्धि हुई। इगतपुरी में उनके वृक्षारोपण अभियान में 15,000 से अधिक पेड़ लगाए गए, जिससे युवाओं को पर्यावरण संरक्षण में शामिल किया गया। कोपर गाँव में गोदावरी को साफ करने के उनके पाँच साल के प्रयासों ने स्थानीय समुदायों के लिए नदी की शुद्धता को बहाल किया।

LET US COME
TOGETHER FOR
LET US COME
TOGETHER FOR

Conclave on

मेहश्वर नदी के पानी से बागी हुए किसान, बंदूक की जगह हाथों में आए फावड़े

छोटेलाल मीणा
जल बिरादरी
करौली, राजस्थान

करौली की महेश्वर नदी में पानी आया तो इलाके के बागी भी बंदूक छोड कर जल संरक्षण में जुट गए और आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं, जल संरक्षण कार्य कर रहे हैं;

जिला करौली ग्राम पंचायत में निभैराके अंतर्गत गाँव खजुरा में महेश्वर नदी क्षेत्र में यहाँ के समुदाय के साथ मिलकर जल संरक्षण का कार्य किया गया। लगभग 108 पगारा पोखर तथा बांध बनाकर लोगों के आर्थिक जीवन स्तर में सुधार हुआ। इसके बनने से इस क्षेत्र की महेश्वर नदी पुनर्जीवित होकर सदानीरा हो गई। यहाँ बांध व जोहड़ बनने से इस इलाके में जो लोग अपने खेती बाड़ी छोड़कर बागी हो गए थे और बंदूक के सहारे लूट खसोट कर लोगों को डरा धमका कर अपना जीवनयापन करने पर विवश हो गए थे वे लोग बदलने लगे।

संपर्क में आने पर, जिन हाथों में बंदूक थी उन हाथों में फावड़ा थमा दिया, उन्हें जल संरक्षण के काम में लगा दिया। जो बागी होकर जंगल में डकैत की बदहाल जिंदगी जीने पर विवश थे वे आज अपने परिवार के साथ रहकर सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। अपनी खेती कर रहे हैं आत्मनिर्भर हो गए हैं।

हालांकि यह काम उतना आसान नहीं था। जल संरक्षण कार्य करते-करते, बागियों ने दो-तीन बार बहुत परेशान किया। डराया-धमकाया एक बार अपहरण कर लिया। मुझे यहाँ से भाग जाने या मार देने की धमकी देते थे। लेकिन मैंने जो यहाँ काम किया उससे उन लोगों को गेंहू की रोटी नसीब हुई, जिन्होंने कभी गेंहू की रोटी नहीं खाई थी आज वह अपनी खेती करके तीन-तीन फसले काट रहे हैं।

जल संरक्षण, जल स्रोतों को बनाने के कार्य से 108 जल संरचनाएं बना सके, जिससे लगभग 55 कुंए रिचार्ज हुए तथा हजारों बकरियों, भैंसों, जंगली व पालतू जानवरों के साथ साथ ग्रामवासियों को भारी संख्या में पानी मिल पाया। सिंचाई व्यवस्था सही हुई इससे सैंकड़ो बीघा में खेती की जा रही है और लोगों की आमदनी में चार गुना इजाफा हुआ है।

एक ग्राम, जिसका दुनिया देख रही है काम

दिनेश बिश्नोई
सरपंच, ग्राम पंचायत
जोधपुर, राजस्थान

जोधपुर में सुरपुरा एक छोटा सा गाँव है जो नेशनल हाईवे 67 के पास बसा हुआ है। सुरपुरा अपने प्राचीन स्थापत्य एवं कृषि के लिए प्रसिद्ध है उक्त ग्राम पूरी तरह से कृषि प्रधान होने के कारण पानी के महत्त्व पर ग्राम विशेष रूप से केंद्रित है।

सरपंच दिनेश बिश्नोई ने पूर्व सरपंच जुगता राम द्वारा शुरू करवाए जल संरक्षण को बढ़ावा दिया और परिणाम दिखने लगे। ग्राम पंचायत सुरपुरा को वर्ष 2023-24 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के अंतर्गत ढाँचागत आत्मनिर्भर पंचायत के अंतर्गत एवं सुशासन युक्त पंचायत के अंतर्गत पूरे जिले में प्रथम पुरस्कार का एवं गरीबी मुक्त आजीविका में द्वितीय पुरस्कार एवं स्वास्थ्य पंचायत अथवा हरित पंचायत में तीसरा स्थान प्राप्त कर मंडोर पंचायत समिति को गौरवान्वित किया। जल संरक्षण एवं पानी के महत्त्व को बढ़ावा दिया, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा 2023 में पंप हाउस का निर्माण करवाया गया जोकि पूरे जिले में उदाहरण के रूप में सामने आया। ग्राम सुरपुरा में पंप हाउस निर्माण से पूर्व पानी की समस्या बहुत अधिक थी, क्योंकि पानी की पाइपलाइन मानक लाभ जोकि ग्राम सुरपुरा से 25 किलोमीटर दूरी पर है वहां से सप्लाई होता था जो की पूरी तरह से नहीं होता था, जिससे ग्रामवासियों को पूरा पानी नहीं मिल पाता था और गर्मियों में समस्या बिकराल हो जाती थी। ग्रामवासियों को पानी के टैंकर मंगवाना पड़ते थे।

इस समस्या का समाधान करने के लिए नवाचार प्रयोग किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सभी ग्रामवासियों की सहमति लेकर पंचायत के फंड से कम से कम लागत में पंप हाउस का निर्माण करवाया गया, जिसमें मनकलाव से आने वाली पाइपलाइन पर उसे लगाकर पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामवासियों ने ली। एक समय सारणी तैयार की गई तथा सारणी के अनुरूप प्रत्येक बस्ती मोहल्ले के पानी की सप्लाई प्रारंभ की गई, जिसमें मानक लव से आने वाली पाइपलाइन को पंप हाउस तक लाकर फिर अलग-अलग बस्तियां में सप्लाई की गई। इससे पानी हर घर पहुँचा। पंप हाउस बनाने से आज सुरपुरा ग्राम में भीषण गर्मी में भी पानी की कमी की समस्या नहीं रहती है सुरपुरा पंप हाउस की तर्ज पर प्रत्येक ग्राम में पंप हाउस बनाने की इस नवाचार की संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा घोषणा की गई तथा विभिन्न अधिकारियों द्वारा पंप हाउस का निरीक्षण कर पंचायत को गौरवान्वित किया गया। जल संसाधन को बढ़ावा देने के क्रम में ग्राम पंचायत की प्रमुख नदी को सभी ग्रामवासियों व जन सहयोग एवं भामाशाह की सहायता से उसका कायाकल्प किया गया। नरेगा योजना के अंतर्गत नाडी खुदाई का कार्य प्रारंभ कर पानी के बराबर क्षमता को बढ़ाया गया, जिससे नरेगा में ग्रामीणों को आर्थिक सहायता के साथ नदी के सौंदर्य निखारा गया और इससे नदी में पानी की आवक क्षमता बढ़ी।

Latitude : 26.383895°
Longitude : 73.0924666666667°
Altitude : 231.6 meters
Date : 19/08/22 02:20 pm
Note : पम्प हाऊस सुरपुरा

पानी से मिला रोजगार, कृषि, व्यापार, इको टूरिज्म एवं धरती हुई पानीदार

गौरंग राठी, आईएएस
जिलाधिकारी, भदोही
उत्तर प्रदेश

भदोही के विकास खंड ज्ञानपुर के ग्राम पंचायत सोबरी में प्रवेश करने वाली मोरवा नदी विभिन्न ग्राम पंचायतों से होकर बहती है और अंततः वरुणा नदी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे किए गए विकास कार्यों से न केवल जल संसाधनों में वृद्धि हुई है बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा हुए।

मोरवा नदी 43.80 किमी लंबी, जिले की 46 ग्राम पंचायतों से गुजरती है। नदी के किनारे बसे गाँवों के लिए यह पानी का मुख्य स्रोत है, इससे कृषि, घरेलू उपयोग, पशुपालन के लिए पानी मिलता है। मनरेगा योजना में खुदाई और जीर्णोद्धार कार्य किए और 31 ग्राम पंचायतों को शामिल किया। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-24 तक इस परियोजना में कुल 44.750 किमी क्षेत्र में कार्य कराया गया है, जिसमें 5.17 करोड़ रुपये खर्च हुए। परियोजना के तहत 3,25,700 मानव दिवस सृजित किए गए। इन कार्यों से स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर मिले। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को मजदूरी करने का अवसर मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस परियोजना से न केवल आर्थिक लाभ हुआ है, बल्कि सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा मिला है।

मोरवा नदी में जीर्णोद्धार कार्यों से किनारों पर वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण और जल स्तर बेहतर हुआ। ये कार्य नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करते हैं और स्थानीय जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद करते हैं। मोरवा नदी में जीर्णोद्धार कार्यों से भी जल संरक्षण हुआ, सफाई और खुदाई से पानी का प्रवाह बेहतर हुआ, कई जल स्रोत पुनर्जीवित हुए। इससे न केवल पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ती है, बल्कि सिंचाई के लिए भी पानी की उपलब्धता बढ़ती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में स्रोत नदी के कार्य की सराहना से प्रेरित होकर तथा मोरवा नदी के जीर्णोद्धार से जल संरक्षण व नये जल स्रोतों के सृजन में मिली सफलता से अब कल्याणी नदी जनपद उन्नाव के पुनरुद्धार पर भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। अमृत सरोवर कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में अब तक 255 अमृत सरोवर बनवाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिनमें औसतन 3,38,252 घनमी. जल संचयन क्षमता की वृद्धि हुई है। अस्सी नदी के पुनरुद्धार कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा पूर्व में सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त वाराणसी शहर में 6 तालाबों का पुनरुद्धार कर इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया। इन कार्यों से आम जन सामान्य के साथ ही पालतू पशुओं व जंगली पशु-पक्षियों को लाभ हुआ। अमृत सरोवर से लगभग 1,400 स्रोत पानीदार हुए एवं नदी के जीर्णोद्धार से 100 से अधिक पानीदार स्रोत हुए तथा लगभग 75,000 लोगों को पानी उपलब्ध हुआ।

अटल अमृत सरोवर

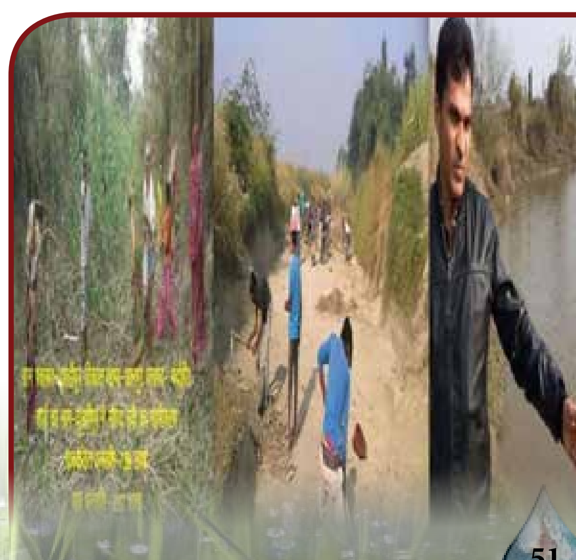

मथुरा, पालघर में इस्कॉन श्रद्धालुओं, क्षेत्रीय किसानों को पानी उपलब्धता के लिए सक्रिय

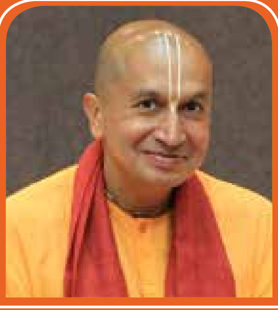

गौरंग दास
निदेशक, गोवर्धन इकोविलेज
पालघर, महाराष्ट्र

इस्कॉन, मथुरा, पालघर में जल संचयन के प्रयासों में जन भागीदारी के साथ लक्ष्य हासिल किए गए। वैज्ञानिक भारतीय फार्मूले से किए प्रयास सफलता की गाथा कह रहे हैं।

पालघर जिले के गोवर्धन इकोविलेज में वर्षा जल संचयन पहल ने अपने परिसर में 9 करोड़ लीटर की क्षमता वाला वर्षा जल संचयन तालाब बनाया है। पुराना तालाब एक करोड़ लीटर का था जो 6-7 साल पुराना था और पानी को संग्रहित करने के लिए उस पर प्लास्टिक की तिरपाल लगी हुई थी। शुरुआत में, तालाब का निर्माण वनीकरण और कृषि उद्देश्यों के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया। समय के साथ, प्लास्टिक कवर पर लगभग एक फुट की तलछट जम गई। इसलिए, प्लास्टिक को हटाकर तालाब को गहरा किया और नौ करोड़ लीटर का नया तालाब बनाया गया ताकि कुल 10 करोड़ लीटर हो जाए।

इस परियोजना ने गोवर्धन इको विलेज में भंडारण क्षमता कम से कम 80 लाख लीटर बढ़ गई, जिससे भूजल स्तर बढ़ा, कुंओं में पानी आया और आसपास के लोगों को लाभ मिला। यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, जिससे पानी साफ कर के बागवानी के काम में लिया और पेयजल को बचाया जा सका। बृज, मथुरा जिले में जल निकायों का पारिस्थितिकी पुनरुद्धार मई 2022 में 16 जल निकायों के साथ बृज तीर्थ विकास परिषद (बीटीवीपी) की अनुमति से शुरू किया गया। ड्रोन सर्वे कर जल और तलछट से नमूने, आंकड़े जुटाए और फिर 16 जल निकायों में से लगभग 70 प्रतिशत जल निकायों में सी ग्रेड का पानी है और बाकी में बी ग्रेड का पानी है। सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ए ग्रेड का पानी पीने के लिए अच्छा है, बी ग्रेड का पानी नहाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि सी ग्रेड के पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए।

इसके बाद एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। फरवरी 2023 में 6 जल निकायों के इको-कायाकल्प के लिए काम शुरू करने की पूरी अनुमति दी गई। फरवरी 2023 में एक जल निकाय-प्रिया कुंड से काम शुरू किया, ताकि अवधारणा का प्रमाण स्थापित किया जा सके और 6-8 महीने की अवधि में विभिन्न स्थायी पहलों के साथ पानी सुधारा जा सका। यह प्रयास सदैव बने रहें इसके लिए एक सफल शासन तंत्र बनाया व स्थानीय बृजवासियों को कुंड मित्र नियुक्त किया। ये मित्र नियमित रूप से इन जल निकायों की निगरानी करते हैं और आगंतुकों को शिक्षित और जागरूक भी करते हैं।

इसके कारण, जल निकायों के रासायनिक, जैविक और जीवाणु संबंधी गुण स्थिर बने हुए हैं। स्वदेशी घास लगाने, स्थानीय संस्कृति से जुड़ी सुंदर पेंटिंग बनाने, होर्डिंग और क्या करें और क्या न करें का उल्लेख करने वाले लेखों के माध्यम से आसपास के क्षेत्र के सौंदर्य को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा हैं। गोवर्धन इकोविलेज में जल संरक्षण की पहल से 8000 से अधिक किसानों को सालाना जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। करीबन 12 लाख मिलियन ग्रामीणों को सालाना मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं 100 से अधिक गायों, घोड़ों, भेड़ों, बकरियों और गधों की देखभाल की जा रही है। यहाँ सालाना 10 लाख से अधिक आगंतुकों के लिए इको-टूरिज्म हेतु जल आवश्यकताओं को भी सपोर्ट करता है। मथुरा जिले में जल निकायों के पुनर्जीवित होने के बाद इलाके के लगभग 15,700 लोगों को पानी मिला।

2022
2023

आइये
कुंड-मित्र बनें!
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Before
After

गन्ने की पैदावार भी बचा रही है पानी

इंदर विक्रम सिंह, आईएएस
जिलाधिकारी
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

कुओं, तालाबों पर निर्भरता, अपर्याप्त वर्षा, अस्थिर जल उपयोग विधियों से हर दिन पानी की चुनौतियां बढ़ रही हैं। आखिर प्रभावी जल संरक्षण रणनीति क्या हो, कैसे काम करें, इसी दिशा में कई पहल रंग ला रही हैं

गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने कई जल संरक्षण पहलों को लागू किया, जिनमें शामिल हैं, वर्षा जल संचयन : यह रणनीति मजबूत प्रणाली बनकर उभरी और वर्षा जल संचयन की स्थापना को बढ़ावा दिया गया। ग्रामीण गाजियाबाद में गाँवों की 350 से अधिक सरकारी इमारतों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाई गई।

जन जागरूकता अभियान : जल संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान समुदायों को स्थायी जल उपयोग और प्रबंधन के महत्त्व के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। भूजल सप्ताह-(16 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक), कार्यशालाएँ, एक्जिबिशन, जल संचयन, कुशल सिंचाई विधियों पर चर्चा की, सूचनात्मक सामग्री का वितरण किया गया। स्कूलों, सामुदायिक समूहों के सहयोग से इंटरैक्टिव चर्चा की गई।

गन्ने की खेती में ड्रिप सिंचाई : ड्रिप सिंचाई अपनाने से जल संरक्षण में महत्त्वपूर्ण कामयाबी मिली। इससे पौधों की जड़ों तक सीधे पानी पहुँचता है, वाष्पीकरण और अपवाह कम होता है। गाजियाबाद के 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके, जहां गन्ने की खेती की जाती है, किसानों का पारंपरिक सिंचाई विधियों की तुलना में पानी का उपयोग 50 प्रतिशत तक कम हुआ है। ड्रिप सिंचाई के उपयोग ने दालों, सब्जियों व तिलहन जैसी फसलों के विविधीकरण को प्रोत्साहित किया है, जिससे कृषि स्थिरता और किसानों की आय दोनों में वृद्धि हुई है।

जल स्रोतों का पुनरुद्धार : जिला भूजल प्रबंधन समिति ने ग्रामीण गाजियाबाद में 908 जल निकायों की पहचान की और उनके क्लस्टर बनाए। चूंकि मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत गाजियाबाद के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है, इसलिए इन जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को बनाए रखना और प्रबंधित करना मुश्किल था। एनसीआर क्षेत्र में आने वाला गाजियाबाद विभिन्न उद्योगों के लिए बसने का द्वार खोलता है। उद्योग अक्सर विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए बड़ी मात्रा में भूजल उपयोग करते हैं, जिससे जलस्रोतों में कमी आती है और कृषि और घरों के लिए पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। विभिन्न कंपनियों को नामांकित किया तथा उनके साथ बैठकें आयोजित कीं। बैठक के पश्चात इन जल निकायों के समूहों को इन कंपनियों को आवंटित किया गया तथा एक एसओपी तैयार की गई, जिसके अंतर्गत सबसे पहले कंपनियों तथा संबंधित ग्राम पंचायतों के बीच एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया, तालाबों से जल निकालने, तालाब के किनारों तथा तलहटी की सफाई एवं खरपतवार निकालने, किनारों/परिधियों का निर्माण, तालाब के चारों ओर आरसीसी पोल एवं तार द्वारा बाड़बंदी, डिस्प्ले बोर्ड एवं खंभों की पेंटिंग, तालाबों के चारों ओर वृक्षारोपण तथा सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए जैव उपचारात्मक उपाय सहित मानक अनुमान तैयार किए गए। वर्तमान में 116 विभिन्न कंपनियां इन चिन्हित जल निकायों के पुनरुद्धार पर काम कर रही हैं।

अमृत सरोवर योजना में जिले को 75 जल निकायों की पहचान कर उनका पुनरुद्धार करना था, गाजियाबाद जिले ने 105 जल निकायों की पहचान की और उनमें से 100 का पुनरुद्धार किया। भविष्य में पुरानी जल निकासी प्रणाली, कुओं, धाराओं, नदियों को पुनर्जीवित करने और जलग्रहण क्षेत्रों की अतिक्रमित भूमि को पुन: प्राप्त करने के लिए प्रशासन काम कर रहा है। जीआईजेड जर्मन के माध्यम से नदी, तालाब, वनीकरण भूमि, हिंडन और यमुना नदी की लुप्त सहायक नदियों की पहचान की जानी है। इसके साथ ही गाजियाबाद जिले का जीआईएस आधारित विश्लेषण इस दिशा में उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

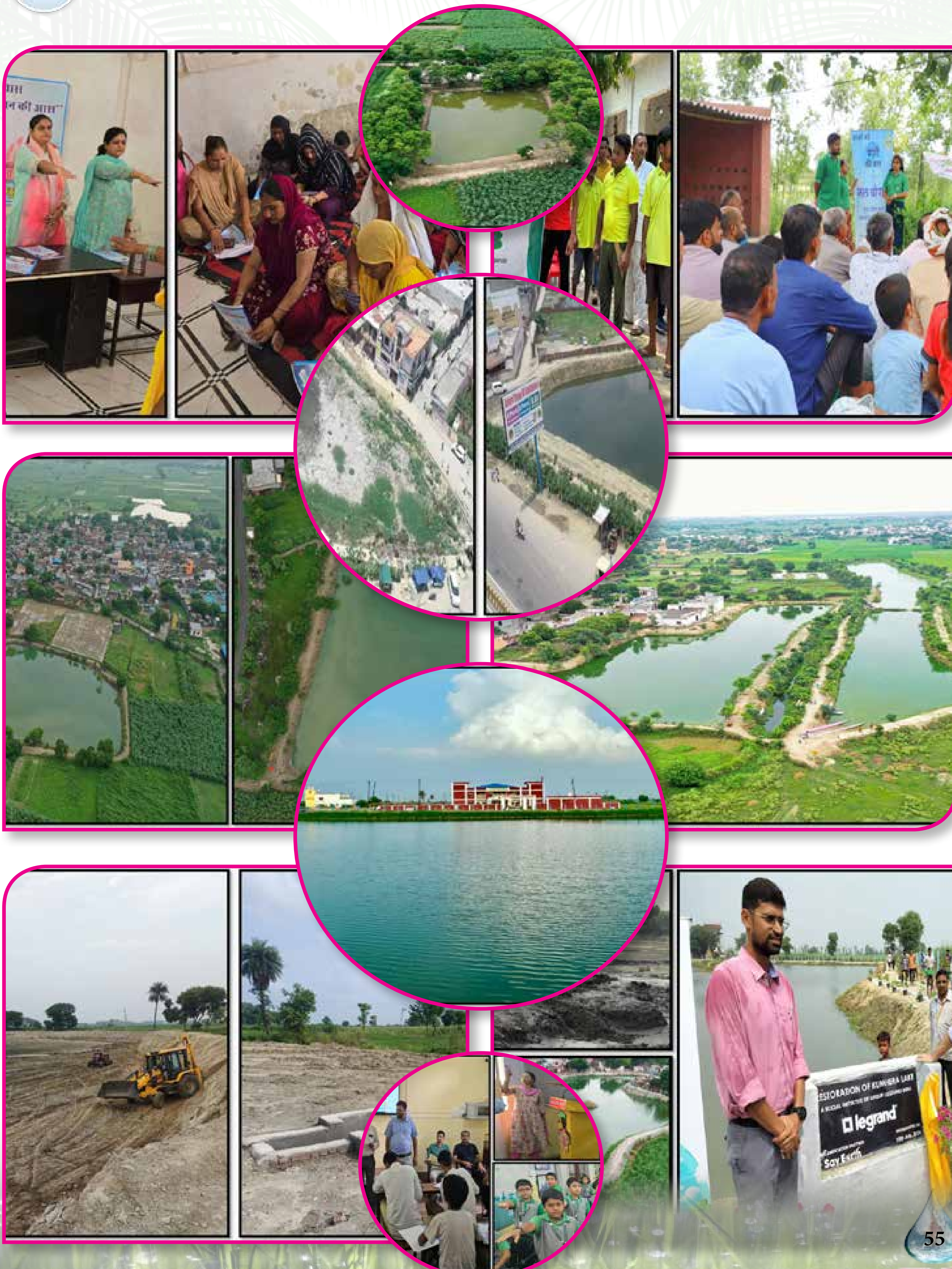
legrand

Climate change destroying our health and wealth, Community-Centric Approach, Student Engagement making reach

KAILASH KARTHIK N., IAS
Secretary
(Phe Department) &
Mission Director
(JJM-Assam)

Through the active involvement of students as "Jaldoots" or "Water Messengers," the initiative fosters a culture of sustainability, helping bridge communication between communities and the government toward the shared goal of ensuring safe water access for all.

The Jaldoot Programme, an innovative initiative under Assam's JJM, is revolutionizing communities by empowering students to champion safe water conservation, sanitation, and hygiene practices. Designed for students from classes 8 to 12, the programme encourages young people to assess and advocate for efficient functioning of Piped Water Supply Schemes in their localities.

Community-Centric Approach and Student Engagement

The Jaldoot Programme takes a community-centered approach to water conservation by engaging students in a two-day interactive workshop called Jalshala. Students, typically aged 12 to 16, undergo mentorship from trained facilitators and coordinating teachers, covering essential topics such as sustainable water management, conservation, sanitation, and hygiene. The sessions emphasize hands-on learning, guiding students in mapping local water resources, assessing community water needs, and identifying practical, sustainable solutions to local water issues. This peer-based approach, grounded in real-world scenarios, inspires students to find creative solutions and positions them as advocates for water conservation within their communities.

Innovation in Action: Water Aerators from Plastic Bottles

A highlight of the programme's impact is the water aerator project, where Jaldoots have creatively repurposed plastic bottles to reduce water wastage. Using discarded plastic bottle caps, students crafted makeshift aerators that attach to taps, controlling water flow to minimize leaks and reduce usage. This resourceful, low-cost innovation not only conserves water but also emphasizes recycling and reuse, demonstrating how small, accessible changes can make a meaningful environmental impact. The success of the water aerator project has resonated across districts, with many schools and households replicating the design, amplifying its positive effects.

Building on Technology and Sustainable Engagement

To sustain momentum beyond training sessions, the Jaldoot Programme leverages technology to keep students engaged. A specially designed WhatsApp chatbot serves as a primary tool, enabling students to stay connected with conservation tasks and updates. Coordinating teachers facilitate student interaction with the chatbot, which provides weekly challenges, conservation tips, and reminders, turning water-saving practices into regular habits. By using WhatsApp, a widely accessible platform, the

program ensures that students remain involved in water conservation efforts long after their initial training. Beyond digital engagement, the program organizes JalAdda, an alumni meet where the top 40 Jaldoots from each district gather to share insights and brainstorm new ideas. These gatherings encourage peer learning and strengthen a network of student advocates for sustainable water use. JalAdda participants present their projects and discuss challenges, fostering an environment of continuous learning and inspiring innovation in water conservation practices.

Success in Majuli: A Model District for the Jaldoot Programme

The island district of Majuli, known for its unique geographical challenges, stands out as a success story of the Jaldoot Programme. In Majuli, Assam, the world's largest river island, the local community faced a significant challenge. They were unaware of the quality of their drinking water despite an apparent abundance. Jaldoots from Ratanpur High School stepped forward to tackle this issue. Motivated by the increasing threat of water-borne diseases, they launched dynamic awareness campaigns, utilizing street plays and rallies within their school premises to educate their peers and the wider community. Their efforts quickly drew the attention of government bodies, resulting in a collaborative campaign to enhance water quality awareness across Majuli. Initiatives like these from the Jaldoots not only received media attention but also led to the recognition of the Jaldoot Programme as a National Policy by the Government of India. The success in Majuli illustrates how youth-led conservation efforts can influence systemic change, even in challenging terrains, making it a model district for the Jaldoot Programme. Practical Tips and Actions for Sustainable Water Conservation To promote sustainable water use in day-to-day life, the Jaldoot Programme provides students with practical conservation tips. These include simple actions like fixing leaks, using buckets instead of running taps, and reusing greywater for gardening. Schools are encouraged to incorporate these practices into daily routines, helping students form water-saving habits that extend to their families and communities.

घर में रहे घर का पानी, रेगिस्तान में पैदल न चले न घर की बेटी, न बहूरानी

श्रीमती कनुप्रिया हरीश
कार्यकारी निदेशक
जल भागीरथी फाउंडेशन
जयपुर, राजस्थान

जल स्रोत पुनर्जीवित करके, उससे हमेंशा पानी मिलता रहे, यह जल संसाधन प्रबंधन बिना ग्रामीण समुदाय भागीदारी मुश्किल है, राजस्थान के कई इलाकों में जेबीएफ यह पिछले 22 वर्षों से कर रहे हैं; 800 गाँवों के काम देख यूएनडीपी और इतालवी विदेश मंत्रालय ने पानी उपलब्धता बढ़ने की रिपोर्ट दी, जलसंकट के दिनों में 3 से 5 महीने की कमी आई है, महिलाओं को हर रोज 3-4 किलोमीटर पैदल चलने की थकान से बचाया और पानी की खरीद पर होने वाले खर्च में 140 प्रतिशत की बचत हुई है, गरीब पर इसकी मार बची।

स्थानीय परिस्थितियों के लिए विशिष्ट एक अभिनव समुदाय के नेतृत्व वाली एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली विकसित कर प्रत्येक गाँव को एक अद्वितीय बॉटम-अप दृष्टिकोण के माध्यम से वर्षा जल को संग्रहीत और वितरित किया। सहभागी उपकरणों का उपयोग करके जल सभाओं के रूप में जानी जाने वाली ग्राम स्तरीय संस्थाओं को उनकी जल संचयन प्रणालियों का प्रबंधन करने की सुविधा दी। सभी परियोजनाओं में एक अद्वितीय वित्तपोषण तंत्र है, वे समुदाय द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित हैं, जो सामुदायिक स्वामित्व की भावना पैदा करते हैं और दीर्घकालिक स्थिरता को प्रोत्साहित करते हैं। संगठन उन क्षेत्रों में काम करता है जहाँ सतही जल स्रोतों का अभाव है, भूजल खारा है और इसलिए पीने योग्य नहीं है। सरकारी जल आपूर्ति योजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता हैं जो राज्य की सीमाओं के पार पहुँचाए गए पानी पर निर्भर हैं। इन योजनाओं की स्थिरता जलवायु परिवर्तन से चुनौती बन रही है, क्योंकि जल-दाता राज्य खुद एक आसन्न जल संकट का सामना कर रहे हैं। राजस्थान में बिखरे हुए आवास पैटर्न के कारण जहाँ लोग ढाणियों (छोटी बस्तियों) में रहते हैं, सरकारी जल योजनाएं बड़ी आबादी तक पहुँचने में असमर्थ हैं। पीने के पानी की कमी समुदायों पर आर्थिक बोझ है, क्योंकि उन्हें पानी खरीदना पड़ता है, जिसे दूर-दूर से टैंकरों के माध्यम से लाया जाता है।

महिलाएँ प्राथमिक हितधारक हैं जो जल संकट से सबसे अधिक प्रभावित हैं। वे अपने जीवन का एक तिहाई हिस्सा पानी इकट्ठा करने में बिताती हैं, चिलचिलाती धूप में प्रतिदिन 4 किलोमीटर तक पैदल चलती हैं। पानी की कमी के कारण न केवल महिलाओं और लड़कियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि शिक्षा और अन्य उत्पादक कार्यों के लिए समय की कमी के कारण बहुत बड़ा अवसर लागत भी होती है। वर्षा जल संचयन सबसे उचित साधन है। जेबीएफ ने जल प्रबंधन का एक अभिनव मॉडल विकसित किया है, जिसे स्थानीय भाषा में जल सभा कहते हैं जो ग्रामीण खुद चलाते हैं। एक समुदाय संचालित जल प्रबंधन प्रणाली तैयार की गई है, जिसमें तालाब (गाँव के तालाब), नाडी (घास के मैदान के तालाब), बेरी (उथले रिचार्ज कुएं) जैसी जल संचयन संरचनाओं का एक मैट्रिक्स बनाया गया है और उनका जीर्णोद्धार किया गया है।

जलग्रहण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया जाता है ताकि वर्षा जल का अधिकतम संग्रह हो सके, जिसमें जलग्रहण क्षेत्रों को जल संचयन तालाबों से जोड़ने के लिए चैनलों का निर्माण किया ताकि पूरे साल पानी मिले। साथ ही, कम वर्षा के दौरान भी अधिकतम संचयन सुनिश्चित करने के लिए जलग्रहण क्षेत्रों की दक्षता में सुधार किया जाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन अनुकूल हो जाता है। इस प्रणाली को घरेलू स्तर पर भूमिगत टैंक (जिन्हें टंका के नाम से जाना जाता है) से पूरित किया जाता है, जो वाष्पीकरण के कारण होने वाले नुकसान को कम करते हुए पानी को घर के करीब लाता है। इन टैंकों में भंडारण को छत के ऊपर जल संचयन के माध्यम से बढ़ाया जाता है। बच्चों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इमारतों से पानी इकट्ठा करने और संचय करने के लिए गाँव के स्कूलों में भी टंका बनाए जाते हैं।

पिछले 22 वर्षों में संगठन ने विभिन्न प्रकार के वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के साथ लगभग 800 गाँवों में काम किया। यूएनडीपी और इतालवी विदेश मंत्रालय द्वारा किए गए बाहरी मूल्यांकनों ने बताया कि जेबीएफ परियोजना वाले गाँवों में पानी की उपलब्धता बढ़ गई है, जल संकट के महीनों में 3 से 5 महीने की कमी आई है, महिलाओं को हर रोज 3-4 किलोमीटर पैदल चलने की थकान से बचाया गया है और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पानी की खरीद पर होने वाले खर्च में 140 की बचत हुई है, जिसका गरीबी में कमी पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।

During
After

अतिक्रमण से भूजल स्तर में सुधार के लिए कई प्रयासों की ओर अग्रसर...

मनीष वर्मा, आईएएस
जिला मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

गौतमबुद्ध नगर में 1018 जल स्रोत हैं। इसमें से लगभग 208 जल निकायों पर अतिक्रमण हो गया या रेल या सड़कें बना ली गईं। अतिक्रमण खत्म करने के लिए जो प्रयास शुरू हुए और सौ फीसदी मामले दर्ज कर उनसे कब्जे वापस लेकर जल को जीवन से जोड़ दिया...

गौतमबुद्धनगर में 3 तहसील हैं, इनमें कब्जा करने वालों पर 15 मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार धारा 67 के तहत 100 फीसद मामले दर्ज किए गए, जिसमें सदर में 245 तालाब पर 48 पर कब्जे, 383 मामले दर्ज किए गए तथा 339 मामलों में बेदखली आदेश हुए, जिनमें 4.9059 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई जानी अपेक्षित थी, जबकि शेष 14 मामलों में कार्यवाही प्रगति पर है। जेवर में 293 तालाबों में से 29 तालाबों पर अतिक्रमण किया गया था। इसमें 168 मामले दर्ज हुए, 143 मामलों में बेदखली नोटिस हुए, 2.1579 हेक्टेयर भूमि मुक्त हुई। केवल 25 मामले लंबित हैं, जिनका यथाशीघ्र समाधान कर लिया जाएगा। दादरी में 480 तालाब हैं, जिनमें से 134 पर अतिक्रमण किया गया था, जिनमें 283 मामले दर्ज किए गए तथा 238 मामलों में बेदखली नोटिस पारित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 3.6956 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हुई। शेष 45 मामले भी प्रगति पर हैं।

'कैच द रेन' अभियान से नोएडा में जल संरक्षण : गौतमबुद्ध नगर ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भूजल स्तर और वर्षा जल संचयन में सुधार के लिए 'कैच द रेन अभियान' के महत्त्व पर जोर दिया। पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार, बोरवैल को रिचार्ज करना, वाटरशेड विकसित करना, सघन रूप से पेड़ लगाना और छोटी नदियों का जीर्णोद्धार करना लक्ष्य है। सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी भवनों पर छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने और सभी अमृत सरोवरों में जल प्रवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर कार्य जारी है। सरकारी कार्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली अनिवार्य है। शहरी पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर भी प्रभावी वर्षा जल संचयन उपाय लागू हैं। राजस्व विभाग, नगर निकायों और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अतिक्रमण किए गए तालाबों को सूचीबद्ध करें और उनका समय पर जीर्णोद्धार सुनिश्चित करें। विभिन्न विभागों को जल संरक्षण योजना तैयार करने और पूर्ण किए गए कार्यों का जियो-टैग्ड दस्तावेज गौतम बुद्ध नगर के विकास भवन में सहायक अभियंता, लघु सिंचाई को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

गौतमबुद्ध नगर में 1.25 प्रतिशत अधिक तालाब और अमृत सरोवर विकसित करे, जिले में 2-2.25 हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले जल निकायों की वर्तमान स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई है ताकि तालाबों और अमृत सरोवरों का जीर्णोद्धार ठीक से किया जा सके। वन विभाग के अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अतिक्रमण किए गए तालाबों का पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार सुनिश्चित करें और हिंडन नदी के किनारों पर वृक्षारोपण की भी संस्तुति की गई है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले भर में 1,018 जलाशय पंजीकृत हैं। वन विभाग को तालाबों और हिंडन नदी के किनारे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया। भूजल प्रदूषण को रोकने के लिए तालाबों में प्रवेश करने वाले अपशिष्ट जल को शुद्ध करने के लिए जल उपचार संयंत्रों पर जोर दिया जा रहा है। कारखानों के उपचार और उनके अपशिष्ट जल को रिचार्ज करने के लिए उद्योगों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कैच द रेन अभियान नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रभावी उपायों को लागू करके पानी की कमी के मुद्दों को हल करना चाहता है। कई विभागों को शामिल करके और कार्यों के समय पर निष्पादन को सुनिश्चित करके अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण में महत्त्वपूर्ण प्रगति करना है। वर्षा जल संचयन के लिए एक स्थायी मॉडल बनाना है

पहाड़ के पेड़ से जल सरंक्षण की बूंदों को सहजने चले...

मनोज सती
अध्यापक
चमोली, उत्तराखंड

पहाड़ पर आग न लगे, नमी बरकरार रहे, इसके लिए परंपरागत धारी, नौला, गाड़-गधरा में पानी को कैसे बचने से इस अभियान को कमतर नहीं कह सकते...।

जल एवं पर्यावरण संरक्षण पर वर्ष 2019 से कार्य कर रहा हूं। मैं पेड़ पौधे लगाने के साथ जंगलों में नमी कैसी बनी रहे वह आग् की घटना को कैसे रोका जा सके इस पर भी हमारे परंपरागत धारी, नौली, गाड़-गधरा में पानी को कैसे बचाया जा सके। इसके लिए बिना किसी सरकारी मदद लिए अपनी वन पंचायत की लगभग 40 सेक्टर भूमि पर 200 से अधिक चाल-खाल खंथी पोखर का निर्माण करवाया गया। इन प्रयासों से ढलान युक्त पहाड़ों पर बारिश का पानी जमा हो सके और इसका परिणाम यह हुआ कि बरसात आने पर हजारों लीटर पानी भूमिगत हुआ और इससे जो हमारी आसपास का प्राकृतिक जल स्रोत हैं। अप्रैल मई आने पर इन प्राकृतिक स्रोतों में पानी सूख जाता है। इन चाल खाल बनाना से इसका परिणाम यह हुआ है कि इन प्राकृतिक स्रोतों में पानी की कमी नहीं हुई। नालों के किनारो पर भी मेरे द्वारा कैचमेंट बनाएं। जिससे नालों, गाड़-गधरा में पानी भरता रहे इसका परिणाम देखने को मिला कि बरसात खत्म होने के बाद भी इन गाड़-गधेरों में पानी की बहुत ज्यादा कमी नहीं रही।

उत्तराखंड में चीड़ के जंगल बहुत हैं उनमें गर्मी के सीजन में आग की घटनाएं बहुत बढ़ती हैं इन चाल-खाल बनने से आसपास नमी रही और आग की घटनाओं पर भी अंकुश लगा। चाल-खाल बनने से नमी के कारण इनके आसपास अनेक प्रकार की वनस्पतियां भी उग जाती हैं और उनके ऊपर जो पौधों का रोपण किया जाता है भीषण गर्मी पडने पर भी नमी के कारण यह पौधे सूखे नहीं हैं। इनके आसपास घास उगने के कारण मिट्टी के कटाव की भी रोकथाम हुई है। स्कूल में भी ये काम करता हूं ताकि बरसात शुरू होने से पहले स्कूल में भी चाल-खाल, खांति को बनाया जाता है। बच्चों को भी आने वाले समय के लिए जल संरक्षण कैस किया जाए इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाती है ताकि ये बच्चे भी भावी नागरिक बनकर जल संरक्षण का कार्य कर सके। जल संरक्षण करने के लिए और भी प्रयास किया जाते हैं जैसे विद्यालय में अध्यनरत बच्चों के जन्म दिवस पर खांति का निर्माण कर दिया जाता है। इस प्रकार से कई खंती बन जाती है वह जल संरक्षण किया जाता है बच्चों को जल संरक्षण के लिए इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक माह जल संरक्षण पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। कक्षा में एक बच्चों को जल मित्र बनाया गया है। हमारे प्रयासों से पहाड़ के दो गांवों के करीबन 400 परिवारों को इसका लाभ मिला।

Tribal farmers aware of Soil & water conserving techniques

Meda Gurudutt Prasad
Executive Secretary,
Action - Association for Rural and Tribal Development,
Rajahmundry, Andhra Pradesh

Tribal Farmers could able to understand the importance of water harvesting techniques and started installing Form Bunds and Trenches in their Land especially on hillocks and waste land.

Soil Moisture Conservation

To make the tribal farmers aware of Soil & water conserving techniques, series of trainings have been organized by KKS -ACTION as 100% tribal farmers do not know the SMC techniques. As part of our continues efforts in inculcating the techniques of SMC, Tribal Farmers could able to understand the importance of water harvesting techniques and started installing Form Bunds and Trenches in their Land especially on hillocks and waste land. We have also organized 15 training events during this period in addition to the trainings organized in 2017, 2018 and 2019, inviting 60 selective farmers from 12 target villages. It is known fact that in our target villages the farmers will not stick on to the number of farmers invited. As usual 484 tribal farmers have attended all the 15 training events and the attendance was more than expected 60 tribal farmer invitees.

In each acre approximately 60 meters of farm bund with 1.5 feet height will be made. The land owned by the target group is located mostly on hillocks which have slops. During rainy season the fertile top soil washes away on their land and it adversely affect fertility and moisture content of the soil and consequently the crop yield. The proposed activity will help in reducing run-off, soil erosion and improved soil moisture conservation and soil fertility, which in turn will help in improved agriculture yield. Moreover, it will also help in percolation of rain water to re-charge of the ground water. The trenches will be constructed on the agriculture land where there is slops. So, during the rainy season water will be harnessed in the trenches preventing soil erosion arresting run-off, maintaining soil moisture, percolation of rain water and growth of vegetation. The size of the ditches will be 15 - 20 feet length, 10 - 15 feet width and 6 feet depth.

Benefits of Soil & Water Conservation

Farmers started explaining about the advantages of SMC work and growth of plants where SMC work was done comparing with other plants growth where SMC work was not done. It is an indicator for healthy growth of plants and also for survival rate of the plants.As mentioned above trenches are also equally useful like farm bunds and all the farmers started explaining about the trenches to new farmers and also advantages of trenches like farm bunds. Trenches are very much useful on slope land and farm bunds are useful at plain land.

During the period (January'2017 to April'2023) Farm bunds in 78 ha (195 acres) have been formed with the involvement of Tribal farmers. These newly formed form Bunds and WRD through SMC are to protect the land from erosion, store the rain water and for water sources etc. During the rains in the hilly areas, the water gets accumulated through farm bund in turn crops get high water supply and the ground water gets replenished as well as prevents the soil erosion. In collaboration with local communities and Tribal farmers, Trenches have been formed in the land of Agro forestry partners. This work was taken place in 40.4 ha (101 acres) of land in 12 target villages. In addition to this, Agriculture Demonstrator, Government of Andhra Pradesh has given orientation to Farmers on how to use the Trenches and advantages of Trenches.

TRAINING OF FARMERS
GROUP MEMBERS ON
GROUP CONCEPT ROLES
AND RESPONSIBILITIES

BMZ
KKS
ACTION
EXPOSURE VISIT TO SHG
LEADERS OF 14 TARGET VILLAGES

BMZ-ACTION-KKS

VILLAGE LEVEL MEETINGS
FOR MONITORING
PLANNING AND
DISCUSSION

पानी, पर्यावरण बचाने के लिए भाएं मोहे, जल दूत के दोहे...

नंद किशोर वर्मा
अध्यक्ष, नीला जहां फाउंडेशन
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

एक ऐसी जर्नी जो शुरू हुई तो नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा गया। करीबन 51 नदियों की कथाएं लिखीं, जिसे हमारों ने पढ़ा। इतना ही नहीं 10 हजार पौधे लगाए गए। अब कारवां बढ़ा तो टीम 7 प्रदेशों में काम कर रही है। जन जन में लोकप्रिय हो रहे हैं जल दूत के दोहे...

यात्रा 2009 से शुरू हुई जब जल-नदी संरक्षण और पौधारोपण के लिए काम शुरू किया। प्रेरणा चिपको आंदोलन के प्रमुख सुंदर लाल बहुगुणा से मिली। भूगर्भ जल और सतही जल पर उत्तराखंड प्रशासन अकादमी से ट्रेनिंग हासिल की। कई चुनौतियां आईं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। स्कूलों में वर्कशॉप आयोजित की और बच्चों को जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक किया। मकसद लोगों को जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित करना है।

साल 2010 में मैंने गर्मी की छुट्टियों में मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की ताकि नदियों, झीलों के पौराणिक महत्त्व के बारे में

जानकारी जुटाई जाए। आठ राज्यों में मोटरसाइकिल यात्रा सफलता से हो चुकी है, करीबन 1500 नुक्कड़ सभाएं कर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा की 51 नदियों की कथाएं लिखीं और यह जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण में विशेष उपलब्धि रखता है।

जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के तहत 10 हजार पौधे लगाए, गोमती तट पर 6000 पेड़ों का मियावाकी वन लगाया। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर जागरूकता कार्यक्रम के जरिए जल संरक्षण, पर्यावरण बचाव और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर चर्चा, अनुभवों और ज्ञान को साझा करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं।

- नदियों की सफाई से जुडे कौन से काम किए कहां, पर क्या लाभ मिला?
- जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने के लिए काम करने का जुनून।
- जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने के लिए हमें जागरूक और सक्रिय होने की आवश्यकता है।

नमामि

@DoordarshanUttarPra

नदी का वैभव लौटाने चला एक किशोर का कारवां...

नंदकिशोर प्रजापति
संस्थापक सदस्य
कानवन सेवा संस्थान,
तहसील-बदनावर,
जिला-धार, मध्यप्रदेश

गांगी नदी सदानीरा अभियान के अंतर्गत नदी पर कई काम हुए, लेकिन 14 किलोमीटर की इस नदी को 1985 में जैसे पूरे साल बहती थी वही वैभव लौटाना है।

कानवन, 1,400 परिवारों वाला गाँव का प्राचीन इतिहास रहा है, यहाँ की कुछ इमारतें और प्राचीन बावड़ियां इसकी गवाह हैं। वर्ष-2015 मे एक फेसबुक मित्र ने उलाहना देते हुए कहा कि गाँव के नाम में तो वन जुड़ा है पर यहाँ हरियाली तो कही दिखती नही, बस वहीं बात की पीड़ा मेरी प्रेरणा बनी और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने में जुट गए। मन बनाया, टीम बनी और टीम संस्था... जिस मित्र ने उलाहना दिया था उसी ने 5,000 रुपए का सहयोग भी दिया और प्रेरणा भी...। बीते नौ वर्षोंमें संस्था ने गाँव और आसपास के छोटे-छोटे गाँवो में 76,000 हजार पौध ों का रोपण किया... आसपास की तीन पहाड़ियों को चिन्हित किया, बीजों को फेंकने की बजाय, गड्ढे बनाकर पिछले 5 वर्षोमें 16 लाख पचास हजार बीजों का रोपण किया, जिससे पहाड़ियों पर हरियाली का विस्तार हुआ। लगातार सूखते आम के पेड़ो से चिंतित होकर वृहद अभियान चलाया, गाँव जाकर बैठके ली और लोगों को आम के तने पर चूना और नीला थोथा पुताई करने की सलाह दी। 2019 में 100 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकालकर गाँव गाँव लोगों को समझाया।

गाँव में बहने वाली नदी को लेकर योजना बनी... 2021 में नदी को स्वच्छ और सदानीरा बनाने के लिए गांगी सदानीरा अभियान की शुरुआत की। नदी के पौराणिक महत्त्व को लेकर नदी के किनारों पर नदी परिक्रमा की शुरुआत की गई, गाँव गाँव जाकर लोगों को नदी की स्वच्छता और निर्मलता के लिए नदी मित्र बनाया, नदी से प्रतिवर्ष गाद और प्लास्टिक निकालने का काम प्रारंभ किया। बारिश से पहले नदी के किनारों पर नदी के अनुकूल बीजों की रोपाई की, पिछले चार वर्षोंमें एक लाख दस हजार बीजों का रोपण किया गया, जिसमे करंज और छिंद को प्रमुखता दी गई। बारिश के बाद अक्तूबर और नवम्बर में बोरी बंधान का कार्य प्रारंभ किया गया, बोरी बंधान से प्रेरणा पाकर अनेक गाँवों ने इसे अपनाया और छोटे-छोटे नालों पर अनेक बोरी बांधो का निर्माण हुआ। नदी से जुड़े टूटे फूटे तालाबों की मरम्मत करवाई, नदी पर इसी वर्ष दो दिवसीय बांस रोपण यात्रा निकाली गई, जिसमे सैकड़ों समर्पित साथियों की मदद से नदी के दोनों किनारों पर 21,000 हजार बांस के पौधों का रोपण किया गया। इन सभी कार्यों का परिणाम अब धीरे धीरे मिलने लगा है, जो नदी अक्तूबर में बंद हो जाती थी अब वह 15 जनवरी तक बहने लगी है। लक्ष्य है कि आगामी 5 वर्षों में हम नदी को मार्च माह तक बहने के लिए मेहनत करेंगे।

गांगी सदानीरा अभियान

प्राकृतिक संसाधनों का यह संसार बसा रहे, बहता रहे नदियों में पानी

नंदलाल सिंह
सामाजिक कार्यकर्ता, प्रकृति गांव
जमुई, बिहार

जमुई जिला प्राकृतिक संसाधानों से भरपूर चारों तरु नदियों, पहाड़ों, जंगलों से घिरा हुआ है। जिले में 1530 गांव हैं जिनमें कुल 32 नदियां हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जिले की नदियों का जल प्रवाह कम होता जा रहा। इसी प्रवाह के लिए 2002 से प्रयास जारी हैं।

जमुई जिला प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर एक छोटा सा जिला है, जो चारों तरफ नदियों, पहाड़ों, जंगलों से घिरा हुआ है। जिले में 1,530 गाँव हैं जिनमें कुल 32 नदियां हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जिले की नदियों का जल प्रवाह कम होता जा रहा था, प्राकृतिक जल संरचनाएं नष्ट हो रही थी, नदियों का दोहन होने लगा था, रेत खनन माफिया नदी का दोहन कर रहे थे, पेड़ों की कटाई, पहाड़ों का दोहन, ये सभी गतिविधियां जिले में लगातार हो रही थीं, गाँव का जल स्तर काफी नीचे चला गया था, यह आने वाले दिनों के लिए काफी भयावह था। जिले के विभिन्न गाँवों में जाकर लोगों के बीच जल, नदी, वनों का संरक्षण और अपनी विरासत को बचाने की मुहिम शुरू की और खासकर युवाओं को जल स्रोत को बचाने और उससे होने वाले फायदे के बारे में बताना शुरू किया, इसी क्रम में जिले की 152 पंचायतों में पैदल यात्राएं की, युवाओं के सहयोग से छोटे-छोटे तालाब भी एकत्रित किए गए और तालाबों का निर्माण किया गया, जल स्रोत को एकत्रित कर लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया, धीरे-धीरे भारी संख्या में लोग सहयोग करने लगे।

नदियों के दोहन के खिलाफ लोगों के बीच नदी बचाओ आंदोलन चलाया गया, सरकार से संवाद किया गया, जल सभा, जल पंचायत का आयोजन किया गया, जो निरंतर चल रहा है, जिले की 32 नदियों के स्रोत जो मृत हो गए थे, आज उनमें जल की धारा बहने लगी है, यह सभी के सहयोग से बहुत बड़ी उपलब्धि है, यहाँ का मुख्य कृषि कार्य जो समाप्त हो गया था, अब लोगों ने फिर से कृषि शुरू कर दी है क्योंकि नदियों में जल स्रोत फिर से शुरू हो गया है, लोगों का पलायन बंद हो गया है और लोगों ने नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर खेती शुरू कर दी है, जिससे लगभग 10,000 लोग लाभान्वित हुए हैं, भविष्य में भी यह नदी बचाओ, जल बचाओ अभियान जारी रहेगा। नदियों से जो पानी आता था वे उससे खेती करते थे, 5,000 किसान फिर से खेती करने लगे हैं और उन्हें इस आंदोलन से बहुत लाभ हुआ है। इसके साथ ही जिले के लगभग 35,000 लोग जोकिसी न किसी बहाने पानी से दूर हो रहे थे, उन्हें हमारे इस आंदोलन और हमारे संरक्षण कार्य से बहुत लाभ हुआ है।

जल ही जीवन है
जल है तो कल है
जल संकल्प यात्रा
जागरूकता अभियान
IFFCO
क्षण संकल्प यात्रा
गरूकता अभियान

Club Who Worked for JAL SAMRUDHI

NIZAMUDEEN. A, IAS
Mission Director
Mahatma Gandhi NREGS State Mission
Thiruvananthapuram, Kerala

A club who worked for JAL SAMRUDHI, an ias leading that..yeah this club working for water and water makes people happy..please welcome NIZAMUDEEN. A IAS, Mission Director, MGNREGS State Mission, Kerala.

A club who worked for JAL SAMRUDHI and honord globly. Jalasamrudhi was introduced as a noble integrated model for water conservation. This turned as a replicable model for water conservation projects on account of the active people's participation, effective planning and coordination of the activities of all the departments and organizations involved in implementation, for ensuring water prosperity in the days to come. One of the major water conservation project is Vattatha Uravaykkay Jalasamrudhi implemented in

Kattakada in Thiruvananthapuram District, Kerala State. Kattakada Assembly Constituency, once prosperous and sufficient in water availability was facing acute water shortage from mid-2000, in spite of the presence of 2 main rivers, numerous streams, canals and ponds. A comprehensive data base on existing water resources through primary data collection coupled with Satellite Image interpretation was done under his leadership. The entire database has been brought in the GIS platform. The database was enriched by secondary data and fine-tuned through user interaction workshops and stake holder discussions.

A series of seminars, discussions and trainings were conducted to ensure the community participation in project planning. The existing water resources were identified with its problems and the reasons for the present situation. Based on detailed discussions, exploring the possibility of conserving the water received through rainfall, rejuvenation/revival of deteriorated water resources and creation of new water storage structures were evolved Vattatha Uravaykkay Jalasamrudhi project was officially launched on 22nd March, 2017, World Water Day.

JAL CLUBS were formed in all 68 schools in the constituency to sensitize and ensure the participation of students in water conservation activities. A volunteer force comprising of 5 members in each ward, 'JAL MITHRAMS' were selected and trained by Suchitwa Mission and Youth Welfare Board. Mass awareness programmes such as rallies and public functions were organized with the active participation of students, Kudumbashree, NGOs, National Service Scheme (NSS) units, youth clubs and Students Police Cadets.

During the last seven years, number of programmes including planting of seedlings, digging rain water pits, protecting ponds and streams using coir geotextiles, rejuvenation of ponds and streams, artificial recharging of wells in schools and public buildings, digging of 350 plus new farm ponds, increase in paddy area, inland fisheries in renovated ponds, conducted water quality testing in all 122 wards, Water Quality Testing labs in 6 schools, Haritha Vidhyalayams (Green Schools), etc. were successfully taken up under this program. Rain water pits were digged in the households with the support of Residents Associations, Libraries and Youth clubs, under the campaign, Veetil oru Mazhakuzhi (One pit per house). The project also undertakes innovative ideas with the support of MGNREGS, such as drawing water from abandoned granite quarries and routing the supply to a recharge pit that is positioned close to the targeted wells in a manner that

facilitates gravitational flow of water and recharge the wells. Earnest efforts are taken to bring back the streams and ponds that are being encroached.

Even though there was a little hesitation during the initial phase for the big farm ponds, people started accepting the new concept on seeing the positive results in the field. This has resulted in the construction of 352 new farm ponds over 5 years. Inland fisheries undertaken in 117 ponds in collaboration with Fisheries Department. An innovative well recharge model that involves utilising water in a quarry has been successfully introduced at Kannancode, Pallichal Grama Panchayat. The project implemented in association with MGNREGS uses the water in a quarry to recharge the wells in the nearby areas. A location specific solution to resolve the continuous flooding of a road was experimented under the project and turned successful. Measuring scales and indication boards were installed in the selected 100 ponds in the initial phase with the assistance of Haritha Keralam Mission. This helps the local people and planners to estimate the water available in each pond.

Wise water uses open the door of happiness

Pradeep Mahapatra
Secretary & Co-Founder
Udyama
Odisha, Bhubaneswar

wise water use changing the picture of villages and people who deserve water full happy livelihood.

Pradeep Mahapatra is a hard-core community development practitioner believes in action on water culture, nature, lives, livelihoods towards a change lifestyle. He has been undertaking citizen-action in minimizing Disaster risks , END-WATER-POVERTY-campaign, Deepening-Water & Energy Governance & Capitalizing-Mainstream Resources-impact-towards Resilient Livelihoods & Community-Disaster-Resilient-Process along with life-skill-building and demonstrating sustainable food systems with rejuvenating rich social & ecological capital at local level towards achieving Global Goals. The focused activities are landscape advancement, wise water use, and agro-ecosystem restoration , soil carbon sequestration and carbon credit-based initiatives, piloting green energy in tribal hinterlands along with digital transformation. with added life skill-building integration. He is one of the members/observers of GCF, GEF, UNCCD, UNEP & Global Water Partnership, Global Soil Partnership & Water & Climate Coalition.

In the process community actively contributed to the process of facilitation of networks at different levels towards local biodiversity conservation and ecosystem management under micro watershed. This process has been benefiting more than half a million households, This is the prime activity undertaken that has been accelerating with maximum requisites and minimum (and without) fund and benefiting poor and rich even without any investment. Strengthening Community Forest Management efforts for all is the highlight and this has become Overwhelming Response & wide spreading and expanding, Benefit without investment: Good amount of fertile silt-forest-manure and large amount of biomass-that helps to curtailing expenses on fertilizer and land reclamation due to flash flood sand deposition. Important thing is that flow water available in the rivulets for longer period and double crops also are being cropped with protective irrigation is ensured. Whole approach is ecosystem conservation based and focus will be given to cultural biodiversity restoration followed by preservation of local forests , farm land development, that will facilitate to regulate local climate, water, food basket along with huge biomass reserve in terms of fuel, fertilizer, fiber and flora & fauna meet the needs of locality and others-Carbon impacts : expected quantities of carbon credits over the lifetime of the project: This process will be added advantage that there will be huge amount of carbon absorption and communities will access and avail the opportunity of credit out of it, there will be, social, ecological & financial capital will be gained .

UDYAMA has been awarded of the Best NGOs awardees on Rural Reconstruction & Environment in 2006, International Awardees on Environment 2014 & Best NGOs on Water Harvesting from UNESCO-2016 and many.

END
WATER
POVERTY
The Mirror

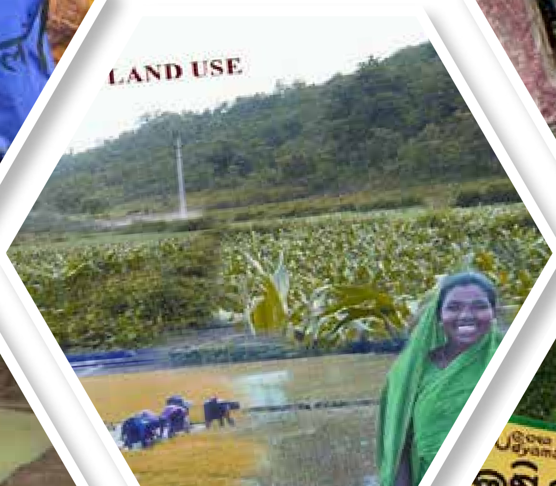
LAND USE

କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ

मेवात में पानी मिला तो होने लगी खुशहाली की बरसात

राहुल सिसौदिया
समाजसेवी, तरुण भारत संघ
मेवात, हरियाणा

मेवात इलाके की पहचान सूखे की जगह पानीदार इलाके के तौर पर हो इसके लिए अरावली पहाड़ियों से सटे इलाकों के दर्जन भर से ज्यादा गांव में अब असर दिखने लगा है। इन पहाड़ियों को हरा-भरा बनाने, सूखे की विभिषिका से निपटने के प्रयासों में धीरे-धीरे ही सही लेकिन बदलाव नजर आ रहा है।

हरियाणा-राजस्थान के सीमावर्ती इलाके मेवात में गर्मियों में भीषण जल संकट होता है। नुंह जिला मेवात कहलाता है और मेवात के गाँव पाटखोरी में जलस्तर लगभग एक हजार से 1200 फुट की गहराई पर है। यहाँ की पानी पीने की बहुत समस्या है लोगों को पेयजल के लिए सात-आठ किलोमीटर दूर से पानी मंगवाना पड़ता है। कभी टैंकर मंगवाकर पानी की आपूर्ति करते हैं। क्षेत्र में तरुण भारत संघ के साथ मिलकर चार जल संरचनाओं का निर्माण करवाया। मानसून के बाद जब जन जल संरचनाओं में पानी आया तो इस गाँव का दृश्य देखने लायक है। गाँव के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई जो बोरवैल पहले सूख गए थे उन में भी पानी आने लगा। जो बोरवैल पहले 2 घंटा चलते थे अब वह 5 घंटे चलने लगे हैं और इलाके के लोग अब खेती करने लगे हैं। गाँववासियों के सहयोग से पहला जल स्रोत तैयार हुआ और अब धीरे-धीरे 15 गाँव के 48 तालाबों को तैयार कर दिया गया। इन तालाबों में पहले से बने तालाब जिन्हें दोबारा जीवन मिला तो वहीं पहाड़ियों के नीचे बनाए विशाल तालाब में पानी भरा तो गाँव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई।

यहाँ रेतीली, भुरभुरी मिट्टी के बीच बांध तैयार करने की चुनौती भी टोली ने सफलतापूर्वक पूरी की और अब यहाँ पर पानी के आने से लगभग कई हजार पशुओं को जहां लाभ पहुँचा वहीं किसान अब खेती करने लगे हैं। छोटे तालाब, जोहड़, एनिकट बनाकर बरसाती पानी को जहां जमीन में उतारा वहीं पहाड़ियों से आने वाले बरसाती पानी, जो गाँववासियों के घरों तक पहुँचकर वेग से उनके कच्चे घरों को नुकसान न पहुँचाएं तालाब बनाकर, उन्हें भी सुरक्षित किया। तालाबों, जोहड़ों, कुंओं में पानी का स्तर बढ़ने से लोगों के बोरवैल में दो फीट से लेकर 3 फीट तक का पानी चढ़ा है व कई जगह खारे पानी की समस्या दूर हो गई। किसान खेती में पानी ज्यादा बर्बाद न करें यह दर्द भी महसूस हुआ तो करीबन डेढ़ सौ किसानों को जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए पाइप वाले दिए, जिससे अब लोगों ने खेती में इस्तेमाल करके अधिक पैदावार लेते हैं वह अधिक खेती लाभदायक हुई है। इलाके में अब कई परिवारों की आय बढ़ी है तो वहीं गाँव खुशहाल होने लगे।

बीहड़ में बह रही तीन नदियों ने बागियों के बदले दिल, ग्रामवासियों के दिन...

रणवीर सिंह गुर्जर
जिला समन्वयक, तरुण भारत संघ
करौली, राजस्थान

धौलपुर में तीन मुख्य नदियां खर्राबाई, बामनी, बद्दह। इन नदियों के पुनर्जीवन से बागियों ने बंदूक छोड़ दी। चंबल में शादी ब्याह होने लगे और रोजगार के तौर पर खेती लहलहाने लगी।

राजस्थान के करौली, धौलपुर में वर्षों से जल, जंगल, जमीन के लिए संघर्ष देखा। एक-एक बीघ जमीन के लिए गोलियां चल जातीं, उस जमीन पर पानी न होने से एक दाना पैदा न होता। लोग बागी बन जाते, बंदूक उठा लेते।

यह दर्द महसूस किया और बंदूक वाले हाथों में जल संचयन, जल स्रोतों को जीवन देने वाले औजार थाम लिए। डेढ़ दशक की यह मेहनत रंग लाई, समाज के साथ मिलकर पिछले 15 वर्षों में करौली धौलपुर में कई नदियों, जल स्रोतों पर काम किया। इसमें करौली जिले की मासलपुर तहसील में नहरों नदी, जोकि मासलपुर से चलकर बंध बारैठा में जाती है। कोट नदी जोकि खैरटपुरा से निकलकर कर कोट होती हुई उतंगन नदी में मिलती है। तीसरी सैरनी नदी जोकि खेड़ा मे ठेकरा की गौशाला से निकलकर पार्वती नदी में पार्वती बांध में मिलती है। चौथी तेवर नदी जोकि मंडरायल में तीन पोखर व श्यामपुर की पहाड़ियों से निकलकर पार्वती नदी में मिलती है।

धौलपुर में तीन मुख्य नदियां खर्राबाई,बामनी, बद्दह नदी पुनर्जीवन किया। यह चम्बल का डांग क्षेत्र है जिसका नाम लेते ही लोग डर जाते हैं। सेरनी में पानी आया तो आसपास की जमीन ने सोना उगल दिया, फसल हुई तो खुशहाली, समृद्धि आई। जल संकट के कारण उजड़ते हुए लोगों को खेत में जब फसल मिली तो वहीं ठहरने लगे। करौली-धौलपुर में सात नदियों को पुनर्जीवित करने में ये लोग भी जुट गए। हजारों की तादाद में कुंए, बोरवैल रिचार्ज हुए, लाखों लोगों को रोजगार मिलने लगा। अब जल जन जोड़ो अभियान बंदूक नहीं समृद्धि से गूंज रहा है।

तरुण भारत संघ
YES FOUNDATION
संरचना का नाम- नरे द्वितीय की पोखर
गाँव-बहेरीपुरा, धौलपुर
इस पोखर का निर्माण वर्ष-2024-2025 में तरुण भारत संघ की प्रेरणा, YES फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग व ग्राम वासियों के अंशदान से किया गया है।

जल संरक्षित हो जाएगा अगर बेटियों को समाज आगे लाएगा

संदीप कौशिक
महासचिव, सर्व कल्याण मंच
भिवानी, हरियाण

जल संरक्षण की मुहिम में समाज को भागीदार बनाते हुए बेटियों को उनके घर में जब सम्मान दिलाया तो जल संचय, जन भागीदारी की बड़ी मिसाल खड़ी हो गई...

पानी की कमी और पर्यावरण क्षरण की खतरनाक दर को पहचानते हुए, संगठन ने इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रभावशाली पहल की है। उनके प्रमुख प्रयासों में से एक जागरूकता अभियान, वर्षा जल संचयन परियोजनाओं और समुदाय संचालित गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया। स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं, प्राकृतिक जल संसाधनों के संरक्षण के महत्त्व और दैनिक जीवन में पानी के कुशल उपयोग के बारे में शिक्षित करते हुए जल संरक्षण के साथ-साथ वृक्षारोपण अभियान, अपशिष्ट प्रबंधन अभियान और पर्यावरण के अनुकूल विधियों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। स्कूलों, स्थानीय निकायों और पर्यावरण के प्रति उत्साही लोगों के सहयोग से सर्व कल्याण मंच ने अनगिनत व्यक्तियों को पर्यावरणीय स्थिरता के मिशन में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित किया है। मंच इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे सामूहिक कार्रवाई और समर्पण से एक स्वस्थ ग्रह और सभी के लिए एक स्थायी भविष्य का निर्माण हो सकता है।

मंच की टीम द्वारा 'जियो जवान जियो किसान' नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जैविक खेती करने वाले किसानों और कारगिल में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को एनजीओ द्वारा सम्मानित किया गया। एनजीओ ने बेटियों को सम्मान दिया और बिना किसी शुल्क के बेटी की नेमप्लेट उपलब्ध करवाता है। अभी हर घर बेटी के नाम अभियान के तहत हरियाणा के कई गाँवों में इस एनजीओ ने हजारों घरों के आगे बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगाई है, जो अपने आप में एक अनुकरणीय पहल है। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए सर्व कल्याण मंच द्वारा कई स्थानों पर पेड़ लगाए गए हैं, जिनकी देखभाल भी मंच के स्वयंसेवक करते हैं। शहीदों के स्मारकों की सफाई करते हैं और इन महान हस्तियों की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर समाज को उनके इतिहास से अवगत कराते हैं।

आपका हार्दिक

मजदूर और किसानों के हक में जब उतरती हैं जमीन पर सरकारी योजनाएं

सरोज कुमार
निदेशक (आईटी) बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी (बीआरडीएस)

भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई चौर भूमि सुधार परियोजना पर सतत कार्य किए गए हैं।

बिहार के मुजफ्फरपुर के चौर भूमि के क्षरण के वास्तविक गवाह हैं। सरोज कुमार के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में आर्द्रभूमि सुधार योजना तैयार की गई और मुजफ्फरपुर जिलों के लगभग हर ब्लॉक में इसे शुरू भी किया गया। यह अनुमान है कि मुजफ्फरपुर के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग चालीस प्रतिशत चौर भूमि में स्थित है।

बाढ़ के दौरान, सभी चौर भूमि क्षेत्र पानी में डूब जाते हैं और तीन से छह महीने तक डूबे रहते हैं। यह घटना इतनी भयंकर होती है कि स्थानीय किसान साल में केवल एक ही फसल उगा पाते हैं। यह किसानों और समाज के लिए बहुत बड़ी आर्थिक क्षति है।

इन चौर भूमि को पुन: प्राप्त करने की चुनौती ली है और इस परियोजना को शुरू करने के लिए लगातार शीर्ष से लेकर निचले स्तर के अधिकारियों की बैठकें आयोजित की गईं। इस पुनर्ग्रहण परियोजना में एक लाख से अधिक मनरेगा मजदूरों को उनके स्थानीय क्षेत्रों में काम मिलेगा और पूरा होने के बाद पांच लाख से अधिक किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। इसी विजन की वजह से बिहार ने लाखों हेक्टेयर बंजर भूमि का पुनर्ग्रहण उपलब्ध हासिल की है। वे लक्ष्य को प्राप्त करने और तीन दिनों के भीतर अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

इस पहल से एक लाख से अधिक मनरेगा मजदूरों को लाभ मिला है और परियोजना के पूरा होने के बाद लगभग 5 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

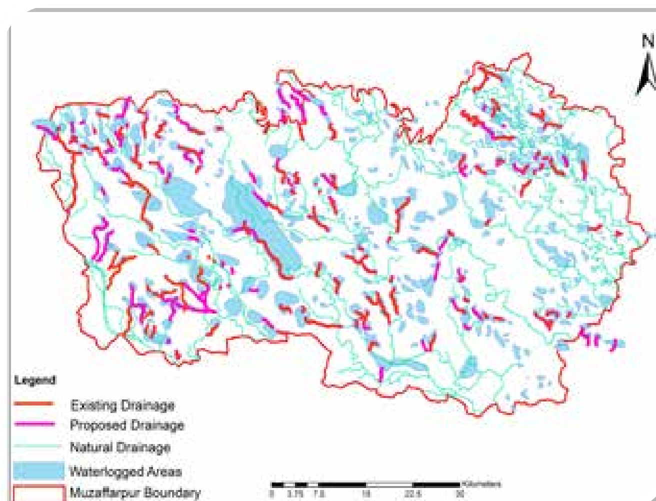
N
Legend
Existing Drainage
Proposed Drainage
Natural Drainage
Waterlogged Areas
Muzaffarpur Boundary
Kilometers

नदी के पानी की धार, नर–नारी, पशु–पक्षिओं के जीवन को रही है संवार...

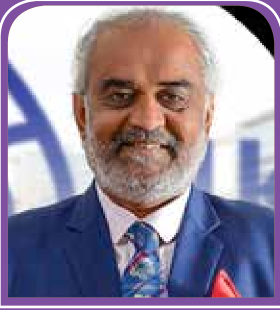

सावजी भाई
ढोलकिया फाउंडेशन
सूरत, गुजरात

गुजरात के सूरत में अमरेली में चमारडी से क्रांकाच तक 52.9 किलोमीटर तक फैली गगडिया नदी के पुनरुद्धार अलग-अलग चरणों में जारी है। नदी की मिट्टी की हालत खराब है। नदी पुनरुद्धार परियोजना 2017 में शुरू हुई और सावधानीपूर्वक नियोजित चरणों में आगे बढ़ रही है। पहला, दूसरा चरण पूरा हो चुका है। लक्ष्य गगडिया नदी को स्थायी जल स्रोत में बदलने का है।

गगडिया नदी के पुररुद्धार के काम जनवरी से मई के बीच किये जाते हैं। चेक डैम बनाने, नदी को गहरा और चौड़ा करने तथा तटबंध बनाने पर फाउंडेशन के काम केंद्रित हैं। ये तटबंध विभिन्न रूप ले सकते हैं, जिसमें गैबियन दीवारें या मिट्टी को जगह पर रखने के लिए बांस लगाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, जहाँ भी संभव हो, नदी के किनारों को और अधिक स्थिर करने और अतिप्रवाह से बचने के लिए सीमेंट की सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। ये संरचनाएं नदी की जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाने में आवश्यक हैं। जल धारण क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त, खराब गुणवत्ता वाली मिट्टी को हटाया जा रहा है।

इन प्रयासों का उद्देश्य गगडिया नदी को स्थायी जल स्रोत में बदलना, सामुदायिक भागीदारी के साथ जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्राथमिक कार्यों में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और पुनर्वास किया, चेक डैम, तटबंध, नदी को गहरा और चौड़ा किया गया। इससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाया, भूजल पुनर्भरण और अन्य जल निकायों जैसे कुओं और खेत के तालाबों को पुनर्भरण की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पिछले पांच वर्षों में, इस परियोजना ने गगडिया नदी के किनारे कई ऐसी संरचनाओं को लागू किया है, जिससे कृषि और घरेलू उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इन संरचनाओं ने 20 बिलियन लीटर से अधिक सतही जल का संरक्षण किया है, जिससे उप-सतही और भूजल क्षेत्रों में पानी की मात्रा क्रमशः 18 प्रतिशत और 12 प्रतिशत बढ़ गई है। इससे गैरमानसून अवधि के दौरान एक स्थायी जल आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है, कृषि उत्पादकता बढ़ा रही है, सूखे से भी निपट रहे हैं।

परियोजना में नदी किनारे और आसपास के क्षेत्रों में लाखों पेड़ लगाए ताकि हरित क्षेत्र बढ़े, कटाव कम हो जैव विविधता बढ़े। मिशन रिवर परियोजना के प्रमुख नवाचारों में से एक नदी के जलग्रहण क्षेत्र की निगरानी और प्रबंधन के लिए उन्नत रिमोट सेंसिंग और जीआईएस उपकरणों का उपयोग किया है। वर्ष 2017 से 2023 तक जलग्रहण क्षेत्र में परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए सेंटिनल-2 इमेजरी और जीपीएस उपकरणों का उपयोग किया जाता है। परियोजना वनीकरण और कृषि में नवीन तकनीकों का भी उपयोग करती है। जैव-उर्वरकों एवं जैव-कीटनाशकों के प्रयोग से परियोजना को बढ़ावा मिलता है।

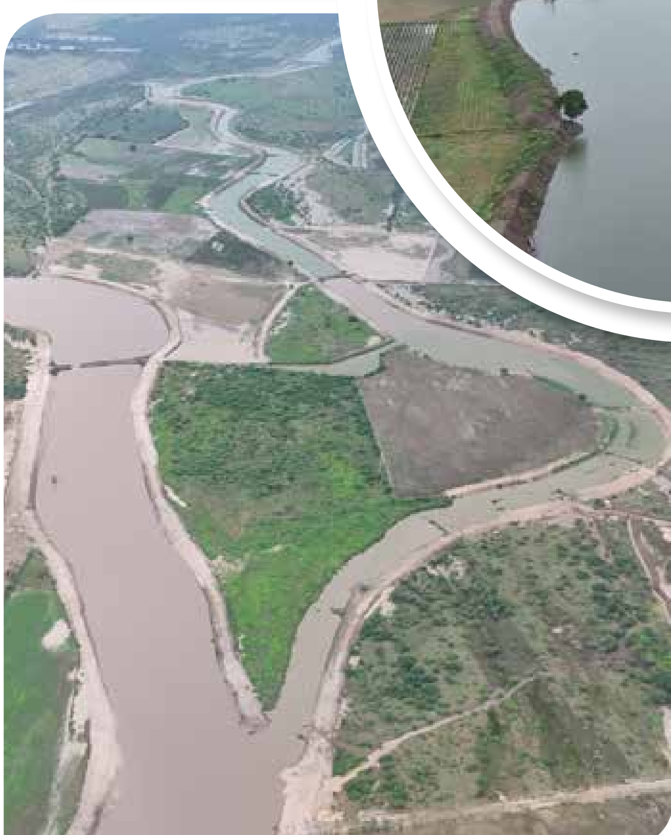

बोरवैल अभियान ने एक माँ बेटे के स्नेहिल रिश्ते को किया चरितार्थ

सिंधव मनसुखभाई रांछोड़भाई
किसान, वाणी, अहमदाबाद, गुजरात

गुजरात के अहमदाबाद के नजदीक वणी गाँव से शुरू हुआ बोरवैल अभियान ने 500 फीट पर पहुँचे पानी को आखिर 30 फीट पर कैसे पहुँचाया...

करीब दस साल पहले जब मैंने अपने खेत में सिंचाई के लिए बोरवैल लगाया तो बोरवैल लगाने के बाद 200 फीट की गहराई पर पानी मिला और सफल हो गया। आज तक इसका उपयोग मेरे खेत में फसलों की सिंचाई के लिए किया जा रहा है। कोरोना काल में एक विचार आया कि हम जमीन से पानी खींच लें, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। बर्बाद हुए बारिश के पानी को उसी बोरवैल के जरिए धरती मां को वापस लौटाने का अभियान शुरू किया। हर साल खेत में भरने वाले अतिरिक्त पानी को बोरवैल रिचार्ज में उपयोग किया जाने लगा और पानी का सदुपयोग शुरू हो गया।

इस सफल प्रयोग को देखकर मेरे गांव के किसान बहुत प्रभावित हुए। मैंने उन्हें इसके बारे में बताया, समझाया और फल स्वरूप में अधिकांश किसान इस जल क्रांति अभियान से जुड़ गए। आज मेरे गांव में 200 से अधिक बोरवैल बरसात के पानी का जल संचय कर रहे हैं। मेरे आसपास के गांव में भी 1000 से अधिक बोरवैल में जल संचय किया जा रहा है। कहना चाहूंगा कि आठ साल पहले हमारे खेतों में पानी का स्तर 500 फीट से ज्यादा गहरा था, जो इस प्रयोग कि बदौलत आज वह 30 फीट तक पहुंच गया है। यह वह लाभ है जो वर्षा जल संचयन के बाद प्राप्त हुआ है। हालांकि पहले खेत में जलजमाव फसल की बर्बादी का कारण था। यह रुक गया है. इससे फसल के बीज, ट्रैक्टर की लागत, डीजल की लागत और समय की बर्बादी रुकी और किसानों के लिए वरदान भी यही है। पुनर्भरित वर्षा के अच्छे जल से फसल का उत्पादन बढ़ता है तथा अनेक प्रकार के रोग एवं कीट नष्ट हो जाते हैं। साफ पानी हमारे लिए प्राकृतिक औषधि की तरह काम करता है।

जैसा कि श्री तुलसीदासजी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं-बरसाही जलद भूमि निपराये। जथानवहि बुध विध्या पाय ।। इस पंक्ति से मिले मंत्र जल ही जीवन है और विश्व महापुरुष, प्रेरणादायक और निरंतर प्रोत्साहित करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दूरदर्शिता को मैंने अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया है। मैं इसके लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूं। मानव अवतार का सच्चा अर्थ यह है कि हम प्रकृति से जो कुछ भी लें, उसे ब्याज सहित लौटाएं। मां, जितना देती है उससे थोड़ा भी उसे वापस मिल जाए तो वह चार गुना दे देती है। धरती मां से पानी लेने वाले एक गुजरात के सपूत ने बता दिया, बोरवैल से पानी लेने की जगह अगर वर्षा जल संचय का पानी धरती मां की कोख में उतार दो तो क्या क्रांति आ सकती है...।

જળ સંચય
જન ભાગીદારી
જન આંદોલન

चुनौतियों के आगे भर दिये जल के सागर अपार

सोमनाथ माली
सुचित्रा पाटिल, दयाराम सोनवणे

जज्बा हो तो कुछ भी संभव है और कम से कम 10 गांवों में जल संरक्षण कार्यों, पर्यावरण रक्षा व झीलों के पुनरुद्धार कार्यों को देखकर यह लगता है...

सेवा सहयोग फाउंडेशन के इन तीन स्वयंसेवकों ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले के चालीसगांव क्लस्टर में ग्रामीण विकास कार्य के पहले चरण में जिम्मेदारी ली। उन्होंने लगभग 10 गांवों में जल संरक्षण कार्य और वृक्षारोपण, पोषण कार्य की जिम्मेदारी ली है। ये झील पुनरुद्धार योजना में उतरे तो ब्रम्हनशेवगे, शेवरी, शिदवाड़ी, दासकेबार्डी, आभोने तांडा, कलमाडु में इन्होंने झीलों को जीवन दे दिया। उन्होंने ब्राह्मनशेवगे और छह आस-पास के गांवों में सात झीलों के जीर्णोद्धार का नेतृत्व किया, जिससे क्षेत्र की जल सुरक्षा में सुधार हुआ। उनकी उपलब्धि है, 25 करोड़ लीटर की जल भंडारण क्षमता का निर्माण। वर्षा जल संचयन प्रणालियों और जल भंडारण संरचनाओं के निर्माण से इलाके में जल संकट को दूर करने में मदद मिली।

झीलें जो कभी सूख गई थीं या अत्यधिक क्षरित हो गई थीं, का कायाकल्प हो गया है और अब इस क्षेत्र में भूजल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लगभग एक मीटर पानी बढ़ा जिससे किसानों को राहत मिली। भूजल स्तर सुधरा तो फसलें सुधरी, किसानों की आय में सुधार आया। इन गांवों से पलायन कम हुआ। वृक्षारोपण किया तो ब्रम्हनशेवगे में 25000 पेड़ों की श्रृंखला खड़ी कर दी। इसके अलावा उन्होंने लोगों की भागीदारी के साथ अपने गांवों में नाला चौड़ा करने, गहरा करने का काम किया है। उन्होंने 25 करोड़ लीटर से अधिक की जल भंडारण क्षमता बनाई है और 25000 से अधिक पेड़ों का पोषण किया है। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने पानी, पानी के महत्त्व और हमें भूजल को क्यों संग्रहित और रिचार्ज करना चाहिए, इसके बारे में जागरूकता पैदा की है।

उन्होंने गांव में जल समिति के रूप में ग्राम सभा का गठन किया है, ग्रामीणों में जल साक्षरता पैदा की है। जल समिति की मदद से उन्होंने गांव में सेवा की है और काम की योजना तैयार की है। यह एक पूर्ण सहभागिता मॉडल है, इसलिए जल संरक्षण गतिविधियों के दौरान हर समय विभिन्न लोगों को योगदान देने और उपलब्ध रहने की आवश्यकता है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि लोग काम के लिए योगदान दें और एनजीओ, सीएसआर संस्थाओं की मदद से उन्होंने गांव के लिए जल संरक्षण कार्य करने के लिए एक खुदाई मशीन उपलब्ध कराई है। स्वतंत्र स्वयंसेवक अब जन-जन के जल संचय में जुटे हैं।

ग्लेशियर घटने लगे, बर्फ के तालाब से मिल रहा है जीवन के लिए पानी

स्टैनजिन चोसफेल
कार्यकारी पार्षद (कृषि) एलएएचडीसी
लेह

बर्फ के जलाशय लोगों की प्यास बुझाने के लिए काम आ रहे हैं। यह सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है।

लेह का एक गांव है इगू (लेह हवाई अड्डे से 50 किमी दूर)। करीब 250 घरों वाला यह गांव कभी एक जीवंत गांव हुआ करता था, जहां हर कोई पर्याप्त भोजन उगाता था और दूसरे सामानों के लिए वस्तु विनिमय करता था। हालांकि इगू का ग्लेशियर क्षेत्र सालाना 1 फीसदी की दर से सिकुड़ रहा है और इसलिए यहां कई लोगों के लिए कृषि तेजी से अव्यावहारिक व्यवसाय बन रही है। इस तरह के हिमनदों के पीछे हटने के खिलाफ अनुकूलन के लिए घरेलू और ग्राम स्तर के जल प्रबंधन प्रथाओं के एक समूह की आवश्यकता होती है जो लागत प्रभावी तरीके से कुशलतापूर्वक पानी का भंडारण और आपूर्ति करते हैं। जल भंडारण उपकरणों के जरिए सिंचाई की मांग के आधार पर जल आपूर्ति को विनियमित करना होगा। बांध और टैंक जैसे पारंपरिक जल भंडारण उपकरणों के निर्माण में लागत बहुत आती है और ऐसे ठंडे शुष्क क्षेत्रों की मौसम की स्थिति के संपर्क में आने पर वे टूटते भी हैं। इसकी तुलना में बर्फ के जलाशय सस्ते होते हैं और साथ ही प्रकृति आधारित तकनीक होने के कारण ग्लेशियरों की पारिस्थितिकी सेवाओं का विस्तार करते हैं। सिंचाई क्षेत्र और अवधि को बढ़ाने के अलावा, वे गांव को अतिरिक्त पर्यटन राजस्व भी प्रदान करते हैं। इगू जैसे गांव में, इस तरह के बर्फ के जलाशय हर सर्दियों में आकार में बढ़ सकते हैं और कुल हिमनद क्षेत्र और जल आपूर्ति को लगभग 30 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं, जो अन्य जल प्रबंधन प्रथाओं की तुलना में कई गुना सस्ता है। लद्दाख के 44 से अधिक गांवों ने पहले ही इन बर्फ के जलाशयों का निर्माण कर लिया है। लेकिन इनमें से एक दर्जन से भी कम गांवों ने पिछली सर्दियों में यह गतिविधि जारी रखी। अन्य लोगों ने इन संरचनाओं के निर्माण में अपनी सर्दियों का अधिकांश समय बिताने के बाद मिलने वाले नगण्य जल आपूर्ति के कारण निराश होकर यह अभ्यास छोड़ दिया था।

पिछले एक साल में एकर्स ऑफ आइस ने बर्फ जलाशय निर्माण के लिए हमारे स्वचालन प्रणाली का परीक्षण करने के लिए इगू में एक पायलट परियोजना का संचालन किया है। पिछली सर्दियों में हमारा प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसा स्केलेबल और रखरखाव में आसान बर्फ जलाशय लागू करना था जोकिसी भी दूरस्थ वातावरण में स्वायत्त रूप से कार्य कर सके। अपेक्षाओं के विपरीत, इसका मतलब था कि हमें अपनी साइटों को इस तरह से चुनना था कि वे दुनिया भर में बर्फ जलाशयों के निर्माण के लिए सबसे कठिन स्थानों में से कुछ का प्रतिनिधित्व करें। यही कारण है कि हमने पिछले नवंबर 2023 से अपने पायलटों के निर्माण के लिए लद्दाख के इगू और नांग गांवों का चयन इसका झरना जल स्रोत, हालांकि गर्म है, लेकिन विशेष रूप से सर्दियों में मात्रा में उतार-चढ़ाव करता रहता है। इसके अलावा, निकटतम सड़क से एक घंटे की दूरी पर होने के कारण साइट तक पहुंचना कठिन है। इगू के पास इन संरचनाओं के निर्माण का एक लंबा इतिहास है। 2009 में, लेह पोषण परियोजना (LNP) ने सूखी पत्थर की दीवारों से युक्त बर्फ की छतों के 2 सेट बनाए। 2014 में, 26 समान संरचनाओं का एक और सेट बनाया गया था, जिसमें दीवारों का आकार 20 से 100 फीट लंबाई के बीच था। 2021 में, जब इगू ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स (HIAL) द्वारा आयोजित आइस स्तूप प्रतियोगिता में भाग लिया, तो एक बर्फ स्तूप बनाया गया। संरचना ने प्रथम पुरस्कार जीता और अगस्त तक बची रही। हालांकि, 2021 से ऊपर सूचीबद्ध सभी बर्फ जलाशय जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं। गाँव में एक जल प्रबंधन समिति है जो इन संरचनाओं का रखरखाव करती है। उन्होंने बताया कि पाइपलाइनें बार-बार जम जाती थीं और इसलिए वे इसका रखरखाव करने में असमर्थ थे। पिछली सर्दियों में अपनी स्वचालन तकनीक के उपयोग के माध्यम से, हम इगू में बर्फ के जलाशयों के निर्माण की परंपरा को पुनर्जीवित करने में सक्षम थे। स्वचालित बर्फ जलाशय (एआईआर) ने हर दूसरे दिन की निगरानी यात्राओं को घटाकर महीने में दो बार कर दिया है। इसने 4 मिलियन लीटर से अधिक पानी का भंडारण किया है, जिससे पारंपरिक लोगों के लिए केवल 20: की तुलना में 80: से अधिक की दक्षता का उपयोग होता है, जो आमतौर पर 1 मिलियन लीटर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा, ये संरचनाएं फव्वारा स्प्रे को संचालित करने के

लिए आदर्श मौसम खिड़कियां पाकर पूरे वर्ष बढ़ती हैं। इस प्रकार, यह उन्नत तकनीक एक बारहमासी बर्फ जलाशय प्रदान कर सकती है, जिसका आकार हर सर्दियों में बढ़ता है और प्राकृतिक ग्लेशियरों की खोई हुई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की भरपाई करता है। कार्य का सामाजिक प्रभाव और कितने लोग लाभान्वित हुए

इस पायलट परियोजना के परिणामों का उपयोग सरकारी एजेंसियों द्वारा झरने के कायाकल्प, भूजल पुनर्भरण और हिमनद संरक्षण के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यह जल जीवन मिशन जैसे सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है, और नमामि गंगे कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य गंगा नदी को साफ और संरक्षित करना है।

"Dhara Vikas" revived drying Springs in the Sikkim Himalayas and make people smile

Dr. Subash Dhakal
Deputy Director Rural Development Department
Gangtok Sikkim

water for the rural people is met by tapping water from small springs, streams, and lakes. Most of the springs are drying up or becoming seasonal. Springs dried up but dhara vikas initiative changed the music of springs...

This resulted in an acute scarcity of water during the lean season especially from December to May. we receive rainfall in the form of heavy downpours in a few months. More than 80% of rainfall is converted into runoff. People in rural areas face acute scarcity of water during the lean season. Women and children are the most affected as they perform the majority of household tasks. To combat the situation, an initiative called "Dhara Vikas" was started in Sikkim in 2008. Initially, neither there was literature nor any related success story which may have provided a lead to combat the crisis.

It started with lots of research questions like-can the dried-up springs be revived? Where is the recharge area? Can we increase the lean season discharge? Etc. The initiative started with the watershed approach which did not prove to be fruitful. With deeper engagement, we understood the significance of geology which was seldom considered in the watershed approach. This was followed by a hydro-geological approach to considering recharge areas for each spring. This was piloted in a few areas. Some of the springs showed positive results but some did not. There was something that was missing to be understood. The network of fractures over the metamorphic rocks in the mid-hills significantly impacted the storativity and transmissivity of groundwater of the mid-hills. This improved our understanding of the mountain aquifer system and guided us to change our approach from a Spring-based approach (focus on the source) to an aquifer-based approach (focus on the resource).

In the aquifer aquifer-centric approach, we consider the entire hill or a standing range for the treatment and consider all the springs abutting the hills. The recharge area is identified for the entire aquifer following hydro-geological study rather than individual springs. This approach was far more successful not only for the springs but also for the base flow of small streams and rivulets which later on joined to form the larger river. Therefore it was more of "learning by doing" on our part to bring this knowledge to the present level. The core thrust of Dhara Vikas is to catch the surface runoff water and use it to recharge groundwater sources. A team of experts go to the spring, understand the geological formation, and identify the correct recharge area for the springs. Artificial recharge pits and trenches are dug on the identified site. During the monsoon, excess runoff generated from the rainfall is captured by these structures thereby controlling soil erosion and recharging the aquifers.

To date, 1023 hectares of intervention have been done on the ground, 5 hilltop lakes revived to their natural state, and 4 lakes converted into recharge structures through the initiative. This has largely impacted the discharge of springs and streams downstream and augmented the water

supply for drinking, agriculture and other uses. A total of 100500 trenches and 6018 ponds have not only helped to recharge groundwater but also helped to control the downstream stormflow thereby, preventing gully erosion and landslides and is acknowledged by some of the local SDMs. The initiative is supported by an independent assessment by IISC Bangalore. Dhara Vikas was incorporated in the list of permissible works under MGNREGA by the Planning Commission of India in 2012. Sikkim is declared as the resource state for the development of spring-shed by the Ministry of Rural Development, Government of India. Above all, the Rural Development Department Government of Sikkim played a crucial role in making spring-shed development a national movement and a key adaptation strategy for water security in the Himalayas. Many dried-up springs have been revived across Sikkim and villagers are thankful and happy with the initiative. This has benefitted more than 17000 households in drought-prone areas of Namchi and Soreng District with a population of about more than 82,0000.

रंगीले राजस्थान में सुखाड़, खारे पानी की समस्या से निपटने की लड़ाई

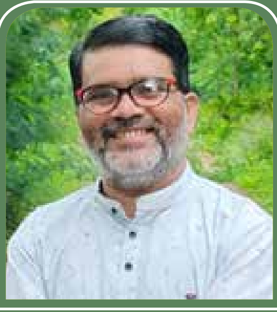

सुरेश चन्द्र रैकवार
तरुण भारत संघ
अलवर, राजस्थान

खारे पानी, सुखाड़ से जूझ रहे जयपुर शहर और शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के लिए कई जल टांको निर्माण कार्य किया है। सिंचाई के लिए भी तकनीक के जरिए पानी मुहैया हो यह कार्य जारी है...

पीने के लिए आम जनों को पानी मिले यह टांका बनाकर सुनिश्चित किया तो वहीं किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध कराने हेतु फार्म पॉंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह ऐसा इलाका है जहां जमीन के अंदर या तो पानी नहीं है, यदि कहीं पानी है तो खारा है। ऐसे में इस इलाके में कार्य की बहुत जरूरत महसूस होती थी। यहाँ के किसानों कंपनियों के जल शोषण से ग्रस्त हैं।

जमीनों का पानी कंपनियां निकाल चुकी हैं। सिर्फ अमीर लोगों के पास ही आसानी से जल उपलब्ध है। हम सभी को पीने के लिए पानी की जरूरत होती है। इंसान ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षियों को भी पानी की जरूरत होती है। धरती के कुल भूभाग के दो तिहाई भाग पर जल मौजूद होने के बावजूद दुनिया के अधिकांश जल का संकट है।

गरमी का मौसम शुरू होते ही पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच जाती है। ऐसे में जल टांकों और फार्म पोंड से जल संरक्षण की मुहिम को पहुँचा रहे हैं ताकि पेयजल उपलब्ध हो। अभी जल टांकों और फार्म पोंड से किसान अपने फसलों का अच्छा उत्पादन कर पा रहे। जहां खेती नहीं होती थी, वहां खेती हो रही है। इससे वर्षा जल का संचयन भी हो रहा है। जल टांकों से किसानों का समय की बचत हो रही है और शुद्ध पेयजल मिल पा रहा है। इससे इलाके में हरियाली और खुशहाली दोनों बढ़े हैं।

वर्ष 1997 से 2003 तक जल संरक्षण कार्य से महिला सबलीकरण हेतु महिला संगठन निर्माण किया। अशिक्षित महिलाओं को महिला शिक्षा के अनेक कैंप गाँव-गाँव आयोजित किए। अलवर जिले में 140 स्कूलों में जल यात्राएं की। अलवर जिले में कार्य करते हुए सैकडों किसानों को जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु पाइप-फव्वारे का वितरण किया। इससे किसानों ने कम जल में अधिक फसलों का उत्पादन किया। कोरोना महामारी में ग्रामीणों को स्वालंबी बनाने के लिए श्रमदान कैंप आयोजित कर जल संरक्षण का कार्य किए।

FOUNDATION
जल संवाद बैठक

बांदा की तपती धरती में उतारें पानी की शीतल बूंदें

वेद प्रकाश मौर्य
मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ)
जिला-बांदा, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का बांदा जनपद, कलिंजर किले, अनेक ऋषियों-मुनियों की भूमि के लिए पहचाना जाता है। गर्मी में यहाँ का तापमान 49 से 50 डिग्री तक पहुँचता है, ऐसे में पानी की किल्लत को समझते हुए प्रयास जारी हैं..

जनपद में पानी की किल्लत वाले इलाके चिन्हित किए, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर काम की जरूरत को देखते हुए सबसे पहले ग्राम स्तर पर वाटर और सेनिटेशन समितियां बनीं। गाँव-गाँव में जल चौपाल बनाई गई। जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पानी को बचाने के लिए खेतों की मेड-बंदी, तालाबों का जीर्णोद्धार, तालाबों की खुदाई, सॉकपिट बनवाए गए, नदियों का पुनरुद्धार, तालाबों में पानी के कैचमेंट एरिया और इनलेट के निर्माण को प्राथमिकता दी गई। इन कामों के लिए जनप्रतिनिधियों कको प्रोत्साहित किया गया। ग्राम पंचायत की जीपीडीपी में पानी बचाने के कार्यों को प्राथमिकता दी गई, मनरेगा की बजट में पानी बचाने के कार्यों को प्राथमिकता से करने के लिए सभी टीम को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी गई और उन कार्यों को चिन्हित करते हुए बरसात से पहले पूर्ण करके जल संरक्षण करने के कार्य पर बल दिया गया। बांदा की नदियों में सिल्ट सफाई का कार्य भी करते हुए उन्हें अविरल जल अभियान का रूप दिया गया। बांदा की बूंद बांदा के नाम एक विशेष अभियान चलाया गया ताकि खेत में ही खेत का पानी रहे।

भूमि संरक्षण अधिकारी को पात्र किसानों के खेतों में खेत तालाब हुए खुद कर जल संचित करते हुए सिंचाई का साधन प्रदान किया गया और उससे वे अपने सूखे खेतों में एक फसल से दो फसल तक उगने लगे, जिससे किसानों का पलायन रुका और उन्होंने अपने गाँव में ही कृषि को अपना रोजगार बना लिया। आज बांदा का जलस्तर डेढ़ से 2 मीटर बढ़ गया है और तालाब पानी से लबालब भर जाते हैं जो सिंचाई के काम आते हैं। अनेक तालाब में मत्स्य पालन हो रहा है। क्षेत्र में जल प्रहरी उमाशंकर पांडे के कार्यों को भी पहचान मिली और उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया। खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ के सिद्धांत को सभी ग्राम पंचायत में लागू किया गया और उसका परिणाम यह हुआ कि जिन खेतों में एक भी फसल नहीं होती थी उन खेतों में आज गेहूं और धान पैदा किया जा रहा है। बांदा जनपद खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं हुआ है वह विभागों को सैकड़ो कुंटल धान और गेहूं पैदा कर बेचा जा रहा है।

तिन्दवारी - बाँदा
2023-24

जल, जंगल के हर स्वरूप के प्रति समर्पण से बनी पहचान

विक्रांत तोंगड़
संस्थापक - सेफ ट्रस्ट
ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश

मात्र 20 वर्ष की आयु में ग्रेटर नोएडा में एक जल रैली निकाली, उसके बाद कई तालाब, जोहड़ को पुनर्जीवित किया। वृक्षारोपण कर पेड़ बचाए तो वहीं खंबाती कुआं प्रणाली से कई तालाबों को बचाया है।

जल संरक्षण की यात्रा : ग्रेटर नोएडा के गाँवों में जल जागरूकता से शुरू हुई। एक बुजुर्ग ने बताया कि ऊंची इमारतों में बेसमेंट की खुदाई के लिए एक दिन में पानी निकालने में गाँव के सालाना पानी के बराबर पानी खर्च होता है। इसके बाद ही उन्होने निर्माण स्थलों का निरीक्षण शुरू कर दिया। बेसमेंट की सफाई के नाम पर 100 से ज्यादा पंप प्रदूषित नालियों में ताजा भूजल बर्बाद करते देख रियल एस्टेट लॉबी से के सामने आ गए। उच्च न्यायालय और एनजीटी ने निर्माण के लिए भूजल निकालने और भूजल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। फैसला आया कि निर्माण कंपनियों को इसके बजाय उपचारित सीवेज जल (एसटीपी) का उपयोग करना था, जिससे भूजल की कमी कम हुई और सरकार को महत्त्वपूर्ण राजस्व प्राप्त हुआ।

जल निकायों के जीर्णोद्धार : नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में लगभग 10 तालाबों का जीर्णोद्धार किया है। नोएडा सेक्टर-135 में 8 एकड़ की परियोजना उत्तर प्रदेश में पहली परियोजना है, जिसमें 3 किमी पाइपलाइन से एसटीपी से उपचारित पानी मिलता है, जिसमें 3,000 देसी पौधे पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाते हैं। गाजियाबाद, खोदना, खेरी, डबरा और जैतपुर में तालाबों का जीर्णोद्धार किया, जिससे भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता को लाभ मिलता है।

वर्षा जल संचयन : छत पर वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) परियोजनाओं के लिए 2010 से काम शुरू किया और दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो स्टेशनों पर आरडब्ल्यूएच प्रणालियों को पुनर्जीवित किया गया, सुधारे गए। विभिन्न संस्थानों में औचक निरीक्षण किए। जाँचा और देखा कि सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं और सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उनके काम ने क्षेत्रीय जल प्रबंधन विधियों को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया है। गुजरात की पारंपरिक खंबाती कुआं (वर्षा जल संचयन प्रणाली) पद्धति को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जो टिकाऊ, प्रकृति-आधारित वर्षा जल संचयन पर केंद्रित है। दिल्ली एनसीआर में पांच खंबाती कुओं के लिए मंजूरी हासिल की है, जो जल संरक्षण और शहरी बाढ़ नियंत्रण में सहायता करेंगे, आधुनिक जरूरतों के लिए पारंपरिक तकनीकों को पुनर्जीवित करेंगे।

वृक्षारोपण, मियावाकी वन : देशी वृक्षारोपण किया और दिल्ली-एनसीआर में लगभग 1 लाख पेड़ लगाए। प्रमुख परियोजनाओं में 30,000 एकड़ जमीन वाला गाजियाबाद जैव विविधता पार्क शामिल है।

जल जागरूकता के लिए : जल पंचायत शुरू की जहां टीम गाँवों, आरडब्ल्यूए, स्कूलों और कॉलेजों में जाकर लोगों को जल संरक्षण के बारे में शिक्षित करती है। यह जमीनी स्तर का अभियान 5,000 से अधिक लोगों तक पहुँच चुका है, जो स्थायी प्रथाओं को मजबूत करता है। उपचारित जल के पुन: उपयोग को भी बढ़ाया दे रहे हैं। प्रमुख उपलब्धियों में सेक्टर 135 नोएडा तालाब और नोएडा गोल्फ कोर्स को जोड़ना शामिल है, जिससे लाखों लीटर भूजल की बचत हुई है। इसके अतिरिक्त, वे एनटीपीसी दादरी तक उपचारित एसटीपी जल का विस्तार करने और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक सूखे तालाब को भरने पर काम कर रहे हैं। फुटपाथ से कंक्रीट ब्लॉक्स हटवाए ताकि बारिश का पानी जमीन में रिसे, जल संचयन हो, धूल कम करने के लिए घास लगाई जा सके। अब तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 5,00,000 से ज्यादा इंटरलॉकिंग टाइल्स हटाई जा चुकी हैं। 10 हजार से ज्यादा पेड़ों के आस-पास से कंक्रीट को भी हटाया गया है, जिससे पेड़ों और भूजल को फायदा पहुँचाने के लिए खुली जगह बनाई गई है। वे भारत भर के दूसरे शहरों में पर्यावरणविदों के साथ मिलकर इस पहल का विस्तार कर रहे हैं। इन कार्यों से सीधे 10,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं।

Yamuna Ch
SAVE WATER
SAVE TREE
WATER BODY REVIVAL CAMPAIGN
Organised By
Social Action For Forest & Environment (SAFE)
Noida 108 Site

NOIDA
EFORE
BEFORE

BEFORE
AFTER
haziabad Pond
The pond in Sector 135.
other waste from the four-hectare pond, apart from fencing the area, digging silt, and level-
"We were
Tongad from SAFE.
HT NOIDA
संरक्षण की नजीर बना डाबरा गांव का तालाब

जल संचय का पेड़ लगाया और आमथला गाँव से हुई मीठे पानी की खेती

विपुल पांडया
कार्यालय समन्वयक, पाटिल फाउंडेशन
आबू, राजस्थान

एक गाँव ने रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्रयोग अपनाया तो अब कई जगह खुद ब खुद पानी का रास्ता बन रहा है...

राजस्थान राज्य में वैसे भी पानी की समस्या बनी रहती है और कुछ पहाड़ी क्षेत्र में बरसात का पानी यूं ही बह जाता है, न कहीं जमा होता है ना ही किसी को उसका उपयोग मिलता है। आबू रोड तलहाटी में कुछ गांव, जैसे दानवाव, जोधफली, मोर्थला, आमथला में जाकर वहां के स्थानीय लोगों से बात की मगर उन्होंने साफ इंकार कर दिया, उनका मानना था कि बरसों से ऐसे कुछ भी तरीके लोग लेकर आते हैं मगर कुछ नहीं होता, उन्हें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तकलीफें होती हैं वह अलग।

गांव में पहले लोग नहीं माने, लेकिन आमथला गांव के सरपंच से मुलाकात हुई और किसी तरह से वह मान गए। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का पहला प्रयास उन्हीं के घर पर किया गया, घर के छत के बाकी आउटलेट बंद करके पीवीसी पाइप के इनलेट को एक कपड़ा बांधकर और नीचे प्लास्टिक टंकी को जोड़ दिया। जो उनकी किसी बंदे ने फिटरिंग कर दी, सिर्फ पाइप के पैसे लगे।

इत्तेफाक से मई महीना था और जब जून महीने में कुछ ज्यादा नहीं पर ठीक-ठाक बरसात हुई और उनकी टंकी करीबन आधे के ऊपर भर गई तो उनका फोन आया, हमें मिले बुलाया। बहुत खुश हुए। उन्हें खर्चे का डर था वो निकल गया। आमथला गांव के लोगों को उन्होंने गुजारिश की और कई लोगों ने तो जमीन में खड्डे करके टंकी बना ली और वो पानी का उपयोग करने लगे।

उन्हीं के संदर्भ से माउंट आबू स्थित अचलगढ़ में संजय भाई के घर एक उपक्रम किया गया, जहां ऊंचाई पर पानी की काफी दिक्कत रहती है। खर्च और ज्यादा मेहनत न होने के कारण धीरे-धीरे लोगों का विश्वास बढ़ते जा रहा है और उन्हें अब खेती के लिए भी कुछ पर्यायी व्यवस्था की इच्छा जागृत हुई है। जोकि हमने आमथला गांव के बाहर एक खेत तल (चेक डेम) के उपक्रम के बारे में सरपंच और गांव वालों से बात की मगर उसमें गांव वालों की मेहनत लगने वाली थी, मगर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग से मिले हुए पानी ने उनका विश्वास बढ़ा दिया था।

आमथला गांव के बाहर जदियों से भरी एक जगह जो अंदाजन लंबाई 80' चौड़ाई 60' के करीब है, जिसे गांव वालों ने मिलकर साफ किया और 8' के करीब खड्डा बनाया। चारों तरफ से जमीन को गड्ढे की और ढलान किया गया ताकि बरसात का पानी सीधा गड्ढे में उतरे। जिसे जैसे समय मिले वैसे वहां आकर मेहनत करते थे। कुल मिलाकर 8 दिन में काम खत्म हुआ। अब प्लास्टिक ट्रैम्पोलाइन की जरूरत थी, जिसका खर्च पटेल फाउंडेशन ने उठाया और उस गड्ढे के अंदर और बाहर तक ट्रैम्पोलाइन बांध लिया ताकि बरसात का पानी उसमें जमा हो सके। आखिरकार आमथला गांव का खेत तल (चेक डेम) बनकर तैयार हो गया।

बरसात क सीजन थी तो सोने पे सुहागा हो गया था, जमीन खुदाई में भी बरसात गिरने की वजह से नरमाई थी और ट्रैम्पोलाइन फिक्स करते हुए भी हल्की बरसात आ रही थी तो जल संचय सामने नजर आ रहा था। जिससे आमथला गांव वाले बहुत खुश हुए और हमें सफलता के आशीर्वाद देने लगे।

जल स्रोतों को जीवन के लिए समर्पित मित्रगण...

विशाल अशोक सोनकुल
उपाध्यक्ष संकल्प फाउंडेशन, सामनेर
तहसील पचोरा, जलगाँव-महाराष्ट्र

अभियान की शुरुआत एक स्कूल और 150 छात्रों के साथ की थी। अब सागरमित्र अभियान पुणे में 1,70,000 छात्रों के साथ 170 स्कूलों तक विस्तारित हो गया है और 80 स्कूलों के साथ जलगाँव में 56000 छात्र इससे जुड़े हैं।

जलगाँव जिले में तापी नदी बेसिन और उसकी सहायक नदियों तथा तापी आबादी में जलगाँव सागरमित्र टीम और जेएमसी, जलगाँव द्वारा 80 स्कूलों और 56,000 छात्र चला रहे हैं ताकि तापी में प्लास्टिक प्रदूषण को रोका जा सके और नई पीढ़ी और उनके परिवार के सदस्यों में नदियों और महासागरों के प्रति जिम्मेदारी भी विकसित की जा रही है। सागरमित्र अभियान को सरकारी और निजी स्कूलों में अंग्रेजी, मराठी, हिंदी और उर्दू माध्यम के स्कूलों में दोहराया जा सकता है। अभियान सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भाषाई और आर्थिक जनसांख्यिकी में इसकी सांस्कृतिक लचीलेपन और अपील को दर्शाता है। सागरमित्र अभियान की एक खास विशेषता यह है कि बच्चों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता है। इसे 5वीं कक्षा से नीचे के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इसमें सुरक्षा का मुद्दा माना जाता है। 5वीं से 9वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए निर्देश है कि वे घर से साफ-सूखा-खाली प्लास्टिक इकट्ठा करें। घर से काम करना तथा यातायात से भरी सड़कों, सड़क के किनारों या कूड़ा-कचरा के ढेरों से प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने का जोखिम भरे काम करने वाला श्रमिक बल न बनना, जहां कुत्ते, गाय और सूअर बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं और बच्चों को कीलों या कांच के टुकड़ों से चोट लग सकती है।

सागरमित्र अभियान ने जलगाँव नगर निगम के सहयोग से कार्यक्रम के 35 सत्र आयोजित किए। जल संरक्षण कार्यों में जन सहभागिता में संत, शासन, महाजन, समाज की अवधारणा पर जलगाँव जिले के पचोरा तहसील के आसनखेड़ा गाँव में काम शुरू किए। गाँव के लिए एक परकोलेशन टैंक बनाया। विनोद बोधनकर और नरेंद्र चुघ ने महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में ऑनलाइन जिला संवाद यात्रा शुरू की। मुझे एक प्रतिभागी के रूप में सभी ऑनलाइन जिला संवाद यात्रा में शामिल होने का मौका मिला और पूरे सत्र में शामिल हुए। तापी नदी को जाने वेबिनार शृंखला आयोजित की और सभी 4 जिलों (जलगाँव, नंदुरबार, धुले और बुलढाणा जिले) की ऑनलाइन जिला संवाद यात्रा में आओ तापी नदी को जानें वेबिनार शुरू किए ताकि जल संरक्षण, नदी के प्रति सम्मान के भाव को बढ़ाया जा सके।

- ➡ सागर मित्र अभियान
- ➡ स्कूलों की संख्या 80
- ➡ छात्रों की संख्या 56,000
- ➡ प्राप्त प्लास्टिक का वजन-8 टन
- ➡ भूमि पर मुक्त बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट 1200 टन
- ➡ समुद्र पर मुक्त जल सतह 800 वर्ग किलोमीटर

पर्यावरणाची करा
पृथ्वी ची होईल सुर

ज.श.म.न.पा.

पर्यावरणाचे ठेऊया ध्यान,
तेव्हाच होईल देश महान

वर्षा जल संचयन से धरती की कोख में चीकू से गुड़ बनाने की तकनीक बताने वाले कुलपति ने भरा मीठा पानी

डॉ. जिनाभाई पी. पटेल
कुलपति, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय,
नवसारी (गुजरात)

गुजरात के कृषि विश्वविद्यालय में चीकू फसल कीट मानचित्र और कीट कैलेंडर विकसित करने के साथ ही किसानों को फसल की सुरक्षा और उच्च आय प्राप्त करने के लिए समय पर एकीकृत कीट प्रबंधन रणनीतियों के साथ जल संचयन की दिशा में भी मार्गदर्शक बने...

नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी, नवसारी में वर्षा जल संचयन इकाई के लिए आवश्यक पूरे ढांचे, छत जल संचयन संरचना (रेन वाटर हारवेस्टिंग), पानी का फिल्टर, वर्षा जल संचयन पिट (खड्डा), इत्यादि का निर्माण किया गया था। लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल (40,000 वर्ग मीटर) की भूमि से अतिरिक्त पानी को जल निकासी चैनल में मोड़ दिया जाता है।

यह जल निकासी चैनल से पानी फिल्टर इकाई से गुजरता है और परकोलेशन पिट में जाता है। परकोलेशन पिट में 10 मीटर गहराई और 5 इंच व्यास के 5 बोरवैल खोदे गए हैं, जिनसे पानी मिट्टी में रिसता रहता है। इस 40,000 वर्ग मीटर के जलग्रहण क्षेत्र से, हर साल औसतन 7 लाख लीटर पानी एकत्र और रिचार्ज किया जाता है।

नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी, नवसारी के मृदा और जल प्रबंधन इकाई की तीन इमारतें, अर्थात् स्टोर भवन, कार्यालय और उपकरण के शेड से भी पानी को एकत्रित कर नाली (गटर) के माध्यम से फिल्टर इकाई से होता हुआ बोरवैल में भेजा जाता है। इन तीनों भवनों का कुल क्षेत्रफल 815 वर्ग मीटर है और इन भवनों के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 10 लाख लीटर वर्षा जल का संचयन किया जाता है।

यूनिवर्सिटी परिसर में लगभग 40 बोरवैल हैं। वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण के कारण यूनिवर्सिटी के बोरवैल के पानी की गुणवत्ता में आसपास के क्षेत्र के अन्य बोरवैल की तुलना में सुधार हुआ है। जल संचयन के लिए, 4425 लाख लीटर क्षमता के 8 तालाबों को गहरा किया और वर्षा के बहते जल से जोड़ा। इसके कारण, विश्वविद्यालय परिसर और आसपास की जमीन का जल स्तर और गुणवत्ता में सुधार हुआ।

Bal Bharati
PUBLIC SCHOOL
Sector-21, Noida, G.B. Nagar

MANAGEMENT TEAM

Mrs Asha Prabhakar
(Principal)

Mrs Anupama Motwani
(Vice Principal)

Mrs. Amita Ganjoo
(Headmistress Sr)

Mrs Neerja Bhatnagar
(TGT Science)

Mrs Ruby Singh
(PGT Commerce)

FUTURE JAL PRAHARI'S

Nitya Panwar

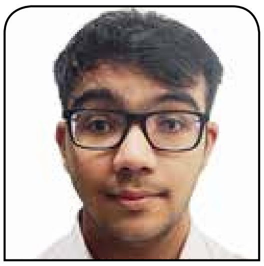
Lakshya Chitkara

Arshdeep Singh Bindra

Ashwin Anil

Harshita Goyal

Lakshya Shorawal

Moksh Bansal

Nanditha V Nambiar

Prabal Jain

Prarabdh Gautam

Renae Chawla

Prtika Sachadeva

Vishvesh Gupta

Shaifali Varun

Shaina Bhatnagar

Shivam

Vidhi Jain

Kavya Rawat

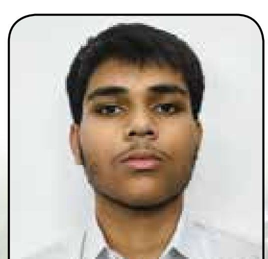
Rishit Tyagi

Ridhima

विकसित भारत के लिए संपदा निर्माण
प्रधानमंत्री आवास योजना (हाउसिंग फॉर ऑल)
स्वच्छ भारत मिशन
जल जीवन मिशन
भारत सरकार के समर्थित प्रयास
शहरी परिवहन
ऊर्जा रूपांतरण
वित्तपोषण
परामर्श
क्षमता निर्माण
हडको
hudco
एक नवरत्न सीपीएसई
हडको
hudco
A NAVRATNA CPSE
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)
(आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तहत)
CIN: L74899DL1970GOI005276 GSTIN: 07AAACH0632A1ZF वेबसाइट : www.hudco.org.in
पंजीकृत कार्यालय: हडको भवन, कोर 7ए, इंडिया हैबीटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
हमें फॉलो करें

Collaborations Rejuvenate Water Bodies Strengthen Water Security

Tata Motors is proud to have joined the National mission for rejuvenating ponds or Amrit Sarovars, assuming responsibility for creating 100 water structures in rural Maharashtra.
We, in partnership with Govt of Maharashtra and NAAM Foundation, rejuvenated and developed 106 Amrit Sarovars in water stressed regions of Pune, Palghar and Satara districts.
Partnering with Govt. of Maharashtra, Tata Motors has rejuvenated additional 356 water bodies across 10 drought prone districts of Maharashtra. We have created a water capacity of approximately 700 crore litres, thus improving water security and enhancing agricultural productivity.